3 राजधानी
150 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले चार गिरफ्तार

6 अभिमत
उपचुनाव नतीजों के संकेत

11 विदेश
ढाका विवि अनिश्चित काल के लिए बंद

12 स्पोर्ट्स
सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर बरकरार

RNI NO.UPHIN/2010/36547
वर्ष 14 अंक 265
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 जुलाई, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
लखनऊ
नगर संस्करण

लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

सबका साथ, सबका विकास की जरूरत नहीं

राष्ट्रीय-10

उपचुनाव के लिए योगी तैयार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर उपुचनाव के लिए प्रभारी बनाए गए मंत्रियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने इन मंत्रियों को उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत के लिए पूरी आक्रमकता के साथ तैयारियों में जुट जाने का पाठ पढ़ाया। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देशित किया कि जमीनी हकीकत और कार्यकर्ताओं को दुख-दर्द समझने के लिए सप्ताह में दो दिन अपने प्रभार वाले जिलों में रात्रि विश्राम करें। इसके साथ ही एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी संबंधित जिले के प्रभारी मंत्रियों के साथ एक-दो मंत्रियों को सौंपी गई है। इसके लिए मंत्रियों के 10 ग्रुप बनाए गए हैं।

सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रभारी मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों पर विस्तार से चर्चा की और वहां का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के सभी 10 ग्रुप को उपचुनाव के मद्देनजर जिले में ही रात्रि विश्राम के लिए कहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है। सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने पर होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बड़ी हार के बाद सरकार हो या संगठन सभी फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं। सभी के सामने 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती है। चाहे जातीय समीकरण की बात हो या प्रत्याशियों के चयन की। योगी नहीं चाहते हैं कि किसी भी मसले को हल्के में लिया जाए। बैठक में जहां योगी तेवर में नजर आए वहीं मंत्रियों में भी ऊर्जा भरने का काम किया। उन्होंने मंत्रियों के सामने अपनी रणनीति स्पष्ट की। उनका फोकस तीन बातों पर था पहला कि कार्यकर्ताओं को मनाएं उन्हें सम्मान दें और उनकी राय पर गौर करें। दूसरा डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को आम जनता के बीच ले जाएं और विपक्ष द्वारा फैलाए गए आरक्षण आदि के भ्रम को दूर करें।

योगी ने मंत्रियों से कहा कि कार्यकर्ताओं से न सिर्फ संवाद करें बल्कि उनकी नाराज़गी को भी दूर करें। बूथों पर स्थिति मजबूत करें। विकास योजनाओं, रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में युवाओं और आमजनता को जागरूक करें। उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करें और विपक्ष के झूठ को बेनकाब करें। मुजफ्फरनगर की मीरापुर, संभल की कुंदरकी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर (सुरक्षित), मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फुलपुर, अयोध्या की मिल्लीपुर, अंबेडकरनगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मझवां विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। इन सीटों के नौ विधायक अब सांसद बन गए हैं। इन दस सीटों में भाजपा गठबंधन के पास पांच और पांच पर सपा के विधायक थे। मुख्यमंत्री ने हर मंत्री को जमीन पर उतरने और पार्टी का पक्ष मजबूत करने की हिदायत दी। (शेष पेज 9)

भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फाइल फोटो

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिले प्रधानमंत्री से

नई दिल्ली (भाषा)। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने के कारण चल रहे मंथन एवं समीक्षाओं के दौर तथा संगठन एवं सरकार में बड़ा कौन मुद्दा गर्माने के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। माना जा रहा है कि इस दौरान चौधरी ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस राज्य में पार्टी के संगठनात्मक मामलों से संबंधित कई मुद्दों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले कम सीटें पाने के बाद भाजपा के भीतर अलग-अलग आवाजें उठ रही हैं। इन सबके बीच चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा से अलग-अलग मुलाकात की थी।

नई दिल्ली के पंडारा मार्केट में आग लगने से खाक हुआ गुलाटी रेस्टोरेंट। फोटो : रंजन डिमरी

दिल्ली का प्रसिद्ध गुलाटी रेस्टोरेंट जलकर खाक

सौम्या शुक्ला। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में स्थित प्रसिद्ध गुलाटी रेस्टोरेंट में बुधवार की सुबह लगी आग ने 1959 से चली आ रही उस ऐतिहासिक विरासत को खाक कर दिया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने लजीज व्यंजनों का कभी लुत्फ उठाया था। रेस्टोरेंट में आग लगने की खबर ने कई दिल्लीवासियों का दिल भर आया जिन्होंने यहां कभी भोजन किया था। उन्हें रेस्टोरेंट में बिताए समय की याद दिला दी है, जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बसा है। इस रेस्टोरेंट की शुरुआत एक छोटे से ढाबे से हुई थी, जिसमें साधारण लकड़ी की बेंच और टेबल थीं, जिसे 2013 में एक बढ़िया रेस्टोरेंट में तब्दील किया गया था। हालांकि, यहां बढ़िया भोजन के साथ यह जगह अपने बेहतर माहौल के लिए प्रसिद्ध थी। शाकाहारी गुलाटी रेस्टोरेंट के बैठने की जगह में तड़के 2.48 बजे लगी आग मुख्य रेस्टोरेंट के पास स्थित है जो जल्द ही पहली मंजिल तक फैल गई और सबकुछ राख हो गया।

पायनियर से बात करते हुए, कई लोग इस खबर से दुखी हो गए और याद करके भावुक हो गए कि यह जगह उनके कई पारिवारिक समारोहों का हिस्सा थी। प्रसार भारती में कंटेंट राइटर के रूप में काम करने वाले 26 वर्षीय आदित्य आहूजा ने बताया कि कैसे वह अपने पिता के साथ बचपन में इस जगह पर आया करते थे। दिल्ली अग्निशमन दल के एक अधिकारी के अनुसार, चार दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के काम पर लगाया गया और एक घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी जिससे कुछ फर्नीचर और अन्य सामान को जल गया। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है। यह रेस्तरां शहर के सबसे अच्छे उत्तर भारतीय रेस्तरां में से एक के रूप में उभरा है और इस जगह के बाहर (शेष पेज 9)

अजीत पवार गुट के चार बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी

टीएन रघुनाथ। मुंबई

हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पिंपरी चिंचवाड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित गवाहाने समेत चार शीर्ष नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस सप्ताह के अंत वे सभी नेता शरद पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। गवाहाने के अलावा, सत्तारूढ़ एनसीपी (एपी) छोड़ने वाले और प्रतिद्वंद्वी शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल होने की घोषणा करने वाले तीन अन्य नेता हैं एनसीपी के पिंपरी-चिंचवाड़ छात्र विंग के प्रमुख यश साने, पूर्व पार्षद राहुल भोसले और पंकज भालेकर। गवाहाने, राहुल और पंकज ने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। साने ने इस सप्ताह की शुरुआत में एनसीपी छात्र विंग के अध्यक्ष प्रशांत कदम को अपना इस्तीफा भेज दिया था।

एनसीपी (एपी) के चार नेताओं के इस्तीफे के एक साल बाद अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ बगावत की, जिससे मूल पार्टी में नाटकीय विभाजन हुआ और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी से अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए, गावहाने ने कहा उन्होंने एनसीपी छोड़ दी है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य पार्टी अध्यक्ष सुनील तटकरे को सौंप दिया है। वह किस पार्टी में जा रहे हैं, यह बताने से इनकार करते हुए, गावहाने ने कहा समय आने पर पता चल जाएगा कि वह किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज कुछ भी नहीं बोलंगे। हालांकि, उनके करीबी सहयोगियों ने पुष्टि की कि वह और अन्य (शेष पेज 9)

विवाद के बाद पीछे हटी कर्नाटक सरकार

● सिद्धरमैया सरकार ने निजी कंपनियों में कन्नड़ भाषियों के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक को ठंडे बस्ते में डाला

भाषा। बेंगलुरु

कारोबार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लोगों की तीखी आलोचना के बाद कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया जिसमें निजी क्षेत्र में कन्नड़ भाषियों के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया था। कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक, 2024 को सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस विधेयक को बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना थी।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया, निजी क्षेत्र के संस्थानों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ भाषियों को आरक्षण देने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत विधेयक को अस्थाई रूप से रोक दिया गया है। इस पर आगामी दिनों में फिर से विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी एक्स पर पोस्ट किया था, निजी क्षेत्र के संस्थानों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ भाषी लोगों के लिए आरक्षण लागू करने का विधेयक अभी तैयारी के चरण में है। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में व्यापक चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

पार्टी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

विधेयक में कहा गया, किसी भी उद्योग, कारखाने या अन्य प्रतिष्ठानों को प्रबंधन श्रेणियों में 50 प्रतिशत और गैर-प्रबंधन श्रेणियों में 70 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति करनी होगी। कारोबार क्षेत्र की हस्तियों ने प्रस्तावित कोटे पर आपत्ति जताते हुए इसे फासीवादी और अदूरदर्शी बताया। जानेमाने उद्यमी एवं इंफोसिस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी टी.वी. मोहनदास पई ने विधेयक को फासीवादी करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, इस विधेयक को रद्द कर देना चाहिए। यह पक्षपातपूर्ण, प्रतिगामी और संविधान के विरुद्ध है। अविश्वसनीय है कि कांग्रेस इस तरह का विधेयक लेकर आई है-एक सरकारी अधिकारी निजी क्षेत्र की भर्ती समितियों में बैठेगा? लोगों को भाषा की परीक्षा देनी होगी...? फार्मा कंपनी बायोकॉन की प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ ने कहा, एक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है और हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना है। हमें इस कदम से प्रौद्योगिकी में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए...। एसोचैम की कर्नाटक इकाई के सह अध्यक्ष आर.के. मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट में तंज कसते हुए कहा, कर्नाटक सरकार का एक और प्रतिभावान कदम। स्थानीय स्तर पर आरक्षण और हर कंपनी की निगरानी के लिए सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाना। इससे भारतीय आईटी और जीसीसी भयभीत होंगे। अदूरदर्शी। कर्नाटक का यह कदम हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक जैसा ही है, जिसमें राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया गया था। हालांकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2023 को हरियाणा सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था।

विदेशी आतंकी दबोचने को डोडा के जंगलों में सघन तलाशी

डोडा में आतंकवादियों से हालिया मुठभेड़ के बाद भारी सुरक्षा के साथ सैन्यकर्मी।

मोहित कंडारी। जम्मू

जम्मू-कश्मीर में छिपे विदेशी आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने डोडा के देसा वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया है। इसी क्षेत्र में सोमवार देर रात भीषण गोलीबारी में एक कैप्टन समेत चार सैन्यकर्मी शहीद होने के बाद पहाड़ी इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। जानकारी के अनुसार सैन्यकर्मियों को निशाना बनाने के बाद आतंकवादी इलाके से भाग गए थे। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, जब संयुक्त टीमें इलाके में तलाशी ले रही थीं, तो मंगलवार देर रात तीन से चार घंटे के अंतराल में दो मौकों पर संक्षिप्त गोलीबारी हुई।

सतर्क ग्राम रक्षा गार्ड (वीडीजी) ने कथित तौर पर अपने गांव के बाहर संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए गोलीबारी की, जबकि गंडोह क्षेत्र से दो विस्फोटक गोले बरामद किए गए। देसा वन क्षेत्र में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सबसे पहले मंगलवार रात 10.45 बजे कलां भाटा में और फिर सुबह 2 बजे पंचन भाटा के पास गोलीबारी की सूचना मिली। चुनौतीपूर्ण भूभाग और मौसम की स्थिति के बावजूद, प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से जुड़े आतंकवादियों को पकड़ने और उन्हें बेअसर करने के प्रयास जारी हैं। इस बीच, डोडा जिले के गंडोह के सिनू वन क्षेत्र में एक अलग तलाशी अभियान के दौरान दो विस्फोटक गोले बरामद किए गए। 26 जून को सिनू वन में एक दिन तक चली मुठभेड़ में तीन विदेशी आतंकवादी मारे गए और अमेरिका निर्मित एम4 कार्बाइन सहित हथियारों और (शेष पेज 9)

भगदड़ जैसे हालात

मुंबई हवाईअड्डे के पास उस समय भगदड़ जैसे हालात बन गए जब वहां लोडर पद की नौकरी के लिए हजारों की संख्या में उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने बुधवार को दावा किया कि उसने पर्याप्त तैयारी की थी ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो।

हरियाणा में अग्निवीरों को नौकरी में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

शिखा शर्मा। चंडीगढ़

विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए अग्निवीरों को चार विभागों में दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने तथा प्राथमिकता के आधार पर आर्म्स लाइसेंस जारी करने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल गया है। हरियाणा में कांग्रेस लगातार सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को समाप्त करने का ऐलान कर रही है।

चंडीगढ़ में बुधवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान करते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, फोरेस्ट व माइनिंग गार्ड, जेल वार्डन व एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) की भर्ती में सेना से चार वर्ष बाद लौटने वाले अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सीधी भर्ती में अग्निवीरों को यह सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए तय उम्र सीमा में भी अग्निवीरों को छूट मिलेगी। अग्निवीरों के पहले (शेष पेज 9)

अग्निवीरों को नौकरी देने पर मिलेगी सब्सिडी

मुख्यमंत्री सैनी ने साफ किया कि अगर कोई उद्योगपति अग्निवीरों को सेना से वापस आने पर 30 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पर नौकरी देता है तो ऐसे उद्योगपतियों को सरकार की ओर से सालाना 60 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए विस्तृत योजना का ड्राफ्ट तैयार करके जारी किया जाएगा। अग्निवीरों को सेना से (शेष पेज 9)

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उन याचिकाओं पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिनमें आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी किए जाने को चुनौती दी गई है और अंतरिम जमानत का अनुरोध किया गया है। केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने न केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से की गई गिरफ्तारी की आलोचना की बल्कि उन्हें मामले में जमानत पर रिहा करने का भी अनुरोध किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मुहरर्म का अवकाश होने के बावजूद सुनवाई की। उन्होंने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनीं और याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। उच्च न्यायालय ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 29 जुलाई तय की है। आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल का पक्ष ले रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी, यह दुर्भाग्य से रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी है। मेरे पास (ईडी के मामलों में) बहुत ही सख्त प्रावधानों में प्रभावी रिहाई के तीन आदेश हैं...ये आदेश दिखाते हैं कि (शेष पेज 9)

विधि मंत्रालय ने अहम बिलों के लिए सनसेट क्लॉज की वकालत की

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कानूनी अव्यवस्था को किताब से हटाने के लिए कुछ प्रकार के विधेयकों में 'सनसेट' क्लॉज या स्वत: निरस्तीकरण प्रावधान को शामिल करने की वकालत की है और इसे अपने 100-दिवसीय एजेंडे में शामिल किया है। सनसेट क्लॉज मुख्य रूप से अस्थायी प्रकृति के कानूनों या गतिशील स्थितियों से निपटने वाले कानूनों पर लागू होता है। एक बार जब उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, तो वे कानून की किताबों से हटा दिए जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में 20 से अधिक वर्षों से सनसेट क्लॉज का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। मंत्रालय के विधायी विभाग ने नए विधायी प्रस्ताव में 'सनसेट क्लॉज' को अपने 100-दिवसीय एजेंडे का हिस्सा बनाते हुए कहा है कि संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से इस संबंध में कदम उठाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अगली सरकार के लिए 100-दिवसीय एजेंडा तैयार करने का निर्देश दिया था।

पूर्व केंद्रीय विधि सचिव पीके मल्होत्रा ने बताया कि जब भी विधायिका, संसद या राज्य विधानमंडल अपने द्वारा पारित किसी कानून का समय अवधि सीमित करना चाहती है, तो वह नीतिगत तौर पर

एक सनसेट क्लॉज प्रदान कर सकती है, जिसमें यह प्रावधान हो कि एक निश्चित अवधि - आवश्यकता के आधार पर पांच या 10 वर्ष - बीत जाने के बाद कानून समाप्त हो जाएगा। मल्होत्रा ने कहा कि विधानमंडल सनसेट क्लॉज के कारण निष्क्रिय हो चुके कानून को नया जीवन देने के लिए एक नया कानून पारित कर सकता है। विधायी विभाग के अनुसार, वह संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से नए विधायी प्रस्ताव में सनसेट क्लॉज या स्वत: निरस्तीकरण क्लॉज को शामिल करना चाहता है। उसने कहा कि जब भी इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होंगे, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह लंबे समय से लंबित मांग है। यह प्रथा कुछ अन्य देशों में भी प्रचलित है। मल्होत्रा ??ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसे कई कानून हैं जहां इस तरह का प्रस्ताव रखा जा सकता है ताकि संसद या राज्य विधानमंडल भी सतर्क रहें कि समय बीतने के साथ, अगर किसी कानून को जारी रखने की आवश्यकता है, तो वे इसे नए सिरे से देखेंगे। अगर वे जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो कानून में दिए गए दिन से यह अपने आप समाप्त हो जाएगा। हाल के दिनों में, कानूनी सुधारों को देखने के लिए गठित कुछ आयोगों ने भी इस तरह के प्रस्ताव पर जोर दिया है। सनसेट क्लॉज एक कानूनी स्थिति है जो किसी कानून या समझौते को समाप्त करने के लिए समाप्ति तिथि या शर्तें स्थापित करता है। यह रेखांकित करता है कि कानून या समझौता एक निश्चित समय के बाद वैध नहीं रहेगा, जब तक कि इसे नवीनीकृत न किया जाए। अनुबंधों में, सनसेट क्लॉज समाप्ति की अनुमति देता है यदि कोई विशेष घटना एक निर्धारित तिथि तक नहीं होती है। यह खंड एक विशिष्ट तिथि पर पहुंचने के बाद विधायी खंडों को स्वचालित रूप से हटा देता है। इसके लिए कुछ प्रावधानों या कानूनों को तब तक काम करना बंद करना पड़ता है (शेष पेज 9)

अगले 72 घंटे में पूरा कराएं कांवड़ यात्रा मार्गों की मरम्मत का शेष कामः मुख्यमंत्री

● सीएम योगी ने की कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जुलाई से प्रारंभ हो रही पावन कांवड़ यात्रा की तैयारियों की बुधवार को समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जलशक्ति, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री तथा पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री एवं राज्य मन्त्रिगणों की उपस्थिति भी रही।

पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और नगर विकास विभाग को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि कावंड़ यात्रा से संबंधित हर जिले की हर सड़क की मरम्मत का शेष काम अगले 72 घंटे में पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे कांवड़ यात्रा रूट की साफ- सफाई कराई जाए। यह क्रम पूरे माह जारी रहना चाहिए। कहीं भी गंदगी अथवा जलभराव नहीं होनी चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, साथ ही पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर अच्छी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएं, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था भी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए यह उचित होगा कि यात्रा मार्ग पर आमजन के सहायतार्थ शिविर लगाएं। यहां शीतल पेय जल, शिकंजी वितरण आदि का भी प्रबंध हो। शिविर लगाने में सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाना चाहिए, यद्यपि शिविर संचालकों का सत्यापन जरूर करा लें। यात्रा मार्ग की ड्रोन से निगरानी कराई जाए और प्रमुख अवसरों पर पुष्पवर्षा भी कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ियों द्वारा तय मानकों के साथ डीजे बजाया जाना चाहिए, लेकिन डीजे की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, काशी, बाराबंकी आदि के नगरीय क्षेत्रों में आस्था के केंद्र शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा मंदिर प्रबंधन से संपर्क-संवाद कर शिवालयों में भीड़ प्रबंधन कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगनहर में मृत जानवरों के प्रवाह की सूचना मिली है, इसे तत्काल रोका जाए।

कयासबाजी के बीच राज्यपाल से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के अंदर चल रही बयानबाजी और अटकलों के बीच बुधवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सीएम योगी राज्यपाल से आगामी मानसून सत्र को लेकर चर्चा करने पहुंचे हैं। सरकार 29 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुला सकती है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने की तैयारी है। हालांकि राजभवन ने भेंट को शिष्टाचार करार दिया है। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित छह स्वर्णिम पृष्ठ पुस्तक भेंट की। बता दें कि कार्यसमिति की बैठक के बाद भाजपा में कयासबाजी और अटकलों का दौर शुरू हुआ है। इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया तो कई अटकलें लगाई जा रही थी। इसी बीच केशव भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर अटकलें चल रही थी कि केशव को संगठन में जगह दी जा रही है। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। यह मुलाकात कई तरह की चर्चा को जन्म दे गई। इस बीच भूपेंद्र चौधरी ने आज पीएम मोदी से भी मुलाकात की है।

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Piramal
Capital & Housing Finance

पंजीकृत कार्यालय पताः यूनिट नं. 601, 6वीं मंजिल पीरामल अमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई–400070
सीआईएनः L65910MH1984PLC032639, वेबसाइट : www.piramalfinance.com
शाखा का पताः धीरज बाग, बिल्डिंग "ए" भूतल और प्रथम तल, एक्सिस बैंक के साथ में, मोनालिसा बिल्डिंग के समाने, आगरा रोड, हरि निवास सर्कल, नौपाड़ा, ठाणे (पश्चिम)–400602

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित। अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के प्रवर्तन के तहत पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीसीएचएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी कर आह्वान किया है निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता") को जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए नीचे दिया गया है। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर पीसीएफएल को भुगतान करने का नोटिस दिया जाता है। नीचे दी गई तारीखों से भुगतान और/या वसूली की तारीख तक, अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय, उक्त मांग नोटिस में बताए गए अतिरिक्त ब्याज के साथ, नीचे दर्शाई गई राशियाँ, यदि कोई हो, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ता द्वारा पीसीएफएल को गिरवी रखा गया है।

उधारकर्ता/गारंटर्स का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि साथ में एन पी ए की तिथि	सम्पत्ति का पता
(लखनऊ शाखा का एलसी सं. 06000000610) सुरेन्द्र सिंह (उधारकर्ता)	25-06-2024/रु. 8,36,545/- (रु. आठ लाख छत्तीस हजार पांच सौ पैंतालीस मात्र) एनपीए (08-01-2021)	फ्लैट नं. 9/11, प्रथम तल, ब्लॉक नं. बी, आश्रय-2 सेक्टर 6, सुलभ आवास, गोमती नगर एक्सटेंशन लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226010
(लखनऊ शाखा का एलसी सं. 0600000929) मनोज कुमार (उधारकर्ता) अंजलि कनौजिया (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 8,86,251/-(रु. आठ लाख छियासी हजार दो सौ इक्यावन मात्र) एनपीए (09-06-2024)	फ्लैट नं. 202, प्रथम तल, मां शांझी छत अपार्टमेंट, प्रा. नं. 128/39 ए ब्लॉक-के, किदवई नगर कानपुर कानपुर शहरी उत्तर प्रदेश - 208001
(नई दिल्ली-पश्चिम शाखा का एलसी सं. 09600000928) रोहित खन्ना (उधारकर्ता) रुचि खन्ना (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 58,47,848/- (रु. अट्ठावन लाख सैंतालीस हजार आठ सौ अड़तालीस मात्र) एनपीए (10-05-2024)	फ्लैट नं.- एफएफ-2, प्रथम तल पीछे की तरफ, प्लॉट नं.- 929, नीति खंड-1 इंदिरापुरम गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश - 201014
(लखनऊ शाखा का एलसी सं. 06000002243) राम प्रसाद (उधारकर्ता) सीमा रानी (सह-उधारकर्ता 1) सोहन लाल (सह-उधारकर्ता 2)	25-06-2024 /रु. 49,008.04 (रु. उनचास हजार आठ और पैसे चार मात्र) एनपीए (09-06-2024)	खसरा नं. 190 वार्ड- इब्राहिमपुर निलमथा लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश - 226020
(लखनऊ शाखा का एलसी सं. 06000006411) राम प्रसाद (उधारकर्ता) सोहन लाल (सह-उधारकर्ता 1) सीमा रानी (सह-उधारकर्ता 2)	25-06-2024/रु. 2,53,741/- (रु. दो लाख तिरेप्पन हजार सात सौ इकतालीस मात्र) एनपीए (09-06-2024)	खसरा नं. 190 पर प्लॉट, वार्ड- इब्राहिमपुर निलमथा लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश -226020
(लखनऊ शाखा का एलसी सं. 06000003106 शाखा) संजय मिश्रा (उधारकर्ता) हर्षिता मिश्रा (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 12,21,140/-(रु. बारह लाख इक्कीस हजार एक सौ चालीस मात्र) एनपीए (09-06-2024)	नगर महापालिका के हिस्से पर मकान प्लॉट नं. 09 का भाग, पुलिस लाइन, खैराबाद सीतापुर उत्तर प्रदेश - 261001
(आगरा शाखा का एलसी नं. 23400000878) दीपक कुमार (उधारकर्ता) कल्पना भारती (सह-उधारकर्ता 1) महीपत सिंह (सह-उधारकर्ता 2)	25-06-2024/रु. 15,82,558/-(रु. पंद्रह लाख ब्यासी हजार पांच सौ अट्ठावन मात्र) एनपीए (09-06-2024)	प्लॉट नं. 14, खसरा नं. 1 मोहल्ला त्रिलोकी रक्षा विहार कॉलोनी फेस । मौजा नगला काली आगरा आगरा उत्तर प्रदेश - 282001
(लखनऊ - लालबाग शाखा का एलसी नं. 19300041606) शमशाद अहमद (उधारकर्ता) शाहिना अंसारी (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 22,84,424/-(रु. बाईस लाख चौरासी हजार चार सौ चौबीस मात्र) एनपीए (09-04-2024)	प्लॉट नं. 3 4 5 6 7 प्लॉट नं. 8 का भाग, खसरा नं. 756 एवं 759 मिन ग्राम नरौना परगना काकोरी तह एवं जिला लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश - 226020
(आगरा शाखा का एलसी सं. 23400001365) चंद्र बहादुर (उधारकर्ता) लक्ष्मी देवी (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 5,17,887/- (रु. पाँच लाख सत्रह हजार आठ सौ सत्तासी मात्र) एनपीए (09-06-2024)	खेत नं. 1503 एवं 1504 का हिस्सा, पीडीएस पब्लिक इंटर कॉलेज चंदनिया अलीगढ अलीगढ अलीगढ उत्तर प्रदेश - 202001
(वाराणसी शाखा का एलसी सं. 12000002769) पुष्पा देवी (उधारकर्ता) अवध बिहारी (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 6,69,894/- (रु. छह लाख उनहत्तर हजार आठ सौ चौरानबे मात्र) एनपीए (10-05-2024)	आराजी नं. 433 मौजा हिनौली परगना मवई तह. मुगलसराय चंदौली चंदौली उत्तर प्रदेश - 232104
(लखनऊ शाखा का एलसी सं. 06000005265) महेंद्र कुमार दीक्षित (उधारकर्ता) सुशील कुमार दीक्षित (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 3,17,248/- (रु. तीन लाख सत्रह हजार दो सौ अड़तालीस मात्र) एनपीए (09-06-2024)	प्लॉट नं. बी 362 बी/1 खसरा नं. 73 ग्राम लौलाई परगना तह माधव ग्रीन्स लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश - 226020
(गोरखपुर शाखा का एलसी सं. 25700001081) कमलकांत मौर्य (उधारकर्ता) शशिकला मौर्य (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 10,45,321/- (रु. दस लाख पैंतालीस हजार तीन सौ इक्कीस मात्र) एनपीए (10-05-2024)	प्लॉट गाटा सं. 1184 का भाग, मोहल्ला- गौहाना, परगना एवं तहसील-अकबरपुर अंबेडकर नगर अंबेडकरनगर उत्तर प्रदेश - 224190
(इलाहाबाद शाखा का एलसी सं. 29400000121) सोनू केसरवानी (उधारकर्ता) जया केशरवानी (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 15,94,707/- (रु. पंद्रह लाख चौरान्वे हजार सात सौ सात मात्र) एनपीए (09-06-2024)	मकान नं. ईडब्ल्यू एस 51, मौजा- कसारी मसारी आवास योजना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश- 211011
(इलाहाबाद शाखा का एलसी नं. 29400000210) सोनू केसरवानी (उधारकर्ता) जया केशरवानी (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 3,10,567 /-(रु. तीन लाख दस हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) एनपीए (09-06-2024)	मकान नं. ई डब्ल्यू एस 51, मौज़ा- कसारी मसारी आवास योजना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश- 211011
(गोरखपुर शाखा का एलसी नं. 25700001501) हरवंस प्रसाद (उधारकर्ता) सुनयना देवी (सह-उधारकर्ता 1) सचिन कुमार (सह-उधारकर्ता 2)	25-06-2024 /रु. 11,05,631.62 (रु. ग्यारह लाख पांच हजार छह सौ इकतीस और पैसे बासठ मात्र) एनपीए (10-05-2024)	गाटा सं. 1 Chha के भाग पर प्लॉट, मौजा- तारापुर रजौली, वार्ड- रेतिया (ए.एन.पी.), परगना- हवेली अवध फैजाबाद फैजाबाद उत्तर प्रदेश- 224001
(बरेली शाखा का एलसी नं. 29100000187) मोहम्मद जाहिद रजा खान (उधारकर्ता) अमना बेगम (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 15,63,745/- (रु. पंद्रह लाख तिरेसठ हजार सात सौ पैंतालीस मात्र) एनपीए (10-05-2024)	ख-नं-255 के भाग पर मकान, रेहपुरा चौधरी बरेली बरेली उत्तर प्रदेश - 243001
(गाजियाबाद शाखा का एलसी नं. 07700002068) देव कुमार तनेजा (उधारकर्ता) रीना तनेजा (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 13,91,819/- (रु. तेरह लाख इक्यान्वे हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) एनपीए (09-06-2024)	प्लॉट नं. बी-1, पहली मंजिल पीछे एलएचएस, खसरा नं. 117 और 118 गांव रईसपुर परग दाना गाज गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश- 201001
(वाराणसी शाखा का एलसी नं. 12000004993) गोपी कुमार झा (उधारकर्ता) मैथिली झा (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 10,53,033.6 (रु. दस लाख तिरेप्पन हजार तैंतीस और पैसे साठ मात्र) एनपीए (09-06-2024)	आराजी नं. 317 मौजा-पहाड़ी परगना-देहात अमानत वाराणसी वाराणसी उत्तर प्रदेश- 221108
(राज नगर शाखा का एलसी नं. 19000002133) दीपक शर्मा (उधारकर्ता) निशा शर्मा (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 12,64,851/-(रु. बारह लाख चौसठ हजार आठ सौ इक्यावन मात्र) एनपीए (09-06-2024)	डी-410 प्लॉट नं. 78 और 79, खसरा नं. 57 आदित्य अपार्टमेंट यूनियन रेजीडेंसी, अकबरपुर बहरामपुर गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश- 201001
(कानपुर शाखा का एलसी नं. 24000003953) मुकेश राठौर (उधारकर्ता) लक्ष्मी देवी राठौर (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 1,29,636/-(रु. एक लाख उनतीस हजार छह सौ छत्तीस मात्र) एनपीए (09-06-2024)	प्लॉट नं. 12/290, आराजी नं. 230, नगर पालिका, परिसद गंगाघाट, कानपुर, उन्नाव उत्तर प्रदेश- 209801
(लखनऊ का एलसी नं. 19300045075 - लालबाग शाखा) धारा सिन्हा (उधारकर्ता) राजा उपाध्याय (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 7,46,970/- (रु. सात लाख छियालीस हजार नौ सौ सत्तर मात्र) एनपीए (09-06-2024)	प्लॉट नं. ए-3, प्लॉट नं. 20 और 21 का हिस्सा, खसरा नं. 164 मिंज गांव लौलाई परगना और तहसील लखनऊ, लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226010
(लखनऊ - लालबाग शाखा का एलसी नं. 193LUK00824) नसीम अहमद सिद्दीकी (उधारकर्ता) शाजिया सिद्दीकुल (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 16,18,641/-(रु. सोलह लाख अठारह हजार छह सौ इकतालीस मात्र) एनपीए (09-07-2015)	प्लॉट नं. 79, कल्याणपुर, लखनऊ, यू.पी.-226024
(लखनऊ - लालबाग शाखा का एलसी नं. 19300041409) मनीष कुमार मिश्रा (उधारकर्ता) सुचि मिश्रा (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 17,18,348/- (रु. सत्रह लाख अठारह हजार तीन सौ अड़तालीस मात्र) एनपीए (09-06-2024)	प्लॉट सं. प्लॉट नं. 15 और प्लॉट सं. 16 का हिस्सा, निर्मल होम्स, सेक्टर तकरोही, वार्ड- शहीद भगत सिंह एच, इंदिरा नगर लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226016
(लखनऊ - लालबाग शाखा का एलसी नं. 193LUK32113) मनीष कुमार मिश्रा (उधारकर्ता) सुचि मिश्रा (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 15,59,980/- (रु. पंद्रह लाख उनसठ हजार नौ सौ अस्सी मात्र) एनपीए (09-06-2024)	प्लॉट सं. प्लॉट नं. 15 और प्लॉट सं. 16 का हिस्सा, निर्मल होम्स, सेक्टर तकरोही, वार्ड- शहीद भगत सिंह एच, इंदिरा नगर लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226016
(हरिद्वार शाखा का एलसी नं. M0204239) सूरज कुमार (उधारकर्ता) अलका (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 13,11,527.02 (रु. तेरह लाख ग्यारह हजार पांच सौ सत्ताईस और पैसे दो मात्र) एनपीए (04-01-2024)	प्लॉट नं. 61, खसरा नं. 1617, ग्राम महादेव ग्रीन, आनेकी हातेमपुर महादेव ग्रीन खसरा नंबर 1617, परगना ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश-249403
(हरिद्वार शाखा का एलसी नं. M0204239TU) सूरज कुमार (उधारकर्ता) अलका (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 98,926/-(रु. अट्ठानबे हजार नौ सौ छब्बीस मात्र) एनपीए (04-01-2024)	प्लॉट नं. 61, खसरा नं. 1617, ग्राम महादेव ग्रीन, आनेकी हातेमपुर महादेव ग्रीन खसरा नंबर 1617, परगना ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश-249403
(मेरठ शाखा का एल सी नं. M0193762) अमित कुमार (उधारकर्ता) आशा रानी (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 7,72,311/- (रु. सात लाख बहत्तर हजार तीन सौ ग्यारह मात्र) एनपीए (04-06-2024)	प्लॉट नं. 54, दौराला तहसील, सरधना 1326, कस्बा दौराला, टोल प्लाजा, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250221
(हल्द्वानी शाखा का एल.सी. नं. M0202523) संजीव गुप्ता (उधारकर्ता) पूजा गुप्ता (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 18,06,619.9 (रु. अट्ठारह लाख छह हजार छह सौ उन्नीस पैसे नब्बे मात्र) एनपीए (04-06-2024)	खसरा नं. 155 मि, खाता खतौनी नं. 00040 (1425-1430), गांव फुलसुंगा, तीन पानी बांध रोड, तहसील रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश-263153
(हल्द्वानी शाखा का एल.सी. सं. M0202523TU) संजीव गुप्ता (उधारकर्ता) पूजा गुप्ता (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 5,50,569/- (रु. पांच लाख पचास हजार पांच सौ उनसठ मात्र) एनपीए (04-06-2024)	खसरा नं. 155 मि, खाता खतौनी नं. 00040 (1425-1430), गांव फुलसुंगा, तीन पानी बांध रोड, तहसील रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश-263153
(दिल्ली - पीतमपुरा शाखा का एलसी नंबर M0198336) देव तिवारी (उधारकर्ता) अंशु तिवारी (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 21,29,373.81 (रु. इक्कीस लाख उनतीस हजार तीन सौ तिहत्तर और पैसे इक्यासी मात्र) एनपीए (04-06-2024)	खाता नं. 00097, खसरा नं. 158, पुरानी आबादी, गांव-मामूरा परगना और तहसील दादरी जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301
(दिल्ली - पीतमपुरा शाखा का एलसी नं. M0198336TU) देव तिवारी (उधारकर्ता) अंशु तिवारी (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 6,88,473/- (रु. छह लाख अट्ठासी हजार चार सौ तिहत्तर मात्र) एनपीए (04-06-2024)	खाता नं. 00097, खसरा नं. 158, पुरानी आबादी, गांव-मामूरा परगना और तहसील दादरी जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301
(अलीगढ़ शाखा का एलसी नं. M0206741) सलमान खान (उधारकर्ता) रजिया (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 5,42,243/- (रु. पांच लाख बयालीस हजार दो सौ तैंतालीस मात्र) एनपीए (04-06-2024)	खेत नं. 353, नगला, पुलिस चौकी के पास, पटवारी, अलीगढ, उत्तर प्रदेश-202001
(वाराणसी शाखा का एलसी नं. HLSA0000335F) प्रतिमा देवी (उधारकर्ता) प्रमोद (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 8,12,437.82 (रु. आठ लाख बारह हजार चार सौ सैंतीस और ब्यासी मात्र) एनपीए (04-06-2024)	प्लॉट नं. 45/1 चंदौली, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के पास मुगलसराय, चंदौली उत्तर प्रदेश
(आगरा शाखा का एलसी नं. M0232655) वीना (उधारकर्ता) कैलाशी प्रसाद (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 9,42,164/-(रु. नौ लाख बयालीस हजार एक सौ चौसठ मात्र) एनपीए (04-06-2024)	प्लॉट नं. 81 82, खसरा नं. 75 का हिस्सा, भोलेभावा धाम कॉलोनी, शमशाबाद रोड, आगरा, खसरा नं. 75 का हिस्सा, मौजा बगदा तह और जिला-आगरा, भोलेबाबा डेयरी के पास, उत्तर प्रदेश-283125
(बुलंदशहर शाखा का एलसी नं. HLSA00006857) अख्तर अली (उधारकर्ता) मोहम्मद मुबीन (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 8,80,145.38 (रु. आठ लाख अस्सी हजार एक सौ पैंतालीस और पैसे अड़तीस मात्र) एनपीए (04-06-2024)	भूमि नं. 1352मि और 1353 का हिस्सा, बुलंद शहर, खुर्जा बहार चुंगी, ईदगाह के पास, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, 203131
(अलीगढ़ शाखा का एलसी नं. BLSA00002669) सतीश (उधारकर्ता) मंजू (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 7,64,061/- (रु. सात लाख चौसठ हजार इकसठ मात्र) एनपीए (04-06-2024)	गाटा नं. 360, मौजा बरौला जाफराबाद शंकर बाजार जिला अलीघर उत्तर प्रदेश 202001
(लखनऊ - गोमती नगर शाखा का एलसी नं. BLSA00003E39) मनोज सिंह (उधारकर्ता) मांडवी सिंह (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 28,30,443/- (रु. अट्ठाईस लाख तीस हजार चार सौ तैंतालीस मात्र) एनपीए (04-06-2024)	प्लॉट सं. 1, 2, 3, 647बी/एफ-40 (पी-1,2,3) के हिस्से पर मकान, खसरा नं. 982 का हिस्सा, सहारा स्टेट लखनऊ के पास एमएमएम मार्ग लखनऊ यूपी 226021
(सीतापुर शाखा का एलसी नं. BLSA00004195) अभिषेक गुप्ता (उधारकर्ता) गौरव गुप्ता (सह-उधारकर्ता 1) लकी गुप्ता (सह-उधारकर्ता 2)	25-06-2024/रु. 62,60,756.5 (रु. बासठ लाख साठ हजार सात सौ छप्पन और पैसे पचास मात्र) एनपीए (05-03-2024)	मकान नं. 2947, मोहल्ला-कुवर जंग, तिहाड़ जिला-शहजानपुर, उमा तकीज वाली गली, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश-242307
(हरदोई - लखनऊ रोड शाखा का एलसी नं. HLSA00043921) देवेंद्र (उधारकर्ता) नीतू (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 5,16,230/- (रु. पांच लाख सोलह हजार दो सौ तीस मात्र) एनपीए (04-06-2024)	गाटा सं. 611 का भाग, परगना और तहसील-संडीला, निकट महाकालेश्वर मंदिर संडीला, ग्राम-एसओएम, जिला-हरदोई, हरदोई, उत्तर प्रदेश-241204
(मेरठ शाखा का एलसी नं. HLSA00042CCC) रियाज (उधारकर्ता) रुकसार (सह-उधारकर्ता 1)	25-06-2024/रु. 15,13,409.08 (रु. पंद्रह लाख तेरह हजार चार सौ नौ और पैसे आठ मात्र) एनपीए (04-06-2024)	प्लॉट सं. ए 86, एच ब्लॉक का भाग, खसरा नं. 3156, ईदगाह कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002

यदि उक्त उधारकर्ता उपरोक्तानुसार पीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो पीसीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर होगा। अधिनियम के तहत उक्त उधारकर्ताओं को पीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा उपरोक्त संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांकः 18.07.2024, स्थानः उत्तर प्रदेश
पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सोनभद्र के खंता पिकनिक स्पॉट के मेकओवर की तैयारियां शुरू

● उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन को सौंपी गई जिम्मेदारी, नए टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर किया जाएगा विकास

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ सोनभद्र

उत्तर प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाने के लिए कृत संकल्प योगी सरकार ने प्रदेश में पर्यटन विकास पर विशेष तौर पर फोकस कर रही है। एक ओर, प्रदेश के सभी प्रमुख तीर्थस्थलों में पर्यटन विकास की तमाम सुविधाओं को विकसित करने के कारण यहां फुटफॉट बढ़ा है, दूसरी ओर प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य युक्त टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में, सोनभद्र जिले के म्योरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले खंता पिकनिक स्पॉट भी शामिल है। कुछ महीने पहले ही इस क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट के तौर पर डेवलप करने के लिए मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिग (एमओयू) साइन हुआ था। ऐसे में, इस क्षेत्र के विकास के लिए सीएम योगी के विजन अनुसार एक विस्तृत कार्य योजना को क्रियान्वित तैयार की गई थी जिस पर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। योगी सरकार द्वारा खंता पिकनिक स्पॉट क्षेत्र के विकास तथा मुख्य भवन समेत अन्य विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के निर्माण व विकास का जिम्मा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन को सौंपा है। यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शॉर्ट टर्म टेंडर के जरिए आवेदन मांगे गए हैं। इस प्रक्रिया से निर्माण व विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी का निर्धारण होगा जो कार्यावंटन के बाद वर्षा अवधि के अतिरिक्त 27 महीने में 3.65 करोड़ रुपए के व्यय से सभी कार्यों को पूर्ण करेगी। वह चिह्नित क्षेत्र में टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर के तौर पर विकास के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगी। इस दौरान भवन निर्माण समेत कुल 283 प्रकार के कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। सीएम योगी के विजन अनुसार तैयार की गई कार्ययोजना के अनुरूप, खंता पिकनिक स्पॉट क्षेत्र को टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर विकसित करने के लिए तमाम प्रक्रार की सुविधाओं से क्षेत्र को युक्त किया जाएगा। इसमें मॉडर्न जिम और चिल्ड्रेन प्लेइंग एरिया जैसी सिविक एमिनिटीज भी

श्रावण मास के दौरान शिवालयों में रहेगी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाः डीजीपी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डीजीपी प्रशांत कुमार ने बुधवार को कहा कि श्रावण मास में भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी।

डीजीपी ने बताया कि राज्य सरकार और पुलिस विभाग का सभी प्रमुख त्योहारों के बारे में पहले से ही एक बेसिक चीजें तय कर दी गई हैं कि सभी परम्परागत तरीके से की जाएगी। कोई भी नई परम्परा नहीं शुरू की जाएगी। इन्हीं मूल सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ते है और हम सभी धर्म गुरुओं और शांति कमेटियों के साथ बैठक करते रहते हैं। यही एक वजह है कि 2017 के बाद से समारोहों के दौरान शांति में किसी तरह की खलल नहीं पड़ी है। इस बार भी, राज्य सरकार के निर्देश पर, मैंने मुख्य सचिव के साथ तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा किया। उन्होंनें कहा कि हमने राज्य सरकार के निर्देश पर जगह-जगह जाकर समीक्षा की है। हम मेरठ, अयोध्या और मथुरा भी गये है। कांवड़ यात्रा के दौरान जो डीजे चलते हैं और मोहर्रम के दौरान जो ताजिया बनते हैं, उनकी लंबाई को निर्धारित किया जाए। जिससे धार्मिक चीजों से किसी को असुविधा न हो और श्रद्धालुओं के किसी भी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। यूपी में आज 15 हजार जुलूस हैं, सभी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 65 कंपनी पीएसी, आठ कंपनी सीआरपीएफ के अलावा पुलिस फोर्स लगी हुई है। मोहर्रम के बाद श्रावण का एक महीने का त्यौहार चलेगा। पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और अन्य क्षेत्रों में जहां सोमवार को बड़ी भीड़ होती है, वहां सावन माह में पड़ने वाले 5 सोमवारों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। इसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। डीजीपी ने कहा कि बुलडोजर को लेकर कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं। पहली चीज यह कि बुलडोजर का इस्तेमाल किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जाता। अगर कोई भी व्यक्ति गरीब के खिलाफ बुलडोजर का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

हापुड़ के एसपी व एएसपी हटाए गए

लखनऊ। शासन ने मंगलवार देर रात तीन आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। इसमें हापुड़ के एसपी और वर्ष 2016 बैच के आईपीएस अफसर अभिषेक वर्मा को हटा दिया गया। अभिषेक को प्रतिक्षारत करते हुए पुलिस मुख्यालय से अटैच किया गया है। उनके स्थान पर 2000 बैच के आईपीएस कुंवर ज्ञानंजय सिंह को हापुड़ का नया एसपी बनाया गया है। ज्ञानंजय गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी थे। वहीं 2000 बैच के ही राजेश कुमार को डीसीपी गाजियाबाद बनाया है। हापुड़ के एडिशनल एसपी राजकुमार अग्रवाल को भी हटाया गया। उनकी जगह विनीत भटनागर को तैनाती मिली है। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को पिलखुवा थानांतर्गत स्थित एक मेडिकल कॉलेज में पुलिस से विवाद की घटना हुई थी। उस समय एडिशनल एसपी भी मौजूद थे। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इसकी शिकायत लखनऊ सीएम कार्यालय में की गई थी। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद स्थानान्तरण की कार्रवाई की गई।

उपचुनावों के मद्देनजर भाजपा शिक्षकों के मामले में पीछे हटी हैः अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारत को पांचवी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए केन्द्र सरकार पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को तीन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने और उत्तर प्रदेश सरकार एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा तो करती हैं किन्तु यह नहीं बताती है कि विकसित राष्ट्रों की तुलना में भारत की स्थिति क्या है? केन्द्र बताए प्रति व्यक्ति आय क्या है और केन्द्र से मदद कितनी मिलनी है।

सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय के डॉ. लोहिया सभागार में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के निर्णय जनविरोधी हैं। शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को स्थगित करने और शहर के कुछ आवासीय स्थलों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही टाल देने में भाजपा की चाल है। उपचुनावों के मद्देनजर ही वह पीछे हटी है। ये निर्णय टालकर सभी को धोखा दिया गया है। वस्तुतः भाजपा सरकार घबराई हुई है। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था चौपट है। बाढ़ में जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। समय से राहत नहीं दी गई है। उसने शानदार गोमती रिवरफ्रन्ट खराब कर दिया है। भाजपा नाले को नदी और नदी को नाला बनाने का काम करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बिखर चुकी है। उसकी राजनीतिक साख भी दांव पर है। वे बेदम है। भाजपा में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। खुद मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार में दलाली की बात स्वीकार करते हैं। भाजपा के पदाधिकारी और विधायक प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और लूट के आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री सब जानते हुए उस पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं।

जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान सपा में शामिल

समाजवादी पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए लखनऊ जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य विजय बहादुर यादव ने बुधवार को अपने तमाम साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। विकास खण्ड बख्शी का तालाब (बीकेटी) लखनऊ के कई दर्जन प्रधान भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी में शामिल होने से संविधान बचाने के लिए पीडीए की लड़ाई में जो मदद मिली उससे मोहनलालगंज क्षेत्र में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को ऐतिहासिक जीत हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन साथियों की मदद से आगे भी समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले प्रमुख ग्राम प्रधानों में वीरेन्द्र सिंह यादव गोइला प्रधान, शैलेन्द्र सिंह यादव देवी रूखारा प्रधान, अरूण सिंह यादव टिकरी प्रधान, उमेश यादव सुभाननगर प्रधान, राम सिंह मुसा पिपरी प्रधान, नरेन्द्र सिंह आधारखेड़ा प्रधान, श्याम शंकर यादव गुडम्बा पूर्व बीडीसी, वीरेन्द्र सिंह यादव अचरामऊ प्रधान, बृजनंदन यादव सरसवा प्रधान, शिवकुमार गांधी चन्द्राकोडर प्रधान, अनिल कुमार संसारपुर प्रधान, सुरेन्द्र रावत बीबीपुर प्रधान, आशीष पाल मडौली प्रधान, लक्ष्मी नारायण कपासी प्रधान, राम विलास सुवंशीपुर प्रधान, राकेश मझोरिया प्रधान, महेन्द्र सिंह हरदौसपुर प्रधान, देशराज रावत जलालपुर प्रधान, विष्णु चौरसिया किशुनपुर प्रधान, आजाद अंसारी अटेसुवा प्रधान, शाहबत अली पैकरामऊ प्रधान, भीम यादव खोजेकपुरवा प्रधान, गुड्डू लोधी घिचेहरी प्रधान, ओम लोधी नगुवामऊ प्रधान, रंजीत मोहम्मदपुर गढ़ी प्रधान, आदि शामिल है।

कोविड काल में नियुक्त एनएचएम कर्मी नहीं हटेंगे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बुधवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा श्रम मंत्री अनिल राजभर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान स्थानांतरण, वेतन विसंगति, नियुक्ति में प्राथमिकता, कोविड काल के भती कर्मियों का समायोजन जैसी मांगों को लेकर हुई बातचीत हुई। यह जानकारी देते हुए महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ बैठक में बिन्दुवार चर्चा में कार्मिकों के स्थानांतरण के विषय पर उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली बैठक में उपलब्ध कराई गई पत्रावली के आधार पर मुख्यमंत्री से स्थानांतरण के लिए अनुमोदन ले लिया गया है। इसके तहत अभी म्युचुअल पर स्थानांतरण की सहमति बनी है, जबकि अन्य रिक्त पदों पर स्थानांतरण की व्यवस्था के प्रयास जारी हैं, इसी वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है। योगेश उपाध्याय ने हालांकि स्थानांतरण मसले पर कर्मचारियों से 30 जुलाई तक इंतजार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वेतन विसंगति पर डिप्टी सीएम को अवगत कराया गया कि 2016 से बजट आ रहा है मगर उसका उपयोग नहीं हो पाया है।

पायनियर वर्गीकृत

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरी माता माया देवी पत्नी स्व.योगेन्द्र नाथ यादव का दिनांक 16.04.2022 को आकस्मिक निधन हो गया था।मेरी माता के नाम केशव ग्रीन सिटी में गाटा संख्या 257/2228 प्लॉट नं. 48 अंश भाग पर स्थित है,जिसका लोन पिरामल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बैंक से था,जिसका भुगतान कर दिया गया है। मय प्लॉट की मूल कॉपी रजिस्ट्री बैंक से लेने के लिए सूचना दे रहा हूं। विकास यादव पुत्र स्व. योगेन्द्र नाथ यादव निवासी–ग्राम गद्दीपुर,पोस्ट–दारानगर, थाना–रामकोट, तहसील व जिला–सीतापुर

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को लिखा पत्र

भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान आकृष्ट कराया

● ऐडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर साझा की पीड़ा, सौंपा ज्ञापन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

ऐडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों के एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री अजय राय से मिलकर अपनी परेशानियां साझा की। प्रतिनिधिमंडल ने राय को इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। उनके समक्ष अपनी बात रखते हुए बताया कि ऐडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 जिसकी परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई तथा परिणाम 17 नवम्बर 2021 को जारी किया गया। परीक्षा में सम्मिलित कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आए हुए परिणाम से असहमत होकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट भी दायर की गई। जिस पर न्यायालय के आदेश पर 6 सितम्बर 2022 को परिणाम पुनः दोबारा घोषित किया गया। अभ्यर्थियों द्वारा दोबारा जारी किये गये परिणाम को लेकर पुनः रिट याचिका दायर की गयी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। अतः अब घोषित परिणाम के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है मगर शासन स्तर पर इस प्रक्रिया को जानबूझकर टाला जा रहा है। प्रतियोगी छात्र समिति से जुड़े आदेश शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बताया कि इसी प्रकार टीजीटी-पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, प्राइमरी भर्ती, एलटी परीक्षा जो कि अभी भी लंबित है जिसे कराने में सरकार हीला हवाली कर रही है। ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए अजय राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 6 सितम्बर 2022 को ऐडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के पुनः घोषित किये गये परिणाम के बाद इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का न्यायालय हस्तक्षेप न होने पर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु उनका ध्यान आकृष्ट कराया। और कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सरकार का ढुलमुल रवैया अभ्यर्थियों के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है।

परिसर में लिफ्ट व एस्केलेटर लगाने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन

● परिसर में पूर्व से स्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर का 6 माह के अंदर आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों व अधिष्ठानों लगी लिफ्ट और एस्केलेटर में दुर्घटना के दौरान नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से मंत्रि परिषद ने मंगलवार को लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली-2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पहले लिफ्ट और एस्केलेटर के विनिर्माण, निर्माण, गुणवत्ता, अंतरनिहित सुरक्षा सुविधायें, संस्थापना, संचालन और अनुरक्षण आदि के लेकर 26 फरवरी, 2024 को विधानमंडल द्वारा यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम-2024 पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा-19 के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर के संचालन, मशीनरी, उपकरण आदि के रखरखाव के लिए नियमावली प्रख्यापित की गयी।

नगर विकास मंत्री ने कहा कि बिना पंजीकरण के अब किसी भी परिसर में लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं लगाये जा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लिफ्ट या एस्केलेटर का अधिष्ठापन एवं कमीशनिंग पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा करते हुए निदेशक विद्युत सुरक्षा के पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसे रजिस्ट्रेशन की अवधि लिफ्ट या एस्केलेटर विनिर्माता द्वारा सुनिश्चित किये गये अवधि तक विधिमान्य होगी। यदि भवन में अधिष्ठापित लिफ्ट या एस्केलेटर में कोई परिवर्तन किया जाना हो, तो इसके लिए नया रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा। प्रदेश में किसी भी परिसर में पूर्व से स्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर का भी 6 माह के अंदर अब आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। एके शर्मा ने कहा कि इसी प्रकार नियमावली में व्यवस्था है कि लिफ्ट व एस्केलेटर के वार्षिक अनुरक्षण हेतु अभिकरण के लिए शामिल सभी एजेंसियों को भी निदेशक, विद्युत सुरक्षा विकास आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियमावली के प्रावधानों के तहत बिजली आपूर्ति बाधित होने या किसी खराबी की स्थिति में लिफ्ट के अंदर फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए लिफ्ट में आटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस लगाया जाना अनिवार्य होगा, जिससे कि दुर्घटना के समय लोगों को बचाया जा सकेगा। सार्वजनिक परिसर में लिफ्ट या एस्केलेटर को संचालित करने के लिए मालिक द्वारा संचालक नियुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम अर्ह और प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ लगाया जाना अनिवार्य होगा।

नगर विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते नगरीकरण, औद्योगिक विकास, बहुमंजिला इमारतों के बनने से सार्वजनिक परिसरों के साथ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, भवनों आदि में लिफ्ट व एस्केलेटर के उपयोग की बढ़ोत्तरी हो रही है। जिसका उपयोग बहुतायत में लोग करने लगे हैं। नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमावली बनाई गयी है।

निवेशकों से 150 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सरगना सहित चार गिरफ्तार

● शेयर बाजार में लाभ दिलाने और पूंजी को क्रिप्टो करेंसी में बदलने का झांसा देकर करते हैं जालसाजी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से निवेशकों को शेयर बाजार में निश्चित लाभ दिलाने का झांसा देकर फर्जी डीमैट खाता खोलकर ट्रेडिंग करने एवं अन्य स्कैमरों की तरह पूंजी को क्रिप्टो करेन्सी में बदलकर विदेश भागने की फिराक में लगे गिरोह के सरगना सहित 4 जालसाजों को लखनऊ के सरोजनीनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया।

एसटीएफ के अनुसार इन जालसाजों ने अभी तक देश व प्रदेश के विभिन्न स्थानों के 2500 निवेशकों से लगभग 150 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की है। गिरफ्तार किए गए जालसाजों में नासिर अली, जाकिर अली, सलमा बानो और सौरभ बाबू शामिल है। एसटीएफ के अनुसार छानबीन के दौरान जानकारी मिली कि नासिर अली पुत्र साकिर अली निवासी 506 कानपुर रोड आजाद नगर लखनऊ अपनी पत्नी, भाई व अन्य लोगों के साथ मिलकर शेयर मार्केट में निवेश कराकर निवेशकों के पैसे हड़पने का कार्य करता है। 16 जुलाई 2024 को सूचना मिली कि नासिर अली हड़पे हुए रुपयों को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्जन कराकर विदेश भागने की फिराक में है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा लखनऊ पुलिस के साथ संयुक्त रूप में घेराबंदी कर थानाक्षेत्र सरोजनीनगर से नासिर अली को गिरफ्तार कर लिया गया।

नासिर अली वर्ष-2018 से इस कार्य को कर रहा है। जिसके लिए उसने कई फर्म बनाकर उसमें लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराता था। लोगों को लोक लुभावन वादे देना कि यह एक सुरक्षित निवेश है जिसमें निवेशक की मूल पूंजी हमेशा सुरक्षित रहेगी और यदि निवेशक अपना पैसा वापिस लेना चाहे तो 3 दिन पूर्व हमे सूचना देकर अपनी निवेश पूंजी अपने बैंक खाते में वापस ले सकता है। निवेशक की पूरी निवेश पूंजी के उपयोग करने का अधिकार नासिर अली व सलमा बानो के पास रहेगा और निवेशक को उसके निवेश की पूंजी का 10 प्रतिशत प्रति माह उसके खाते में जमा भी कराया जाता रहेगा। निवेशकों को किसी प्रकार का शक न हो इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर एक एप 'फैन कैपिटल सर्विसेस' के नाम से बनाया गया था, जिसका एडमिन राईट नासिर अली के पास था। इस एप के माध्यम से निवेशकों की डिटेल लेकर उनका खाता खोला जाता था जिस पर निवेशकों की निवेश रकम का ब्योरा अपने अनुसार दिखाया जाता था। खोले गये फर्जी डीमैट खाता नम्बरों को उसी एप के माध्यम से निवेश धनराशि का लाभ दिखाने के लिए किया जाता था। परन्तु बैकएण्ड पर कोई इस तरह के बैंकिंग सिस्टम को न संचालित करते हुए केवल निवेशकों को पैसों से ही उन्हें भुगतान करते हुए छद्म बैलेंस दिखाने एवं कुछ समय बाद लाग को खाते में न दिखाते हुए उसे प्रिंसिपल अकाउंट में ऐड करना बताया जाता था। बाद में अपने ही अंतर्गत एप्प का एडमिन राईट होने से उसे नियंत्रित करते हुए जिन खातों की देनदारी अधिक हो जाती थी, उसे डीएक्टिवेट करके निवेशकों को झूठी सूचना देते रहना तथा पैसा मांगने पर सर्वर अपडेट, सॉफ्टवेर अपडेट, आदि बहाने बताकर भुगतान को लंबित रखना एवं धीरे-धीरे निवेशकों को कानूनी दांवपेंच में फंसाने की धौंस दिखाने के लिए अपनी कम्पनी में काम करने वाली लड़कियों और अपने अनुसूचित जाति के ड्राइवर के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर डराता रहता था। पैसे न देने के नियत से एडमिन पैनल से उनके खातों में हेराफेरी कर बैलेंस को निल कर देने का कार्य भी करता था। जिन निवेशकों द्वारा अत्यधिक दबाव बनाया गया उन्हें फर्जी हस्ताक्षर का चेक दे देता था जो बाद में बाउंस हो जाते थे। इस सम्बन्ध में पता करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ में भी इसी प्रकरण में 2 अभियोग और पंजीकृत है।

बैक पेपर परीक्षा में ट्रिपल आईआईटी कर नियम लागू, रिजल्ट में एक ग्रेड कम देगा एकेटीयू छात्रों को

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बैकपेपर परीक्षा को लेकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने आईआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे संस्थानों की तरह नियम लागू कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार सत्र 2024 25 में होने वाले बैक पेपर परीक्षा में छात्रों को रिजल्ट आने पर उनके मूल रिजल्ट से एक ग्रेड कम उनको दिया जाएगा।

इसके अलावा अब नए सत्र से बैक पेपर दो मोड में होंगे। बैक पेपर परीक्षाओं में छात्रों को दो विकल्प विश्वविद्यालय की ओर से दिया जाएगा। छात्र अब ऑनलाइन या ऑनलाइन मोड में किसी एक विकल्प चुन कर बैक पेपर की परीक्षा दे सकेंगे। सत्र 2024-25 की सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ यह व्यवस्था लागू होगी।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि इससे पहले कैरी ओवर (बैक पेपर परीक्षा) एमसीक्यू पैटर्न पर करने का निर्णय लिया गया है। कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बताया की विश्वविद्यालय में कई बार देखने को मिला है कि एक साथ जो अपने सभी सेमेस्टर बिना बैक के क्लियर करता है। उसका टोटल परसेंटेज ऐसे छात्रों की तुलना में काम हो जाता है, जो कई विषयों में बैक देखकर अपना पढ़ाई पूरा करते हैं। ऐसे में जब कोई छात्र जो बिना बैक दिए अपनी पढ़ाई पूरी करता है, वह इंटरव्यू के दौरान काफी निराश हो जाता है। क्योंकि बैक पेपर देने वाले छात्रों के नंबर उनसे अच्छे होते है। ऐसे छात्रों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने परीक्षा के नियम में बड़ा बदलाव करते हुए बैक पेपर परीक्षा देने वाले छात्रों के मूल परीक्षा परिणाम जो भी होगा। उसे एक ग्रेड कम उनको उसे विषय में अंक देगा। कुलपति ने बताया कि यह नियम देश के सभी आईआईटी ट्रिपल आईटी और एनआईटी में पहले से ही लागू है। अब वह प्राविधिक विश्वविद्यालय में भी लागू किया जा रहा है.

बता दें कि एकेटीयू ने बीते एक जून को बैक पेपर परीक्षा ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कराने का खाका तैयार किया था। इस फैसले को परीक्षा समिति और एकेडमिक काउंसिल (विद्या परिषद) में रखा गया। एकेटीयू कुलपति ने बताया कि कैरी ओवर परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा को परीक्षा समिति और एकेडमिक काउंसिल से पास हो गया है। विद्या परिषद से पास होने के बाद अब इसे कार्य परिषद में रखकर लागू कर दिया जाएगा। सत्र 2024-25 में दिसंबर में सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ ही यह व्यवस्था शुरू होगी।

इस बार दीक्षांत में नही मिलेगी पीजी व सुपर स्पेशियालिटी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिग्री

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पीजी व सुपर स्पेशियालिटी की परीक्षा अभी तक न होने के चलते इस बार 17 अगस्त को प्रस्तावित किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षान्त समारोह में इन छात्रों को डिग्रियां नहीं मिल पायेंगी। समारोह में सिर्फ एमबीबीएस व बीडीएस के मेधावियों को डिग्री व पदक प्रदान किए जाएंगे।

विवि के प्रवक्ता सुधीर सिंह का कहना है कि दीक्षांत समारोह 17 अगस्त है। इसकी तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। जिन छात्रों की परीक्षा पूरी हो चुकी है। उन्हें डिग्री मिलेगी। बता दें कि इस साल अभी केजीएमयू में सिर्फ एमबीबीएस की ही परीक्षा हुई है। पीजी और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2021 बैच में दाखिले काफी देर से हुए थे। नतीजतन इनकी तीन वर्ष की अवधि अभी पूरी नहीं हो सकी है।

इन पाठ्यक्रमों की परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। पीजी के 300 व सुपर स्पेशियालिटी के करीब 100 सीटें हैं। एमबीबीएस में 250 सीट हैं। इन छात्रों को दीक्षांत समारोह के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। पीजी और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए 20 से ज्यादा पदक हैं। यह पहला मौका है जब दीक्षांत में पीजी व सुपर स्पेशियालिटी छात्र व मेधावियों को डिग्री व पदक नहीं मिल पा रहे हैं।

ग्रह दोष मिटाकर पंचायतों में सौभाग्य जगाएगी नवग्रह वाटिका

● मोहनलालगंज की सभी 78 ग्राम पंचायतों में नवग्रह वाटिका बनवाने की तैयारी

पौधा	ग्रह
पलाश	सोम
खैर	मंगल
अपामार्ग	बुध
पीपल	गुरु
गूलर	शुक्र
शमी	शनि
दुर्वा	राहु
कुश	केतु
मदार	सूर्य

मोहनलालगंज। ग्रह शांति के लिए नवग्रह वाटिका की तलाश में अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। अलबत्ता नवग्रह वाटिका लोगों का सौभाग्य जगाने में मददगार बनेगी। ब्लॉक प्रशासन ने मोहनलालगंज की सभी पंचायतों में नवग्रह वाटिका बनाने की तैयारी की है। खास बात यह है कि वन विभाग की नर्सरी में इसके लिए सभी पौधे भी तैयार किए गए हैं।

मोहनलालगंज की सभी 78 ग्राम पंचायतों में पौधरोपण अभियान के तहत नवग्रह वाटिका तैयार की जाएगी। जिसके लिए बीडीओ आशुतोष श्रीवास्तव ने सभी सचिव और प्रधान को पंचायत भवन और स्कूल में सुरक्षित स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। एपीओ उदयराज शर्मा ने बताया नवग्रह वाटिका में पलाश खैर अपामार्ग पीपल गूलर शमी दुर्वा कुश और मदार के पौधे लगाए जाएंगे। वाटिका के पौधे सुरक्षित रखने के लिए चिन्हित भूमि पर पिलर लगाकर तारबाड़ लगाया जाएगा। पौधों की सिंचाई और देखरेख के लिए मजदूर लगाए जाएंगे।

हरवंश खेड़ा नर्सरी में उगाए गए हैं वाटिका के लिए पौधे

वन विभाग के डिप्टी रेंजर अभिषेक ने बताया नवग्रह वाटिका के पंचायतों को पौधे तलाशने में कोई परेशानी नहीं होगी। विभाग की हरवंश खेड़ा नर्सरी में इसके लिए खासतौर पर पलाश पीपल गूलर अपामार्ग शमी खैर और मदार के पौधे उगाए गए हैं। जबकि शेष पौधे स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। डिप्टी रेंजर ने आम लोगों से भी हरियाली बढ़ाने के लिए पौधरोपण अभियान में भाग लेने और नवग्रह वाटिका तैयार करने की अपील की।

ग्रहदोष का निवारण करेगी नवग्रह वाटिका

आचार्य दिनेश त्रिपाठी ने बताया नवग्रह वाटिका तैयार होने से गांव के लोगों को विभिन्न ग्रह दोष का निवारण करने में काफी आसानी होगी। वाटिका तैयार होने के बाद उसमे लगे पौधों के फूल फल पत्तों और लकड़ी से ग्रह शांति में काफी मदद मिलने का विधान है। जबकि इन पौधों की सेवा मात्र से भी सौभाग्य जगाने में अहम मदद मिलती है। पंडित ओमप्रकाश त्रिवेदी ने बताया नवग्रह वाटिका गांव के लोगों के लिए प्रकृति का वरदान बनेगी। वाटिका में लगे पौधों की मदद से पूजा पाठ और हवन के जरिए ग्रहों की महादशा का प्रभाव कम हो सकेगा।

सिपाही ने बदलवा दी तहरीर, लूटपाट को मारपीट बना गई पुलिस

● पीड़ित दुकानदार ने सोशल मीडिया पर बेपर्दा किया पुलिस का खेल

संवाददाता। मोहनलालगंज

चाउमीन दुकानदार से लूटपाट के मामले में अठारह घंटे तक सीमा विवाद में उलझी रहने वाली पुलिस ने एफआईआर में भी खेल कर दिया। पुलिस कर्मियों ने पीड़ित की तहरीर बदलवाकर लूट की वारदात को मारपीट में तब्दील करा दिया। हालांकि पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस की कारगुजारी बेपर्दा हो गई है।

निगोहा के अहमदपुर खालसा निवासी शोभित चाउमीन की दुकान चलाकर परिवार की आजीविका चला रहे हैं। शोभित का आरोप है कि सोमवार की रात कुढ़ा बाजार से ठेला लेकर वापस घर लौटते समय रास्ते में दो बाइक से आए चार नकाबपोश बदमाशों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर तीन हजार रुपए और मोबाइल फोन छीनकर भाग निकले। पीड़ित शिकायत लेकर निगोहा और मोहनलालगंज थाने के चक्कर काटता रहा। लेकिन कार्रवाई के बजाए पुलिसकर्मी सीमा विवाद में उलझे रहे। लूटपाट का मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मोहनलालगंज पुलिस ने एफआईआर तो लिखी। लेकिन दारोगा और सिपाही ने पीड़ित की तहरीर बदलवाकर एफआईआर में भी खेल कर दिया। बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए पीड़ित के वीडियो ने पुलिस के सारे खेल को बेपर्दा कर दिया। पीड़ित शोभित ने सिपाही पर दबाव डालकर तहरीर बदलवाने का आरोप लगाया।शोभित ने बताया पुलिस कर्मियों ने लूटे गए रुपए और मोबाइल जल्द बरामद करने का भरोसा दिया है। लेकिन उन्होंने लूट दर्ज करने से इंकार कर दिया। जिसे लेकर लोग पुलिस की कारगुजारी पर तमाम सवाल उठा रहे हैं।

एकेटीयू में इनोवेशन हब ने स्टार्टअप्स के लिए लांच किया पहला कोहट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के अर्ली स्टेज स्टार्ट अप्स के लिए डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के इनोवेशन हब ने कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे के निर्देशन में वाधवानी फाउंडेशन के साथ मिलकर उनके कार्यक्रम लिफ्ट ऑफ प्रोग्राम के तहत लिफ्ट ऑफ कोहट 7.0 नाम से एक कोहट लॉन्च किया है। जिसका उद्देश्य प्रदेश के अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को सफल स्टार्टअप बनाना है। उक्त कार्यक्रम में कुल मिलाकर 50 चुनिंदा स्टार्टअप्स ने प्रतिभाग किया। अगले चरण में इनमें से 20 स्टार्टअप्स को चयनित करके लिफ्ट ऑफ कोहट कार्यक्रम के अंतर्गत चार सप्ताह की ट्रेनिंग, ऑनलाइन माध्यम से वाधवानी फाउंडेशन द्वारा दी जाएगी। इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइपिंग, पेटेंट प्रोसेस, कंपनी रजिस्ट्रेशन, आइडिया पिचिंग, इन्वेस्टमेंट एवं अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। जिससे भविष्य में ये सफल स्टार्टअप्स बन पाए एवं प्रदेश की इकॉनमी में सहायक हों। कार्यक्रम में इनोवेशन हब हेड महीप सिंह ने सभी स्टार्टअप्स को इन्नोवेशन हब एवं वधवानी फाउंडेशन द्वारा सम्मिलित रूप से स्टार्टअप्स को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। तथा इनोवेशन हब किस तरह से स्टार्ट अप्स को सहायता दे रहा है इसके बारे में भी जानकारी दी। इनोवेशन हब मैनेजर वंदना शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।

टीएस मिश्रा लॉ स्कूल में 19 से दो दिवसीय नेशनल वर्कशॉप का आयोजन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

टी.एस. मिश्रा विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल द्वारा तीन नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 पर आगामी 19-20 जुलाई को दो दिवसीय ऑनलाइन नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। वर्कशाप में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं, अधिवक्ता एवं विधि व्यवसाय से जुड़े लोग बड़ी संख्या में प्रतिभा कर रहे हैं।

संकाय के अधिष्ठाता प्रोफ़ेसर (डॉ.) सी.पी. ने बताया कि ये नए कानून भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं, इनका उद्देश्य पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से न्याय के क्रियान्वयन पर विचार करना, राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करना तथा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य समीक्षा शुरू कर पुराने औपनिवेशिक कानूनों को नया रूप देना और उन्हें बदलना है, ताकि उन्हें इन कानूनों की प्राथमिकता बनाया जा सके। इस नेशनल वर्कशॉप में प्रतिष्ठित वक्ताओं द्वारा उपरोक्त विषयों पर चर्चा एवं व्याख्यान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन तीन नए आपराधिक कानून पर और अधिक प्रकाश डालने एवं छात्रों के मध्य इस और ध्यान आकृष्ट कराने हेतु एक ऑनलाइन नेशनल क्विज का भी आयोजन किया जा रहा है। जिसमें देश भर के विभिन्न विधि संस्थाओं के सत्तर से अधिक छात्र-छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। इस ऑनलाइन क्विज के विजेताओं को धनराशि एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

ग्राम प्रधान की मदद से जन-जन तक पहुँचेंगी स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं

लखनऊ में 65 प्रशिक्षकों को किया गया तैयार, फतेहपुर और वाराणसी से होगी शुरूआत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

गांव के प्रधान समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण फेथलीडर माने जाते हैं। इसे देखते हुए उप्र सरकार स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराने की तैयारी में है। इसकी पहल शासन स्तर पर हो चुकी है और लखनऊ में 65 स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मियो और फतेहपुर व वाराणसी जिले के पंचायती राज प्रतिनिधियों को बतौर प्रशिक्षक दो दिनों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये प्रशिक्षक परिवार नियोजन , मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं एवं पोषण संबंधी सेवाओं को लेकर ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित करेंगे। यह कार्यक्रम फिलहाल फतेहपुर और वाराणसी जिले से शुरू किया जा रहा है।

ग्राम प्रधानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उप्र, सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज (सीथ्री) के सहयोग से लखनऊ के एक होटल में

दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस योजना के पीछे यह सोच है कि स्वस्थ गाँव की अवधारणा, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में एक महत्वपूर्ण थीम है। जिसमें पंचायतें जागरूकता बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परिवार कल्याण निदेशालय की संयुक्त निदेश मातृत्व स्वास्थ्य डॉ शालू गुप्ता का कहना है कि यह एक अनूठा हस्तक्षेप है और यह बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमें समुदाय को संगठित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि प्रधान हमारा समर्थन करते हैं, तो हम गुणवत्ता के साथ और कम समय में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल कर सकेंगे। सिफ्सा की महाप्रबंधक प्रशिक्षण डॉ रिंकू श्रीवास्तव ने कहा कि यह मॉड्यूल प्रधानों की क्षमताओं को विकसित करने, परिवार नियोजन सेवाओं में सुधार लाने, स्वास्थ्य प्रणाली की समझ बढ़ाने, फ्रंटलाइन वर्कर्स की भूमिका को समझने और उनके योगदान पर केंद्रित है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रधानों को सशक्त बनाना है ताकि वे समुदाय के परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकें।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक परिवार नियोजन कार्यक्रम डॉ सूर्यांश ओझा ने कहा कि परिवार नियोजन को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य व पोषण पर प्रधानों का प्रशिक्षण कई कारणों से महत्वपूर्ण है। स्थानीय जनप्रतिनिधि के रूप में, प्रधान समुदाय की आवश्यकताओं और गतिविधियों को गहराई से समझते हैं, जिससे वे परिवार नियोजन और अन्य स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं।

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण से मिलेगी गति

दो दिवसीय कार्यक्रम में बतौर प्रशिक्षक, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले फतेहपुर जिले के सहायक पंचायती राज अधिकारी राम सेवक वर्मा का कहना है कि यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम है। जब पंचायतों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के केंद्र के रूप में मान्यता दी जा रही है। यह एकजुटता एलएसजीडी (स्थानीय स्व-शासन संस्थानों) में वांछित परिवर्तन लाएगी। इसी जिले के अमौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ पुष्कर कटियार मानते हैं कि यह एक अनूठा हस्तक्षेप है और यह बहुत आवश्यक है क्योंकि हमें समुदाय को संगठित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि प्रधान हमारा समर्थन करते हैं, तो हम गुणवत्ता के साथ और कम समय में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल कर सकेंगे। वाराणसी जिले की उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कल्पना सिंह ने कहा कि यह प्रशिक्षण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समुदाय की भागीदारी को बढ़ाएगा और अंतिम मील सेवाओं को सुनिश्चित करेगा।

नदियों के जलस्तर और तटबंधों की निरन्तर मॉनीटरिंग की जाए

● जलशक्ति मंत्री ने की सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल देर शाम यहाँ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्यालय स्थित सभागार में प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग अनिल गर्ग, विभागाध्यक्ष अखिलेश सचान की उपस्थिति में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में जलशक्ति मंत्री द्वारा उपस्थित विभाग के समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 से उनके कार्यक्षेत्र में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

जलशक्ति मंत्री ने मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिये गये कि वे अपने क्षेत्र के समस्त कार्यों आदि की जानकारी अपनी डायरी में रखें तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करते रहें व जिन अधिकारियों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती जा रही है उनके विरूद्ध कार्यवाही भी प्रस्तावित करें। स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक में बाढ़ से सम्बन्धित उन अधीक्षण अभियन्ताओं / अधिशासी अभियन्ताओं की सूची तैयार करने के निर्देश प्रदान किये गये जिनका परिवार लखनऊ में रहता है एवं उन अधिकारियों की बाढ़ के समय उनके मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर रात्रि के समय भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया। सिंह ने बैठक में उपस्थित मुख्यालय पर कार्यरत मुख्य अभियन्ताओं से भी वार्ता की व उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। बैठक में कड़े निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित जनपदों के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाए। नदियों के जलस्तर और तटबंधों की निरन्तर मॉनीटरिंग की जाए। बाढ़ चौकियों पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी निरंतर स्थिति पर नज़र बनायें रखें। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय पर ही रहें, कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी विभागाध्यक्ष की अनुमति के विना अपने मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा पाए जाने पर कड़ी करवाई की जाएगी। बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों के समस्त अधिकारी/कर्मचारी ज़िला प्रशासन से नियमित संपर्क बनाए रखें जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके, दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के ख़िलाफ़ करवाई की जाएगी। जलशक्ति मंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में विभागीय ज़मीन/नहरों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, यदि कहीं अतिक्रमण हो तो उसे अतिक्रमण मुक्त करायें, अतिक्रमण होने पर संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/ आधिशासी अभियंता की ज़िम्मेदारी तय की जाएगी।

कृषि विभाग के छापे में अवैध उर्वरक फैक्ट्री का भंडाफोड़

● जिला कृषि अधिकारी की टीम ने मोहनलालगंज के महेश खेड़ा में की छापेमारी

संवाददाता। मोहनलालगंज

महेश खेड़ा गांव में बुधवार की शाम कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित हो रही उर्वरक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। टीम को मौके से बड़े पैमाने पर खाद बनाने का कच्चा माल भी बरामद हुआ है। मौके से बरामद खाद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। जबकि फैक्ट्री को सील कर मामले में कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी है।

मोहनलालगंज के महेश खेड़ा गांव में पिछले कुछ माह से अवैध रूप से खाद बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। किसी ने इसकी शिकायत एसडीएम बृजेश कुमार वर्मा से की। एसडीएम की सूचना पर बुधवार को जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह और अपर जिला कृषि अधिकारी हर्षित त्रिपाठी की अगुवाई में कृषि विभाग की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ महेश खेड़ा में जगदीश प्रसाद की बिल्डिंग में छापा मारा। इस दौरान चार दुकानों और गोदाम में डीएपी एनपीके और एमओपी के लगभग सात सौ बैग बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त काफी मात्रा में खाद बनाने का कच्चा माल और बैग सिलने की मशीन बरामद की गई। यही नहीं गोदाम और दुकानों में सरकारी खाद के बैग भी पाए गए। जिनकी जांच भी शुरू कर दी गई है। जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने बताया छापेमारी में मिली खाद के चार सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। चार दुकानों और गोदाम को सील कर दिया गया है। बिल्डिंग मालिक जगदीश प्रसाद ने बताया दुकानें और गोदाम राघव गुप्ता नाम के किसी शख्स ने किराए पर लिया था। जिसका मोबाइल नंबर उन्होंने दिया है। हालांकि कोई किरायानामा अथवा एग्रीमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। डीएम के निर्देशानुसार एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया सरोजनीनगर के खटोला गांव में भी इसी तरह अवैध रूप से खाद स्टोर किए जाने की सूचना मिली है। वहां भी छापेमारी की जाएगी।

निशातगंज में मोहर्रम पर ताजिया निकालते मुस्लिम समाज के लोग

अनुप्रिया पटेल को नन्दी का जवाब

टोल प्लाजा भी ठीक, दूरी भी सही, नहीं हो रही गलत वसूली

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● पत्र लिखकर अनुप्रिया पटेल ने उठाया था वाराणसी- शक्तिनगर मार्ग (एसएच-5ए) में स्थित टोल प्लाजा का मामला, नियमसंगत नहीं होने का लगाया था आरोप

वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर टोल प्लाजा की अनियमितता को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के आरोपों को योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता %नंदी% ने तथ्यहीन बताया है। नंदी ने कहा है कि सम्बंधित मामले में कहीं भी अनाधिकृत टोल वसूली नहीं की जा रही है। अनुप्रिया पटेल को लिखे जवाबी पत्र में यूपी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री ने हर एक आरोप का तथ्य के साथ बिंदुवार जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर पूर्व में 3 स्थानों यथा-फत्तेपुर (चैनेज 4.680 किमी), लोढ़ी (चैनेज 68.100 किमी) तथा मालोघाट (चैनेज 108.940 किमी) पर निर्धारित मानकों के अनुरूप टोल प्लाजा स्थित हैं। निजी विकासकर्ता द्वारा यह शिकायत किये जाने पर कि फत्तेपुर टोल प्लाजा से शक्तिनगर जाने वाले वाहन नरायनपुर-जमुई के रास्ते चुनार होते हुये अहरौरा से पहले वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर चले जाते हैं एवं शक्तिनगर से वाराणसी को आने वाले वाहन अहरौरा के बाद (मार्ग के चैनेज 18.700 किमी) चकिया होते हुये चले जाते हैं, जिससे राजस्व की हानि होती है। उक्त लीकेज को रोकने के लिये अहरौरा में एडिशनल टोल कलेक्शन बूथ स्थापित करने की अनुमति सशर्त अनुमति दी गई। एडिशनल टोल बूथ के लिए शर्त थी कि फत्तेपुर या अहरौरा में से किसी एक टोल पर ही वाहन से टोल फीस वसूली की जाए। राज्य सरकार के मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अहरौरा टोल प्लाजा पर केवल उन्हीं वाहनों से शुल्क वसूल किया जाता है, जो फत्तेपुर टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान नहीं करते हुये वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा है कि टोल प्लाजा फत्तेपुर एवं अहरौरा मे से एक ही स्थान पर टोल लेने की व्यवस्था है।

इस प्रकार उपर्युक्त टोल की व्यवस्था एवं एक से दूसरे टोल के बीच की दूरी स्थापित मानकों के अनुरूप है। यही नहीं, निजी विकासकर्ता मे. एसीपी टोलवेज प्रा.लि. (मे.एपको) को पूर्व में टोल बूथों पर फास्ट टैग सिस्टम लगाकर टोल शुल्क वसूली के लिये निर्देशित किया गया था, परन्तु उनके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही न किये जाने के कारण पुन: 14 जुलाई को उनके प्रतिनिधि को बुलाकर यह निर्देश दिए गए कि एक माह के अन्दर मार्ग के सभी टोल बूथों पर फास्ट टैग सिस्टम लगाकर टोल वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते: राजेश्वर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट के जवाब में बुधवार दोपहर को सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने ट्वीट कर सपा मुखिया पर तीखा हमला किया है। अखिलेश यादव के कुर्सी की लड़ाई की गर्मी वाले बयान पर जवाब देते हुए अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। डॉ. सिंह ने आगे लिखा कि सपा प्रमुख आप याद कीजिए, सत्ता के रथ पर आरूढ़ होकर आप अपने परिवार को भी एक नहीं रख सके थे। आपको वो समय भी नहीं याद जब, मुजफ्फरनगर दंगे में 62 से ज्यादा लोग मारे गए, विस्थापितों को टेंट में ठिठुरता छोड़ आप सैफई महोत्सव में फिल्मी सितारों के साथ समय बिता रहे थे। सरोजनीनगर विधायक ने आगे लिखा कि भाजपा 19 करोड़ कार्यकर्ताओं का विशाल परिवार है जिनके लिए देश प्रथम है, अपना हित नहीं, भाजपा की नीतियां स्पष्ट हैं, नीयत स्पष्ट है, नेतृत्व सशक्त है। डॉ. राजेश्वर सिंह ने व्यंग कसते हुए आगे लिखा कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता भाजपा राज में सुख, शांति से रहते हुए आज भी सपा शासनकाल के दंगों, गुंडाराज, माफियाराज को याद करके सिहर जाती है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी और योगी के नेतृत्व में भाजपा 2027 का चुनाव लड़ेगी और फिर से प्रचंड बहुमत से जीत कर आएगी। समाजवादी पार्टी को चुनौती देते हुए सरोजनीनगर विधायक ने आगे लिखा कि मेरी ये बात, ये दिन और ये तारीख़ याद रखें। तारीख़ का इंसाफ़ हमेशा आम जनता की आवाज़ होता है। इसमें न मुझे और न ही भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को संशय है। हर एक कार्यकर्ता मोदी-योगी के साथ है और दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा।

गजवरियन खेड़ा गांव में उल्टी दस्त की सूचना पर पहुंची सीएमओ की टीम, पांच भर्ती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

क्षेत्रीय आशा एवं एएनएम द्वारा कल्ली पश्चिम के गजवरियन खेड़ा गांव में उल्टी दस्त की सूचना प्राप्त होने पर बुधवार को सीएमओ के निर्देश पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरठिया के चिकित्सीय दल ने गांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 5 मरीजों को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहनलालगंज में भर्ती किया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देशों के क्रम में जनपदीय अधिकारियों डा गोपीलाल अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डा निशान्त निर्वाण, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ तथा डा अशोक कुमार, सामु.स्वा.केन्द्र मोहनलालगंज एवं डा चन्दन कुमार सिंह यादव, अधीक्षक, सामु.स्वा.केन्द्र सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा निरीक्षण का भ्रमण किया गया। रात्रि में उक्त क्षेत्र में रोगी वाहन को स्थापित किया गया। वहीं आज प्रात: डा मनोज अग्रवाल, मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ एवं डा एपी सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा गजवरियन खेडा गॉव का भ्रमण किया गया तथा जनसामान्य से हाल-चाल लिया गया। भ्रमण के दौरान स्थानीय सभासद भी उपस्थित थे।

भ्रष्ट पर एक्शन तो ईमानदार कर्मियों को सम्मानित कर रही योगी सरकार

● गाजियाबाद के बहरामपुर बस डिपो के चालक और परिचालक को ड्यूटी के दौरान ईमानदारी के लिए दिया जाएगा प्रशस्ति पत्र

लखनऊ। योगी सरकार एक तरफ जहां भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों और अधिकारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत नकेल कस रही है तो वहीं मेहनती और ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत भी कर रही है। ताजा मामला गाजियाबाद का है, जहां नगरीय परिवहन के तहत संचालित सिटी इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर और कंडक्टर को उनकी ईमानदारी के लिए विभाग की संस्तुति पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी ईमानदारी के साथ कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया जाएगा।

दरअसल, बुधवार को गाजियाबाद सिटी ट्रांस लि. के तहत बहरामपुर डिपो की बस संख्या यूपी 14 केटी 6554 जोकि लोनी रूट पर थी पर अज्ञात महिला यात्री का पर्स छूट गया था। परिचालक सतेंद्र (आईडी 231) एवं चालक आसिफ को यह पर्स मिला, जिस पर दोनों ने ईमानदारी का परिचय देते हुए प्राप्त हुए पर्स को गाजियाबाद सिटी ट्रांस.लि. के बहरामपुर बस डिपो में लाकर जमा कराया गया। पर्स में 6000 रुपए नगद एवं अन्य जरूरी समान था। संबंधित महिला यात्री के परिजनों द्वारा पर्स पर दावा करने पर जांच किए जाने के उपरांत संबंधित दावेदारों को पर्स दे दिया गया। साथ ही दोनों कर्मचारियों की ईमानदारी से अन्य कर्मचारियों को भी ईमानदारी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से संबंधित परिचालक सतेंद्र एवं चालक आसिफ को प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई है।

बिजली भी पैदा करेगा, पर्यावरण भी बचाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे

● दोनों किनारों पर रोपे जाएंगे 25 हजार से अधिक वृक्षों के पौधे

एक्सप्रेस-वे पर बीओओ मॉडल पर विकसित होगा बुंदेलखंड सोलर पार्क, करेगा 450 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

दशकों तक उपेक्षा का दंश झेलने वाले बुंदेलखंड में सुनियोजित और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा जग-जाहिर है। एक तरफ यहां करीब 36 हजार एकड़ भू-क्षेत्र में नया औद्योगिक शहर बसाने के लिए शासन की कवायद जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के सबसे लंबे सोलर पार्क को भी बुंदेलखंड से होकर गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के दोनों किनारों पर विकसित किया जाना है। करीब 1700 हेक्टेयर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे इस सोलर पार्क को विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वेज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) की देखरेख में इसे बी.ओ.ओ. यानी बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट मॉडल पर विकसित किया जाएगा। बता दें कि बीते साल अगस्त में यूपीडा की ओर से इसके प्री-फिजिबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया गया था, जिसमें 9 संस्थाओं की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया था। इनमें से मेसर्स ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट ने इसी साल फरवरी में अपनी विस्तृत रिपोर्ट यूपीडा के अधिकारियों के सामने पेश की थी, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री के समक्ष यूपीडा के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे क्षेत्र को सोलर फार्म के रूप में स्थापित करके इसे सोलर एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित करना चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूपीडा की ओर से इस सोलर पार्क के लिए 17 सौ हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है। ये भूमि इटावा से चित्रकूट तक 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के मुख्य कैरिज वे और सर्विस रोड के बीच की है। मुख्य कैरिज वे और सर्विस रोड के बीच उपलब्ध भूमि की औसत चौड़ाई 15-20 मीटर है। यहीं पर सोलर पार्क को निर्मित किया जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में सोलर रेडिएशन दर 5 से 5.5 केडब्ल्यूएच प्रति स्क्वायर मीटर, प्रतिदिन है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां सोलर पार्क को विकसित करने में तकरीबन ढाई हजार करोड़ से अधिक की लागत आएगी। इसके लिए कंपनियों को 25 साल के लीज पर भूमि आवंटन की व्यवस्था होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के दोनों किनारों पर विकसित होने वाले सोलर पार्क से 450 किलोगवाट ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा, जो करीब 1 लाख उपभोक्ताओं की आवश्यक्ता को पूरा कर सकेगा। इटावा से चित्रकूट तक लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर बांदा और जालौन में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इस एक्सप्रेस-वे के किनारे 25 हजार से अधिक वृक्षों को लगाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिये हैं। इसके किनारों पर पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर और नीम के वृक्ष लगाए जाएंगे। वहीं बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा करीब 36 हजार एकड़ में नोएडा की तर्ज पर नया शहर बसाने की कवायद भी तेज गति से आगे बढ़ रही है, जिसे 2028 तक विकसित करने का लक्ष्य सीएम योगी ने तय किया है।

मेरठ के विभिन्न मार्गों पर 10 बस स्टॉप्स का होगा मेकओवर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश में यात्री सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार लगातार प्रदेश में परिवहन क्षेत्र की आधारभूत संचनाओं का विकास कर रही है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में यात्री यातायात को लेकर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर लगातार काम हो रहा है। ऐसे में, अब सीएम योगी की मंशा अनुसार मेरठ शहर के विभिन्न मार्गों पर स्थित 10 बस स्टॉप्स व यात्री शेल्टर्स का मेकओवर कर उन्हें आधुनिक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे न केवल यात्री सुविधाओं में विकास की प्रक्रिया को गति मिलेगी बल्कि शहर के सौंदर्यीकरण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने अवस्थापना निधि के जरिए इन सभी कार्यों को पूर्ण करने की तैयारी शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एमडीए द्वारा सिंगल बिड प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन मांगे गए हैं जिससे एजेंसी निर्धारण की प्रक्रिया को पूरा कर उसे कार्य आवंटित किया जाएगा। इस विकास कार्य को पूर्ण करने के लिए 1.70 करोड़ रुपए का व्यय होगा। एमडीए की कार्ययोजना के अनुसार, जिन 10 बस स्टॉप्स व यात्री शेल्टर्स के कायाकल्प की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है उसमें यूनिवर्सिटी के 2 बस स्टॉप्स, तेजगढ़ी बस स्टॉप, हापुड़ बस अड्डा बस स्टॉप, मेरठ मेडिकल कॉलेज में 2 बस स्टॉप, बच्चा पार्क बस स्टॉप तथा जीआईसी बस स्टॉप शामिल हैं। इन सभी बस स्टॉप्स में यात्री शेल्टर्स में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए जाएंगे। इन्हें सोलर सेटअप से युक्त किया जाएगा तथा मुख्यत: 6 प्रकार के विकास कार्यों को यहां पूर्ण किया जाएगा। बस शेल्टर्स 6 मीटर लंबे व 2.5 मीटर चौड़े होंगे। इन्हें टफेन बैक सपोर्ट ग्लास युक्त किया जाएगा।

भविष्य के अनुकूल होगी धान और गेहूं की खेती, घटेगी लागत, बढ़ेगी उत्पादकता

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (इरी) के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं की खेती भविष्य के अनुकूल होगी। इससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ेगी। इरी ने इस दिशा में महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) चौक माफी पीपीगंज और गोरखनाथ मंदिर के चौक बाजार (महराजगंज) स्थित 500 एकड़ के फार्म के साथ अनुसंधान परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। इरी ने महायोगी केवीके चौक माफी और चौक बाजार, महराजगंज स्थित फार्म के एक हिस्से पर इस सीजन में धान की सीधी बुआई कराई। इससे खर पतवार से मुक्ति तो मिली ही है, रोपाई का खर्च भी बच गया है।

इरी के साउथ एशिया रीजनल सेंटर (वाराणसी) के डायरेक्टर डॉ. सुधांशु सिंह के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने बुधवार को चौक बाजार स्थित फार्म पर धान की खेती का निरीक्षण किया और अब तक किए गए प्रयोग/अनुसंधान के परिणाम का मूल्यांकन किया। निरीक्षण और मूल्यांकन के बाद डॉ. सुधांशु सिंह ने बताया कि फार्म के एक हिस्से पर समय रहते मशीन से धान की सीधी बुआई कराई गई थी। इसके कारण फसल में खर पतवार नहीं लगे हैं। सीधी बुआई से रोपाई की लागत बच गई है। रोपाई में खर पतवार का पनपना आम समस्या भी है। उन्होंने बताया कि समय पर धान की सीधी बुआई करा दी जाए तो प्रति एकड़ 10 से 15 हजार रुपये की लागत कम हो जाएगी। साथ ही खर पतवार की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। इरी के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, महायोगी गोरखनाथ केवीके के साथ मिलकर धान की ऐसी खेती की प्रविधि पर काम कर रहा है जिससे मीथेन का उत्सर्जन कम हो, खाद और सिंचाई की लागत घटे और उत्पादकता में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि हो। इसके लिए धान की कई किस्मों को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि गेहूं की बुआई समय पर होनी चाहिए। 15 नवंबर के बाद गेहूं की बुआई करने पर 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति दिन की उत्पादकता गिरती है। डॉ. सुधांशु ने बताया कि इरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सहफसली और मिश्रित खेती को लेकर भी विशेष परियोजना पर काम कर रहा है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के साथ कालानमक धान की खेती पर अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही उन्नत, क्लाइमेट स्मार्ट और बायोफर्टिफाइड धान की किस्मों को भी, जिसमें हाई जिंक प्रमुख है, को वर्टिकल कैफेटेरिया में भी लगाया गया है। सभी परियोजनाओं के प्रारंभिक परिणाम सुखद और उत्साहवर्धक आए हैं। चौक बाजार स्थित फार्म पर धान की खेती का निरीक्षण करने के दौरान डॉ. सुधांशु सिंह के साथ भारत सरकार के पूर्व औषधि महानियंत्रक डॉ. जीएन सिंह, इरी के सीनियर एसोसिएट साइंटिस्ट डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, महायोगी गोरखनाथ केवीके चौक माफी के अध्यक्ष डॉ. आरके सिंह, वैज्ञानिक डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव आदि भी मौजूद रहे।

आने वाले कुछ वर्षों में बाजारों में होगी यूपी के लीची की बहार

योगी सरकार बागवानी को लगातार दे रही प्रोत्साहन, स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आने वाले कुछ वर्षों में बाजार में सिर्फ बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश के लीची की भी बहार होगी। बिहार के जिन जिलों (मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और चंपारन आदि) में लीची की खेती होती है उनकी कृषि जलवायु क्षेत्र (एग्रो क्लाइमेट जोन) कमोबेश यूपी के पूर्वांचल के ही समान हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में पूर्वांचल की ही भूमिका अग्रणी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी गृह जनपद पूर्वांचल का गोरखपुर ही है। ऐसे में सरकार और इसकी कृषि संस्थाओं का भी लीची की खेती पर खास फोकस है।

लीची के पौधों के रोपण में विशेष सावधानी रखें। जिस गड्ढे में लीची के पौधे का रोपण किया जाए उसमें लीची के पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी अवश्य डालें। इसमें माइक्रोराइजा पाया जाता है जो लीची के नए पौधों की बढ़वार के लिए अति आवश्यक है। इससे लीची के पौधों के मरने की आशंका कम रहती है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एसपी सिंह के अनुसार पूर्वांचल के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार किसानों को कुछ खास प्रजातियों के रोपण की सलाह दी जाती है। ये सात प्रजातियां हैं रोज सेंटेड, शाही, चाइना, अर्ली वेदाना, लेट बेदाना, गांडकी संपदा और गांडकी लालिमा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत चयनित इस केंद्र का प्रयास है कि किसानों को बेहतर फलत वाले गुणवत्ता के पौध मिलें। इसके लिए हर प्रजाति के कुछ पौधे भी लगाए गए हैं। इनमें से श्रेष्ठतम गुणवत्ता के पेड़ से नर्सरी तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एसोसिएशन नामक संस्था टाटा ट्रस्ट, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर और कृषि विज्ञान केंद्र कुशीनगर की मदद से यह काम पिछले कुछ वर्षों से कर रही है। संस्था के प्रमुख वीएम त्रिपाठी के अनुसार जरूरत के अनुसार वे संबंधित संस्थाओं से प्लांटिंग मैटेरियल, तकनीकी और अन्य सहयोग लेते हैं। अब तक उनकी संस्था की मदद से शाही और चाइना लीची के करीब 40 से 50 एकड़ बाग लगाए जा चुके हैं। किसान इनमें सीजन के अनुसार सहफसल भी लेते हैं। डॉ. एसपी सिंह के अनुसार लीची के नवरोपित बाग में लाइन से लाइन और पौध से पौध के बीच की खाली जगह में किसान सीजन के अनुसार सहफसल भी ले सकते हैं। मसलन शुरुआत के कुछ वर्षों में फूलगोभी, पत्तागोभी, मूली, गाजर, मेंथी, पालक, लतावर्गीय सब्जियां उगाई जा सकती हैं। जब पौधों की छांव अधिक होने लगे तो छायादार जगह में हल्दी, अदरक और सूरन की खेती भी कर सकते हैं। ऐसा करने से बागवानों की आय तो बढ़ेगी ही, सहफसल के लिए लगातार देखरेख से बाग का भी बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। कलांतर में इसका लाभ बेहतर फलत और फलों की गुणवत्ता के रूप में मिलेगा।

लीची को फलों की रानी भी कहते हैं। सुर्ख लाल रंग। रस इतना कि छिलका उतारने के साथ ही टपकने लगे। मिठास से भरी लीची को इन्हीं खूबियों के कारण फलों की रानी कहा जाता है। बाजार में आने पर भी लीची का जलवा रानी जैसा ही होता है। मात्र दो तीन हफ्ते के लिए लीची बाजार में आती है और छा जाती है।

मानिकपुर जंक्शन का उत्तर मध्य रेलवे के जीएम ने किया निरीक्षण

संवाददाता। प्रयागराज

महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे उपेंद्र चंद्र जोशी ने बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु बडोनी के साथ प्रयागराज मानिकपुर रेल खंड का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी ने निरीक्षण की शुरुआत प्रयागराज से मानिकपुर के मध्य विंडो ट्रेलिंग माध्यम से की। इस दौरान उन्होंने मार्ग में आने वाले रेल पथ एवं उसके पास के सभी इंस्टालेशन जैसे सिगनल ओएचई प्लेटफॉर्म पर सफाई इत्यादि का चलती हुई गाड़ी में लगे निरीक्षण यान की पिछली खिड़की से निरीक्षण किया। उन्होंने अन्य संरक्षा सम्बंधित कार्यों के साथ साथ राइडिंग गुणवत्ता विशेष तौर से प्वॉइंट एवं क्रॉसिंग पर ट्रैकज्योमेट्री इंडेक्स में सुधार ओएमएस औसिलेशन मोनिटरिंग सिस्टम विवरण ओएचई की स्थिति मार्ग के लेवल क्रॉसिंग गेटों की स्थिति पटरी के आस पास स्क्रैप की स्थिति साफ सफाई वायरिंग या लूज़ इंस्टालेशन मार्ग में आने वाले माइनर और मेजर ब्रिज के साथ साथ उक्त खंड में चल रहे आधारभूत संरचना कार्य का पिछली खिड़की से जायजा लिया। साथ ही सम्बंधित अधिकारियों को पूर्ण दक्षता एवं संरक्षा मानकों का पालन करते हुए शीघ्रता से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।

श्री जोशी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास हेतु चयनित मानिकपुर जंक्शन स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मण्डल रेल प्रबंधक हिमांशु बडोनी ने मानिकपुर स्टेशन के क्रमवार विकास की प्लानिंग के बारे में महाप्रबंधक को बताया। महाप्रबंधक ने स्टेशन का सघन निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों और उपलब्ध यात्री सुविधाओं का अवलोकन किया। जीएम एनसीआर ने लोको पायलट गार्ड रनिंग रूम का निरीक्षण किया। साथ ही उपलब्ध सुविधाओं और रनिंग रूम के रखरखाव को उत्कृष्ट रखने के निर्देश भी दिए।

केंद्र समन्वयकों की कार्यशाला में दूरस्थ शिक्षा की महत्ता बताएंगे कुलपति

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति प्रो सत्यकाम अपने चार दिवसीय दौरे में पूर्वांचल में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की स्थिति जानेंगे एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केंद्र समन्वयकों की कार्यशाला में समर्थ पोर्टल के माध्यम से आधिकाधिक प्रवेश किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्स देंगे। साथ ही विश्वविद्यालय के लोकप्रिय कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना इस कार्यशाला का उद्देश्य रहेगा। मुक्त विश्वविद्यालय ने प्रवेश सत्र 2024 25 की प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से संचालित की है। मुक्त विश्वविद्यालय के लिए यह एकदम नया अनुभव है। प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में फैले अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों के सामने आ रही कठिनाइयों से निजात दिलाने के लिए कुलपति प्रो सत्यकाम ने पूर्वांचल के चार प्रमुख क्षेत्रीय केन्द्रों वाराणसी आजमगढ़ गोरखपुर और अयोध्या में नामांकन अभिप्रेरण एवं प्रतिपुष्टि फीडबैक कार्यशाला का आयोजन करके समन्वयकों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। कार्यशाला के माध्यम से समन्वयकों को समर्थ पोर्टल से प्रवेश की जानकारी वित्तीय परामर्श परीक्षा में गुणवत्ता समय पर काउंसलिंग आदि के संबंध में विशेष जानकारी प्रदान की जाएगी। समन्वयकों से प्राप्त फीडबैक के माध्यम से विश्वविद्यालय इस बार प्रवेश के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने में सफल रहेगा। विश्वविद्यालय के जन संपर्क अधिकारी डॉ प्रभात चन्द्र मिश्र ने बताया कि अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य एवं समन्वयकों की कार्यशाला का शुभारंभ 19 जुलाई को वाराणसी से होगा। वाराणसी में 19 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे स्वामी अतुलानंद कॉन्वेंट कॉलेज कोईराजपुर तरनापुर वाराणसी में इसका आयोजन होगा। इसी क्रम में 20 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे आजमगढ़ के पूर्वांचल पीजी कॉलेज रानी की सराय में प्राचार्य एवं समन्वयकों की कार्यशाला होगी।

33वें अंतरराज्यीय स्वास्थ्य मेले का जिलाधिकारी ने किया शुभारम्भ

संवाददाता। सोनभद्र

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बुधवार को 33 वां अंतर्राज्यीय स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किये, 17 जुलाई से 21 जुलाई 2024 तक चलने वाले स्वास्थ्य मेले का सुरभि शोध संस्थान श्री तपोवन गौशाला हिनौता अहरौरा स्थल पर किया। जिसके सयोजक डॉक्टर एस0 एन0 राय डॉक्टर रामानंद तिवारी व कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सत्य नारायण संखवार निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान मुख्य वक्ता भारत भूषण अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख, रमेश जी प्रान्त प्रचारक काशी प्रान्त कार्यक्रम में सम्मिलित रहे।

इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित जनों को सम्बोधित करते हुए कहा की स्वास्थ्य मेला में विभिन्न स्थलों पर कुल 75 कैंपों में 300 से अधिक चिकित्सकों ने अपनी सेवा चार प्रमुख केंद्रों जैसे सुरभि शोध संस्थान और संस्थान हिनौता अहरौरा राबर्ट्सगंज खन्ना कैंप डाला सेवा समर्पण संस्थान कॉरिडार चपकी से विभिन्न गांवों तक छोटे छोटे कैंपों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य जागरूकता एवं औषधि वितरण किया जाएगा जिसमें 50000 वनवासी एवं अन्य परंपरागत वनवासियों को आरोग्य बनाने की योजना है। कार्यक्रम विश्व आयुर्वेद परिषद सुरभि शोध संस्थान सेवा समर्पण संस्थान संजीवनी वेलफेयर सोसायटी उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग मिर्जापुर सोनभद्र चंदौली एवं जिला प्रशासन सोनभद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है।

पर्यावरण के लिए पूरे क्षेत्र में 25000 से अधिक पौधरोपण होना सुनिश्चित किया गया है, उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनुराग पाठक एवं धन्यवाद ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार द्वारा किया गया।

150 किग्रा गांजे के साथ दो तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यायल कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर डॉ0 चारू द्विवेदी के पर्यवेक्षण में बुधवार को थाना रॉबर्ट्सगंज व एसओजी सर्विलांस टीम द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 12.44 बजे थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर राधे कृष्ण ढाबा हिन्दुआरी के पास से 1 ट्रक संख्या डब्ल्यू बी 39 बी 0434 के डाला में तिरपाल के नीचे छिपाकर उड़ीसा प्रान्त से गांजा लोड करके रॉबर्ट्सगंज के रास्ते मीरजापुर ले जा रहे 150 किग्रा अवैध गांजा जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये के साथ 2 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करों चंद्रेश उर्फ बब्बू यादव पुत्र लल्लन यादव निवासी ग्राम देवरी थाना पड़री जिला मिर्जापुर व टहल सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी ग्राम पकीवा थाना कलानौर जिला गुरुदासपुर पंजाब वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया जबकि अन्य दो वांछित अभियुक्त अभय मालवीय पुत्र रामदश मालवीय निवासी ग्राम तीता बरयां थाना हलिया जनपद मीरजापुर व रामदश मालवीय निवासी ग्राम तीता बरयां थाना हलिया जनपद मीरजापुर की गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रयासरत है। बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि गाड़ी में लदा माल रामदरश मालवीय व उनके पुत्र अभय मालवीय निवासी ग्राम तीता बरयां थाना हलिया जनपद मीरजापुर का है। जिसे लेने के लिए हम सभी लोग उड़िसा गये थे जहां से 90 हजार रुपये के किराये पर इस ट्रक में गांजा भरकर रामदरश व अभय मालवीय वापस चले आये। हम दोनों पुलिस से बचते बचाते माल लेकर मीरजापुर उनके पास ले जा रहे थे।

आश्वासन पर समय बिता रही है सरकार: रामराज गोंड

- उम्भा नरसंहार की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि

संवाददाता। सोनभद्र

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामराज सिंह गोड के नेतृत्व में उम्भा नरसंहार में मृत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पीड़ित परिवार के साथ जाने की तैयारी में थे लेकिन एसडीएम घोरावल राजेश सिंह व सी0ओ0 राहुल पांडे के साथ प्रशासन ने स्थल तक जाने से रोक दिया स्थानीय लोग घटनास्थल पर जाने की जिद की कुछ दूर तक आगे भी बढ़े लेकिन प्रशासन ने उन्हें घटनास्थल तक पहुंचने सें रोक दिया।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामराज सिंह गोंड ने उप जिलाधिकारी से कहा कि घटना को 5 वर्ष पूर्ण हो गए लेकिन आज तक सरकार के द्वारा कही गई बातें पूर्ण नहीं की गई, जहां 7:50 बीघा जमीन देने की बात सभी को की गई थी उसमें भी किसी को दो बीघा किसी को साढे तीन बीघा, किसी को चार बीघा करके जमीन दिया गया, गांव में अभी तक मोबाइल टावर नहीं लग पाया नेटवर्क की समस्या है, बिजली का कनेक्शन भी नहीं हो पाया है, आश्रम पद्धति से बन रहा विद्यालय चार वर्ष से बन रहा है अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, केवल आश्वासन पर सरकार समय बिता रही है 10 सूत्री मांगों को उन्होंने उप जिलाधिकारी को दिया, सांसद छोटेलाल खरवार नें कहाकि आदिवासियों का हक उन्हें मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि पीड़ित का जो भी अधिकार है उसकी बात जिलाधिकारी एवं शासन से भी करेंगे घटनास्थल पर शहीद स्मारक बनाने की बात आदिवासियों ने की उस पर भी उन्होंने विचार करने की बात कही। शहर अध्यक्ष राजू त्रिपाठी ने कहाकि इस घटना के बाद आदिवासियों की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और उसकी लड़ाई लड़ी और उनका अधिकार दिलाने का काम भी किया लेकिन वर्तमान सरकार ने वायदे पूरें नही किए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य आशुतोष कुमार दुबे आशु ने कहा कि यहां घटना होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश रही प्रियंका गांधी ने लड़ाई लड़ने का काम किया प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार भी किया लेकिन सरकार ने जो वायदे किए उस पर वह अभी तक खरी नहीं उतर पाई है।

इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव सुनील गौड संजय यादव, त्रिपुरारी गोड़ राजबली पांडेय रामबली सीता अनीता संतलाल के साथ सैकड़ो लोग उपस्थित रहे।

क्विक न्यूज

सपा के राष्ट्रीय सचिव बने पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा

सोनभद्र। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रॉबर्ट्सगंज के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। जिससे समर्थकों एवं शुभ चिंतकों ने हर्ष जाहिर करते हुए कहा कि इससे सपा मजबूत होगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सबसे पहले वर्ष 2012 में रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र से युवा प्रत्याशी के ऊपर भरोसा जताते हुए अविनाश कुशवाहा को टिकट दिया था, जिस पर विजय हासिल कर अविनाश कुशवाहा विधायक चुने गए। उसके बाद विधायक के साथ ही सोनभद्र जिले का जिलाध्यक्ष भी बना दिया गया। अपने कुशल नेतृत्व एवं व्यवहार की वजह से अखिलेश यादव के करीबी बन गए। इसी का नतीजा रहा कि इन्हें सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया। अबकी बार 17 जुलाई 2024 को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा का कद बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। जिससे समर्थकों एवं शुभ चिंतकों ने हर्ष जाहिर करते हुए कहा कि इससे सपा को मजबूती मिलेगी।

कला को संरक्षित रखने की दिशा में हैं प्रतिबद्ध

प्रयागराज। गैर लाभ संगठन देधिया म्युज़िक फाउन्डेशन जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संरक्षण के लिए समर्पित है इसके द्वारा युवा सर सरताज 2024 की घोषणा की गई है। यह ज़ायकस के सीईओ आतिश देधिया द्वारा स्थापित किया गया है। अपनी तरह की अनूठी यह टेलेंट हंट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान करेगी। इसका उद्देश्य उभरते हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों को उचित मार्गदर्शन तथा विकास के लिए मंच प्रदान करना और उन्हें पहचान देना है। इस अवसर पर देधिया म्युज़िक फाउन्डेशन के संस्थापक आतिश देधिया ने कहा आज के दौर में ज़्यादातर प्रतिभा पश्चिमी संगीत पर ही ध्यान केन्द्रित करती है। देधिया म्युज़िक फाउन्डेशन में हम युवाओं में देश के समृद्ध संगीत की धरोहर को बढ़ावा देना चाहते हैं। युवा सर सरताज के माध्यम से हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सौंदर्य को बरक़रार रखने और युवाओं को इस कला के प्रति समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कौशिकी चक्रवर्ती राहुल देशपाण्डे संजीव अभयंकर जजों के पैनल में शामिल होंगे। वास्तव में चुने गए प्रतिभागियों को उचित सहयोग मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। अपने प्रयासों के माध्यम से देधिया म्युज़िक फाउन्डेशन भारत में संगीत की समृद्ध धरोहर को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस कला को संरक्षित रखने की दिशा में प्रतिबद्ध है।

एसपी ने जनसुनवाई आसान बनाने को जारी की नई गाइडलाइन

गाजीपुर। जनसुनवाई को आसान एवं पारदर्शी बनाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा आवेदक पर्ची में बदलाव किये गये हैं। अब यह आवेदक पर्ची तीन प्रारूपों में रहेगी प्रथम पर्ची पुलिस कार्यालय रिकार्ड के लिये, द्वितीय पर्ची- सम्बन्धित थाना कार्यालय व तृतीय पर्ची- आवेदक को दी जायेगी। आवेदक को दी जाने वाली पर्ची रिसिविंग के रूप में मौजूद रहेगी। प्रत्येक पर्ची पर यह विवरण अंकित है कि किसी शिकायत का 10 दिवस में निस्तारण न होने पर प्रत्येक कार्य दिवस में समय प्रात: 10 बजे से 17 बजे के मध्य रिसिविंग पर्ची पर अंकित मोबाइल नं0 7839864009 पर सम्पर्क कर या पुलिस कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी शिकायत के निस्तारण एवं की गयी कार्यवाही के बारे में विस्तार से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल से आमजनमानस को आश्वस्त किया जा रहा है कि उनकी शिकायतों का निस्तारण समयवद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जायेगा।

डर और तनाव की वजह से हो रही कैंसर जैसी घातक बीमारी: डॉ अजय सोनकर

संवाददाता। प्रयागराज

आज हर इंसान डरा हुआ है डर की वजह से तनाव हो रहा है वहीं डर और तनाव की वजह से ही इंसान कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में आ रहा है। महंगा इलाज करा रहे हैं। पाखंडी और ढोंगी बाबाओं की शरण में जा रहे हैं। पद्मश्री वैज्ञानिक डॉ अजय सोनकर ने मनुष्यों में होने वाली बीमारियों पर कई साल अध्ययन करने के बाद यह बातें कही हैं। डॉ अजय सोनकर ने बताया कि जब कोई व्यक्ति तनाव में आता है तो शरीर की रक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया देती है। जिसके तहत एड्रनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल हॉर्मोन उत्पन्न होता है। यह पाचन तंत्र प्रजनन अंग पैन्क्रियाज जैसे तमाम अंगों को अस्थाई रूप से निष्क्रिय करके खून में सामान्य से कई गुना अधिक ग्लूकोज संग्रहित कर देता है। शरीर को ग्लूकोज का उपयोग करने के लिए उसी अनुपात में कई गुना ज्यादा आक्सीजन की जरूरत होती है। आक्सीजन एरोबिक व्यायाम से ही मिल सकता है। इसके लिए कड़ा श्रम या दौड़ना जरूरी है। आज की विकृत जीनवशैली में इंसानों से यही नहीं हो पा रहा है। डा सोनकर के मुताबिक खून में बढ़ा ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो पाता और इससे वसा की मात्रा बढ़ जाती है। यही हृदय रोग की बीमारी का कारण बनता होता है। पैन्क्रियाज के बीटा कोशिकाओं पर क्षमता से कहीं अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

जिसके कारण वह ठीक से काम नहीं कर पाटी और व्यक्ति को मधुमेह जैसी बीमारी भी जकड़ने लगती है। शरीर में आक्सीजन की कमी हो जाने के कारण नान सेलुलर नामक परिस्थिति उत्पन्न होती है। जिसके कारण कोशिका में मौजूद ग्लूकोज फरमेंट हो जाती है। ऐसी कोशिकाओं का आवरण शख्त हो जाता है। ऐसी कोशिकाओं में आक्सीजन जा सकता है न अपव्ययी पदार्थ बाहर निकल सकता है। ऐसी कोशिकाओं को ही मैलिग्नेंट या कैंसर का सेल कहा जाता है। अल्पकालिक दीर्घकालिक तनाव और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के लिए डॉ अजय आज की व्यवस्था को दोषी मानते हुए कहते हैं कि जीवन में असुरक्षा और डर के साये में जीने की सभी की आदत हो गई है। उत्पाद का प्रचार और सनसनीखेज समाचार भी लोगों में डर पैदा कर रहे हैं।

सरकार लोगों के लिए अस्पताल बना रही। इसी डर और भय का लाभ ढोंगी बाबा ले रहे हैं। लोग सुखद जीवन की आस में ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं। इसी डर और तनाव से मुक्ति पाने के लिए पिछले दिनों हाथरस में जबर्दस्त भीड़ एकत्र हुई जिसमें भगदड़ मची और 121 लोगों की जान चली गई।

संगीत की उत्कृष्टता बिखेरेगी अपनी चमक

प्रयागराज। जाना माना सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा एक ताजातरीन नए सीज़न के साथ वापस लौट रहा है। जी टीवी का यह शो पिछले साल के सफल सीज़न में हर हफ्ते टैलेंटेड सिंगर्स को ज़ी म्यूजिक कंपनी पर अपने ओरिजिनल सिंगल्स रिलीज करने का मौका देकर उन्हें सिंगिंग सेंसेशंस बनाने के बाद यह शो अब एक नए रोमांचक फॉर्मेट में लौट रहा है। इस बार कंटेस्टेंटस को उनके मेंटर्स अच्छी तरह से ग्रूम करेंगे और अपने शिष्यों के म्यूजिकल सफर में पूरी लगन से शामिल रहेंगे। जहां संगीत जगत के सबसे बड़े कंपोजर्स इस प्रतिस्पर्धी माहौल में एक दूसरे के आमने सामने नजर आएंगे।सारेगामापा का प्रीमियर जल्द ही ज़ी टीवी पर होने जा रहा है। सारेगामापा दो हजार चौबीस के ऑन ग्राउंड ऑडिशन की शुरुआत 18 जुलाई से नवाबों के शहर लखनऊ में हो रही है। समय सुबह नौ बजे से स्थान द मिलेनियम स्कूल रायबरेली रोड एफ ब्लॉक साउथ सिटी लखनऊ में होगा।

मुहर्रम को लेकर पूरी तरह सतर्क रहा पुलिस प्रशासन

सकलडीहा, चन्दौली। महर्रम की त्योहार को लेकर एसडीएम अनुपम मिश्रा और सीओ रघुराज पुलिस फोर्स के साथ पूरे दिन अलर्ट रहे। केातवाली अंतगत कुल 31 ताजिया स्थापित किया गया था। बुधवार को देर शाम को ताजियादारों ने सकुशल ताजिया को कर्बला तक लेकर मसीहा पढ़ते हुए गये। इस दौरान ताजियादारो ने विभिन्न प्रकार के लकड़ी खेल का कला कौशल का प्रदर्शन किया।

सकलडीहा में मुहर्रम पर हिन्दु मुस्लीम भाईचारा का मिशाल देखने को मिलता है। कस्बा सहित कोतवाली अंतर्गत कुल 31 ताजिये बैठाये गये थे। सकलडीहा कस्बा में दस ताजिया विभिन्न प्रकार की नकासीदार ताजिया बनाया गया था। जिसमें छोटी मस्जिद के पास तिरंगादार ताजिया बनाया गया था। शाम पांच बजे से कस्बा में ताजिया पूरे कस्बा भ्रमण करते हुए कर्बला तक पहुंची। इस दौरान विभिन्न प्रकार के कलाबाजी का प्रदर्शन व मसीहा पढ़ते हुए मुस्लिम बंधु कर्बला तक पहुंचे। मुहर्रम को लेकर एसडीएम सीओ और कोतवाल संजय कुमार सिंह पूरे दिन पुलिस फोर्स के साथ चक्रमण करते रहे। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि राजेश सेठ, डा. अकबर, रोजन अली, इकराम, अमानत, नासिर, विवेक जायसवाल, सुरेन्द्र यादव सहित अन्य रहे।

बिजली विभाग में घोटाले का मामला सदन में उठाएंगे सांसद सनातन पांडेय

- मीटर रीडरों के लंबित वेतन और बकाया ईपीएफ पर सपा सांसद का बड़ा खुलासा
- अधिकृत कंपनियां प्रदेश में मीटर रीडरों का अरबों रुपया बकाया लगाकर भाग गईं
- गाजीपुर में ही तीन सौ मीटर रीडर हैं प्रभावित

संवाददाता। गाजीपुर

बिजली विभाग में जहां विद्युत कर्मी परेशान हैं और आए दिन जिले के सबसे बड़े विद्युत अधिकारी अधीक्षण अभियंता का घेराव और प्रदर्शन कर रहे हैं, कारण है कि बिजली विभाग ने सरकारी कर्मियों की जगह अब प्राइवेट कंपनियों के जरिए आउट सोर्स कर्मियों से बिजली उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग का कार्य करा रही है और कमीशन बेसिस पर काम करने वाली तीन तीन कंपनिया इन मीटर रीडरों का करोड़ों रुपया वेतन और ईपीएफ के साथ कंपनियों द्वारा 15 हजार रुपया प्रत्येक कर्मियों से सिक्यूरिटी का डिपॉजिट कराया गया था।

वो लेकर एक नहीं तीन तीन कंपनियां जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से अधिकृत हैं वो भाग गई हैं अब कर्मचारियों के सामने विभाग ने एक चौथी नई कंपनी लाकर खड़ी कर दी है, जो पहले से तय मानदेय से भी कम मानदेय पर इनसे काम कराना चाहती है और पुराने बकाए की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, ऐसा आरोप धरना प्रदर्शन कर रहे आउट सोर्स कर्मी कर रहे हैं। विभाग के अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि करदायी संस्थाएं इनका पेमेंट बाकी लगाकर भाग गई हैं। अब बलिया लोकसभा सीट से सपा सांसद सनातन पांडेय जी को भी मीटर रीडरो ने पत्रक दिया जिसमें सांसद सामने आए हैं और बिजली विभाग के इन कर्मियों की समस्याओं के लिए सदन में इस बाबत प्रश्न उठाने की बात कहे हैं। एक आंकड़े पर गौर करें तो सिर्फ गाजीपुर जनपद में जहां सात तहसीलें हैं वहां लगभग तीन सौ मीटर रीडर सेवा प्रदाता कंपनियों के जरिए सरकारी काम कर रहे हैं और यूपी के कुल 75 जिलों में देखा जाए तो इनकी संख्या लगभग 22 हजार कर्मियों से ज्यादा होगी।

ऐसे में आरोप है कि विभाग के उच्चाधिकारियों से मिलकर ये सेवा प्रदाता कंपनियां हर जिले और डिविजन में कर्मियों का मोटा वेतन बकाया लगाकर अपना भुगतान लेकर चंपत हो गई हैं, अब विभाग इस बात से पल्ला झाड़कर चाहता है कि परेशान और आर्थिक रूप से कमजोर बिजली कर्मी अपनी लड़ाई खुद लड़ें, लेकिन जनप्रतिनिधि और सांसद अब इन कर्मियों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ने की बात कह रहे हैं।

भस्सी डालकर जलभराव से राहगीरों व ताजियादारों को मिली राहत

सकलडीहा, चन्दौली। सकलडीहा इंटर कॉलेज से लेकर कस्बा में जलभरॉव व जर्जर सड़क से राहगीरों व पटरी दुकानदारों को काफी समस्या होती है। सकलडीहा ग्राम सभा की ओर से नागेपुर स्थित इंटर कॉलेज गेट से लेकर सकलडीहा कस्बा में जगह जगह भस्सी डलवाया गया। इससे पटरी दुकानदार राहगीर सहित ताजियादारों को काफी सहुलियत मिली है। सकलडीहा ग्राम सभा की ओर से किया गया पहल चर्चा का विषय बना हुआ है। लम्बे समय से सकलडीहा इंटर कॉलेज गेट से लेकर सकलडीहा कस्बा में जगह जगह सड़क गड्ढें में तब्दील होगया था। जिसके कारण बरसात होने पर जगह जगह जलभरॉव हो जाने से राहगीरों को काफी परेशानी होती थी। इसके साथ ही मुहर्रम को लेकर ताजियादारों को भी समस्या हो रहा था। ग्राम सभा सकलडीहा की ओर से नागेपुर स्थित सकलडीहा इंटर कॉलेज गेट से कस्बा में जगह जगह भस्सी गिराकर जेसीबी से पटवाया गया। ग्राम सभा सकलडीहा की ओर से किया गया पहल ताजियादारों के साथ राहगीर और पटरी व्यवसाईयों को काफी सहुलियत और चर्चा का विषय बना हुआ है।

संचारी अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित, पैसे की हो रही बन्दर बांट

मीरज़ापुर। जिले में इस समय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार संचारी अभियान का संचालन किया जा रहा है और संचारी अभियान के तहत दस्तक अभियान को भी चलाया जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारी व कर्मचारी केवल कागजों को पूरा करके उच्चाधिकारियों सामने प्रेषित करने का कार्य कर रहे है और पहला स्थान पाने का प्रयास कर रहे है। लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नही किया जा रहा है। दस्तक अभियान के बीते अभी सातदिन होगये है लेकिन विभाग के आशाओं द्वारा न नगर व ग्रामीण इलाको दस्तक देना उचित नही समझा है और कागजों की खाना पूर्ति करके अधिकारियों के सामने पेश कर दिया जा रहा है। सत्ताइस लाख की आबादी वाले जिले में केवल एक गाड़ी व भी आफिस टाइम में शहर में कचहरी से लेकर स्टेशन तक आसानी से देखा जा सकता है यह सिर्फ खाना पूर्ति करने का कार्य किया जा रहा है यह लापरवाही यही तक नही गांवो व शहर के एन्टीलार्वा का भी छिड़काव नही किया जा रहा है। इसका एक मात्र कारण है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में दौरा नही किया जा रहा है और न ही मानीटरिंग की जा रही है। छिड़काव न होनेवाले में विकास खण्ड के तीन दर्जन से अधिक गांव मड़िहान के सुगांपाख व हिनौता गांव में पिछले तीन अभियान से आशाको तो छोड़े विभाग के अधिकारी भी जाना उचित नही समझे। इसे यह साबित हो रहा है कि विभाग के अधिकारी प्रोगाम को लेकर किस तरह सक्रिय है। इस समय विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सीएमओ आफिस मीरजापुर के अधिकांश कर्मचारी व अधिकारी इलाहाबाद जिले के है जो छुट्टी के दिनों में मुख्यालय छोड़कर अपने-अपने घरों में मौज मस्ती में लग जाते है जिससे विभाग के तमाम प्रोग्राम अधर में है जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है अगर यही हालत रही तो आने वाले कुछ दिनों में डेगू के मरीजों से चिकित्सालय पट जायेंगे। जागरूकता के कार्य में लगी फेमिली हेल्थ इण्डिया के कर्मचारी का दावा है कि आने वाले दिनों में किस विकास खण्ड में डेगू के मरीजों की आने की आशंका है इसका यह सबसे बड़ा कारण है कि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा न छिड़काव व जागरूकता ही है।

जम्मू कश्मीर

आतंकी हमले

जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जारी हैं जिनमें लोगों की जानें गई हैं। जम्मू कश्मीर में हुई एक और त्रासद घटना में सुरक्षा बलों के चार जवान शहीद हुए हैं। एक मेजर समेत भारतीय सेना के चार सैनिक डोडा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ करते समय शहीद हुए। इस घटना से सुरक्षा बलों के समक्ष उपस्थित चुनौतियां उजागर होती हैं तथा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के बारे में सरोकार गहरे होते हैं। व्यवस्था में सुधार के दावों के बावजूद आतंकी हमलों की बारंबारता और तीव्रता बढ़ रही है। सुरक्षा बलों में हताहतों की संख्या अलग-थलग घटनाओं के परिणामस्वरूप न होकर हिंसा के एक व्यापक पैटर्न का संकेत है। आतंकी घटनाओं व लक्षित हत्याओं का जम्मू में केन्द्रित होना एक महत्वपूर्ण व चिन्ताजनक बदलाव है, जबकि यह दो दशकों से शांत था। 2021 में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद जम्मू में आतंकी हमलों और लक्षित हत्याओं में चिन्ताजनक उभार आया है। इसके कारण हिंसा खतरनाक स्तर तक बढ़ी है जिससे क्षेत्र में अस्थिरता की आशंका है। संभवत: कश्मीर में प्रभावी 'आतंकवाद-विरोधी रणनीतियां' जम्मू के विशिष्ट और सामाजिक परिदृश्य के अनुकूल न हों। हालांकि, अतीत की रणनीतियों से प्राप्त सबकों से कुछ दिशा मिल सकती है, पर जम्मू में आतंक की नई लहर से निपटने के लिए नए आतंकवाद-विरोधी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय रूप से कश्मीर में पत्थरबाजी और सामाजिक अशांति में परिवर्तन आया है, पर उग्रवाद बना हुआ है और सक्रिय उग्रवादी समूहों ने अब जम्मू क्षेत्र को निशाना बनाना शुरू किया है। इन समूहों को

अक्सर सीमापार से समर्थन मिलता है जिससे सुरक्षा परिदृश्य जटिल होता है। उग्रवाद को कुचलने के लिए अनेक सैनिक कार्रवाइयों के बावजूद इन समूहों की मजबूती एक बड़ी बाधा है। जम्मू कश्मीर में सामाजिक-राजनीतिक परिवेश भी हिंसा भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐतिहासिक कठिनाइयों, राजनीतिक हाशियाकरण तथा सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां उग्रवाद के लिए उपजाऊ जमीन उपलब्ध कराती हैं। हाशियाकृत अनुभव होने के बाद अनेक स्थानीय नौजवान हिंसा के दुष्चक्र में फंस जाते हैं जिससे सुरक्षा बलों के लिए स्थिति और जटिल हो जाती है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना टकराव के किसी दीर्घकालीन समाधान के लिए जरूरी है। सुरक्षा बलों में हताहतों की संख्या बढ़ने से वर्तमान रणनीतियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं और आतंकवाद-विरोधी तथा आंतरिक सुरक्षा दृष्टिकोण के पुन: मूल्यांकन की आवश्यकता उजागर होती है। हालांकि, अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद की गई उम्मीद पूरी तरह सफल नहीं हुई है। इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। इसमें जीवन्त सुरक्षा उपायों के साथ ही राजनीतिक संवाद तथा समुदाय की सहभागिता के प्रयास भी शामिल होने चाहिए। यह तथ्य भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि हालिया लोकसभा चुनाव में तीन-चार दशक बाद जनता की भारी सहभागिता देख कर आतंकियों, चरमपंथियों व उनके समर्थकों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। जम्मू कश्मीर में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे तत्व जनता को डरा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संकट में डालना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने ऐसे 'स्थानीय तत्वों' की ओर संकेत किया है जो आतंकी तत्वों को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक रूप से ऐसे तत्वों पर लगाम लगाना भी जम्मू कश्मीर में शांति के लिए जरूरी हो गया है।

उपचुनाव नतीजों के संकेत

उपचुनाव नतीजों के अनेक संकेत हैं। विपक्ष के अनुसार इनसे सरकार के स्थायित्व पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि भाजपा आंतरिक व बाहरी दबावों का सामना कर रही है।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

उपचुनाव नतीजों के अनेक संकेत हैं। विपक्ष के अनुसार इनसे सरकार के स्थायित्व पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि गठबंधन बनाए रखने के लिए भाजपा को आंतरिक व बाहरी दबावों का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में हुई 13 सीटों के उप-चुनाव परिणामों से प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बारे में मतदाताओं की राय समझने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लगातार तीसरा कार्यकाल मिल गया। लेकिन आम चुनाव के एक महीने बाद हुए 13 सीटों के उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' को 10 सीटों पर विजय मिली। इससे देश में राजनीतिक उथलपुथल पैदा हुई है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, 'इंडिया' समूह को मिले इन सकारात्मक परिणामों से सत्तारूढ़ गठबंधन की सत्ता पर पकड़ प्रभावित हो सकती है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सफलता मिली, पर वह बहुमत के 272 के आंकड़े से पीछे रह गई।

इसके परिणामस्वरूप उसे 'राजग' सहयोगियों के समर्थन पर निर्भर होना पड़ा। आशंका है कि इन स्थितियों में गठबंधन सहयोगी सरकार के नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करेंगे तथा इसके कारण गठबंधन बनाए रखने के लिए भाजपा को समझौते करने पड़ सकते हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ गठबंधन में किसी अनिश्चितता की स्थिति या उसकी संभावना में विपक्षी दलों की हिम्मत बढ़ सकती है। पिछले महीने हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा 240 सीटें ही प्राप्त कर सकी और इस प्रकार वह अपने दम पर 272 के बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। ऐसे में भाजपा को अपने 'राजग' सहयोगियों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस निर्भरता के कारण भाजपा के उन नीतिगत निर्णयों पर प्रभाव पड़ सकता है जिनकी रूपरेखा उसने चुनाव के पहले ही तैयार कर ली थी। गठबंधन सहयोगियों पर निर्भरता के कारण भाजपा को उन खास मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालना पड़ सकता है जो उसकी पहचान माने जाते थे। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं तथा कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में सरकार के स्थायित्व पर भी संदेह के बादल मंडरा सकते हैं। संख्याबल के इस नाजुक संतुलन में विपक्ष संतुलन बिगाड़ने के प्रयास कर सकता है। उसका इरादा सत्तारूढ़ गठबंधन में असहज स्थितियां पैदा करने का है ताकि इसकी स्थिरता पर संदेह पैदा हो जाए। विधायिका में सीट खाली होने पर भारत का निर्वाचन आयोग स्वत: उप-चुनाव की घोषणा कर देता है। विधायिका में सीट खाली होने के अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें निर्वाचित विधि-निर्माता की मृत्यु, इस्तीफा, अयोग्यता या उसकी सदस्यता समाप्त होना शामिल हैं।

संसद के किसी सदस्य की मृत्यु या उसके इस्तीफे की स्थिति में भी उपचुनाव होते हैं। इस स्थिति में केवल उस खाली सीट के मतदाता ही वोट दे सकते हैं। पिछले बुधवार को सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव हुए थे। इनमें पंजाब की एक, हिमाचल प्रदेश की तीन, उत्तराखंड की दो, पश्चिम बंगाल की चार तथा मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु की एक-एक विधानसभा सीटें शामिल थीं। इन उपचुनावों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस-टीएमस, आम आदमी पार्टी-आप तथा द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम-द्रमुक, आदि ने अपने उम्मीदवार उतारे थे ताकि वे इन क्षेत्रों में अपनी शक्ति का परीक्षण कर सकें। इन उपचुनावों में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' को मिली व्यापक सफलता से विपक्ष के हौसले में काफी वृद्धि हुई है। ये उपचुनाव 'इंडिया' समूह के लिए काफी महत्वपूर्ण और इसका एक प्रकार से परीक्षण थे क्योंकि लोकसभा चुनाव, 2024 के बाद वह पहली बार भारतीय जनता पार्टी-भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग का चुनाव मैदान में सामना करने जा रहा था। इन उपचुनावों में विपक्ष के क्षेत्रीय कद्दावर नेताओं का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। 'इंडिया' समूह की एक प्रमुख पार्टी तृणमूल कांग्रेस-टीएमसी ने बंगाल की सभी चारों सीटों पर विजय प्राप्त की। उसकी यह विजय महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उत्साह से भरी कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दो-दो सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की। इससे कांग्रेस की शक्ति इन राज्यों में और बढ़ गई है।

द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम-द्रमुक ने तमिलनाडु में एक सीट जीती। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी-आप को जालंधर पश्चिम की सीट पर विजय मिली। इन विविधतापूर्ण नतीजों से वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अनिश्चितता की भावना बढ़ सकती है। इसके साथ ही भाजपा द्वारा केवल दो सीटें जीतने तथा बिहार में एक निर्दलीय के चुनाव जीतने से उपचुनाव परिणामों की जटिलता और बढ़ जाती है। यह आमतौर से माना जाता है कि उपचुनावों में राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी को सफलता मिलती है। इसे देखते हुए टीएमसी, द्रमुक, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी-आप की अपने सत्तारूढ़ राज्यों में विजय इनका उन राज्यों पर लगातार जारी नियंत्रण समझा जा सकता है।

टीएमसी के लिए ये उपचुनाव परिणाम बहुत उत्साहवर्धक थे क्योंकि केवल एक महीने पहले उसने पश्चिम बंगाल में 29 संसदीय सीटों पर विजय पाई थी, जबकि 2029 में इनकी संख्या 22 थी। लेकिन उत्तराखंड और बिहार में चीजें अलग थीं। यहां सत्तारूढ़ भाजपा और जदयू के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में हुए तीन उप-चुनावों में से दो पर विजय मिली है। परिणामों के बाद 68 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में कांग्रेस की संख्या फिर बढ़ कर 40 हो गई है। इससे हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू क नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार स्थिर हो गई है। उपचुनाव राजनीतिक पार्टियों और उनकी लोकप्रियता का महत्वपूर्ण परीक्षण होते हैं। इनके माध्यम से पार्टियां अपने समर्थन आधार तथा जनता की भावनाओं का पता लगाती है। अक्सर वे अपनी अभियान रणनीतियों की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए उपचुनावों का प्रयोग करती हैं। इसका प्रभाव भावी चुनावों पर पड़ता है। यदि सत्तारूढ़ पार्टी उपचुनाव में कोई सीट जीतती है तो इससे उसकी सीटों की कुल संख्या बढ़ सकती है जिसका प्रभाव सरकार के स्थायित्व तथा उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ सकता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो भाजपा को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है, हालांकि वह लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के कारणों की लगातार जांच भी कर रही है। हार के उभरते कारणों और मीडिया में आने वाली खबरों से लगता है कि भाजपा के भीतर वर्तमान रणनीतियों पर सवाल उठ रहे हैं तथा संभवत: कुछ नेताओं के बीच इसके कारण तनाव है।

मीडिया में आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि संभवत: आरएसएस और भाजपा के बीच तनाव है। इससे पार्टी को आरएसएस का समर्थन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही भाजपा के भीतर और बाहर से पैदा दबावों के कारण सत्तारूढ़ गठबंधन में भी तनाव व अनिश्चितता का माहौल पैदा हो सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 'इंडिया' समूह के मजबूत प्रदर्शन से लगता है कि देश में राजनीतिक गत्यात्मकता बदल रही है। उल्लेखनीय है कि मतभेदों के बावजूद विपक्षी दलों के एकजुट होकर काम करने से उनको सफलता मिली है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि दोनों तत्वों के कारण वे सफल हुए हैं।

विपक्ष के राजनीतिक रूप से मजबूत होने के कारण सत्तारूढ़ गठबंधन कमजोर हो सकता है जिससे विपक्ष की स्थिति और मजबूत होगी। हालांकि, वर्तमान समय में भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, पर जीतना और हारना लोकतंत्र का अंग हैं। उपचुनावों के परिणामों का प्रभाव इस वर्ष के अंत में होने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों में खासतौर से दिख सकता है। 'इंडिया' समूह द्वारा उपचुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन से आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्ष की स्थिति और मजबूत हो सकती है। इन विधानसभा चुनावों से तय होगा कि विपक्ष को शक्ति मिलती है, अथवा वह कमजोर होता है। ार बन जाता।

पर्यटन उद्योग के समक्ष चुनौतियां और भविष्य

जैसे-जैसे केंद्रीय बजट 2024 नजदीक आ रहा है, भारतीय पर्यटन उद्योग को समर्थन और रणनीतिक पहलों में वृद्धि की बड़ी उम्मीदें हैं।

दिव्या भाटिया
(लेखक, स्तम्भकार हैं)

पर्यटन हमेशा से दुनिया भर के देशों की आर्थिक वृद्धि और जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है, और भारत इसका अपवाद नहीं है। भारतीय पर्यटन ने लगातार उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है, भले ही यह सरकारी नीतियों का प्राथमिक फोकस नहीं रहा हो। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार हुए हैं, लेकिन ये प्रयास सीमित रहे हैं। भारतीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को कोविड-19 महामारी के दौरान अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की यात्राओं में तेज गिरावट के कारण महत्वपूर्ण गिरावट आई। इन चुनौतियों के बावजूद, उद्योग ने 2023 में सुधार के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार, 2023 में 152 मिलियन घरेलू यात्री आए, जो 2022 के 123 मिलियन से लगभग 24त्न अधिक और 2019 के 144 मिलियन से लगभग 6त्न अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में भी पुनरुद्धार के संकेत मिले, 2023 में भारत से और भारत के लिए 63.9 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय यात्री आए, जो 2019 में देखे गए 64.2 मिलियन के करीब है और 2022 के 47 मिलियन से 35 प्रतिशत अधिक है। कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से एंड कंपनी का अनुमान है कि भारत 2030 तक खर्च के मामले में चौथा सबसे बड़ा घरेलू यात्रा बाजार बन जाएगा।

इसके अतिरिक्त, विमानन विश्लेषण फर्म संकेत देती है कि भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। डब्ल्यूटीटीसी ने बताया कि इस क्षेत्र ने 2023 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 19.13 ट्रिलियन (. 230 बिलियन) का योगदान दिया, जो 2019 के स्तर से लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। उद्योग में रोजगार में भी 8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 43 मिलियन नौकरियों तक पहुंच गई। यह क्षेत्र के लचीलेपन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। वे अनुमान लगाते हैं कि भारतीय पर्यटन उद्योग में वृद्धि जारी रहेगी, और 2024 में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 21.15 ट्रिलियन (. 253 बिलियन) तक पहुंचने की उम्मीद है। उद्योग में नौकरियों में भी 2.45 मिलियन की वृद्धि होने का अनुमान है, जो भारत में हर 11 नौकरियों में से एक है। सकारात्मक संकेतकों के बावजूद, हाल के सरकारी बजटों में पर्यटन उद्योग को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है जैसे-जैसे केंद्रीय बजट 2024 नजदीक आ रहा है, पर्यटन उद्योग सरकार से अधिक समर्थन और निवेश की उम्मीद कर रहा है।

द ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष ज्योति मयाल को लगता है कि विदेशी प्रचार और प्रचार के लिए आवंटन में भारी कटौती करके उसे मात्र 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले साल के 100 करोड़ रुपये से कम है। वे कहती हैं, उद्योग बुनियादी ढांचे, विपणन और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए बजट आवंटन में वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कनेक्टिविटी, विरासत स्थलों और इको-टूरिज्म में निवेश से विकास को बढ़ावा मिल सकता है। संधारणीय प्रथाओं, अपशिष्ट प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना जिम्मेदार पर्यटन के साथ सरेखित होता है। वीजा आवश्यकताओं को सरल बनाना और भारत आने वाले पर्यटकों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश को प्रोत्साहित करना विदेशी पर्यटकों के आगमन को काफी हद तक बढ़ा सकता है।

होटल और रेस्तरां एसोसिएशन वेस्टर्न इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी का कहना है कि पर्यटन और आतिथ्य, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है और इसे प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की परियोजना लागत वाले होटलों और सम्मेलन केंद्रों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देना निवेश आकर्षित करने और आतिथ्य क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए आवश्यक है। 7500 रुपये से अधिक के कमरे के किराए वाले होटलों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी श्रेणी को समाप्त करके, इसे 12 प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में विलय करने से घरेलू और इनबाउंड पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ओटीओएआई) के अध्यक्ष रियाज मुंशी का कहना है कि आउटबाउंड पर्यटन क्षेत्र सकारात्मक नीतिगत बदलावों की उम्मीद कर रहा है।

उन्होंने कहा, एक प्रमुख उम्मीद आउटबाउंड टूर पैकेजों पर जीएसटी दरों में कमी की है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा अधिक किफायती हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, मौजूदा टीसीएस दरों की तुलना में बेहतर कर संग्रह (टीसीएस) नीतियों की उम्मीद है, जो वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं का कारण बन रही हैं।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ) के अध्यक्ष श्री राजीव मेहरा का मानना है कि वैश्विक मानचित्र पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। उनका कहना है, पर्यटन मंत्रालय को उद्योग के हितधारकों के साथ विदेशी यात्रा मार्ट में भागीदारी के लिए विपणन और प्रचार के लिए अलग से पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए, रोड शो आयोजित करने और टूर ऑपरेटरों को एमडीए सहायता के लिए। ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री अजय प्रकाश का मानना है कि पर्यटन के आर्थिक और सामाजिक लाभों के बारे में सभी दिखावटी बातों के बावजूद, उद्योग दुखद रूप से उपेक्षित है। केवल बुनियादी ढांचे का विकास पर्याप्त नहीं है - यदि इस क्षेत्र को अपनी क्षमता का एहसास करना है तो इसे विशिष्ट प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

यात्रा और पर्यटन उद्योग हर साल बजट से पहले अपनी इच्छा सूची रखता है और, उस दिन हमेशा निराश होता है। उच्चतम जीएसटी स्लैब 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और ट्रैवल एजेंट/टूर ऑपरेटर सेटऑफ का दावा करने के पात्र होने चाहिए। हवाई किराए को और अधिक किफायती बनाने के लिए विमानन ईंधन को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, वे कहते हैं।

आप की बात

आतंक से मुकाबला

हाल ही में हमारे पांच जवान आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए, हालांकि वीर जवानों ने आतंकी ठिकानों और आतंकियों को भी ढेर कर दिया। इससे पहले भी आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हालांकि, हमारे सुरक्षाबल मुस्तैदी से आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं और उन्हें तथा उनके अड्डों का सफाया कर रहे हैं किन्तु आखिर कब तक ये खूनी खेल जम्मू-कश्मीर में चलता रहेगा। इसका अंत होना चाहिए ताकि वहां शान्ति स्थापित हो सके। सरकार को आतंकी तैयार करने और उनको शरण व सहायता देने वालों तक पहुँचने के लिए विशेष कार्य योजना बनानी होगी। सरकार को अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिये आतंक के स्रोतों तक पहुंच कर त्वरित और गंभीर प्रयास कर आतंक का समूल नाश करना चाहिए। जम्मू-कश्मीर को आतंक से मुक्ति दिलाने के प्रयास तेज करने होंगे। आतंक से मुकाबले के लिए जनता को भी प्रशिक्षित व सैनिक रूप से तैयार करने की जरूरत है। यदि बहुसंख्य जनता अपने बीच छिपे आतंकियों तथा उनके समर्थकों के खिलाफ स्वत: कार्रवाई करने में सक्षम हो जाए तो सुरक्षा बलों से बोझ कम होगा तथा आतंकवादियों और उनके समर्थकों को पूरे देश में पैर टिकाने का स्थान भी नहीं मिलेगा।

- **महेश नेनावा,** इंदौर

शिक्षा में नवाचार

शिक्षा प्रणाली को नवाचार के माध्यम से सुधारना अब बेहद जरूरी हो गया है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे छात्रों में रचनात्मकता, समस्या समाधान की क्षमता और स्वतंत्र सोच को विकसित करना भी शामिल होना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि शिक्षा का असली उद्देश्य मस्तिष्क को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है न कि केवल तथ्यों को याद रखना। शिक्षा प्रणाली में नवीनतम तकनीकों और पद्धतियों को शामिल कर शिक्षकों को भी नियमित रूप से अद्यतित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे छात्रों को सबसे बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकें। शिक्षकों का ज्ञान और प्रशिक्षण ही छात्रों को श्रेष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण और अनुसंधान व विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षा में नवाचार केवल छात्रों के भविष्य के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में सुधार और नवाचार से ही हम एक प्रगतिशील और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं।

- **अवनीश कुमार गुप्ता,** आजमगढ़

ट्रंप पर हमला

अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला हर लिहाज से दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। गनीमत है कि हमले में ट्रंप को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और वह सुरक्षित हैं। बैलेट से होने वाले चुनावों को बुलेट द्वारा बाधित करने के प्रयास विश्व के हर कोने में होने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की चुनावी भाषण के दौरान हत्या कर दी गई थी। उससे पूर्व भी इंदिरा गांधी व राजीव गांधी सहित विश्व के कई नेताओं पर जानलेवा हमले हुए हैं। अब समूचे विश्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को मिलकर आतंकवाद को जड़ मूल से खत्म करना होगा। ट्रंप तो बच गए मगर फिर भी आतंकवादी मौके की तलाश में हर जगह मौजूद हैं। इस प्रकार बंदूक के जोर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस करने के प्रयास अक्षम्य हैं। सुरक्षा व्यवस्थायें मजबूत करने तथा सुरक्षा बलों को आधुनिकतम तकनीकों से लैस करने के साथ लोकतांत्रिक समाजों में हिंसा और आतंकवाद पैदा होने के कारणों पर गंभीर विचार कर ऐसी परिस्थितियां बनानी होंगी जिनमें ऐसे तत्वों को विकास का अवसर ही न मिले। अब देखना होगा कि ट्रंप अपने देश में, खासकर नौजवानों में बंदूकों के आकर्षण से निपटने के बारे में क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

इमरान की मुश्किलें

इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर सरकार विदेशी चंदा स्वीकार करने, गोपनीय दस्तावेज लीक करने, अमेरिका में गुप्त प्रस्ताव करने और 9 मई को पाकिस्तान में हुए दंगे कराने के मामले में केस शुरू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है। इसके चलते इमरान खान पर देशद्रोह का आरोप और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ - पीटीआई पर प्रतिबंध भी लग सकता है। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान में राजनीतिक संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया है और एक भयावह स्थिति पैदा हो गई है। मौजूदा सरकार का मानना है कि पीटीआई और पाकिस्तान सरकार एक साथ काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन विडंबना है कि पाकिस्तान सरकार तथा सेना के तमाम प्रयासों के बावजूद आम जनता में इमरान खान की लोकप्रियता बनी हुई है। इसके साथ ही पाकिस्तान में बढ़ती अराजकता, आतंकवाद व आर्थिक बदहाली न केवल उस देश, बल्कि भारत समेत सारी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। विफल राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है जहां वह लगातार आतंकी भेज रहा है।

- **दत्तप्रसाद शिरोड़कर,** मुंबई

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

कर्बला में ताजिए हुए सुपुर्द-ए-ख़ाक ग़मे के बीच ग़मगीन रहा माहौल

संवाददाता। नसीराबाद, रायबरेली

नगर पंचायत नसीराबाद में दसवीं मोहर्रम पर शिया धर्म के लोगो ने सीनाज़नी और छूरी जंजीर का मातम करते हुए ताजिया कर्बला में दफन किया। कस्बे में लोगो ने कर्बला के बहत्तर शहीदो की याद में दसवीं मोहर्रम का पहला जुलूस सुबह नौ बजे इमामबाड़ा चौपार व दूसरा रौजा इमामबाड़ा से तथा तीसरा दोपहर एक बजे चौपार इमामबाड़े से बड़े ही ग़मगीन माहौल में अलम और जुल्जना के साथ अपने क़दीमी रास्तो से होते हुए अली शहीद पहुंचा। कस्बे के हाशिम कुंआ के पास तीनों जूलूसों के अजादारों ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को याद करके नौहाख्वानी और सीना ज़नी की।

जुलूस में हसन नकवी ने पढ़ा- शय को ना पानी दिया जुल्म हुआ या नहीं कांटो पे चलना पड़ा जुल्म हुआ या नहीं, शय के सलमदार पर टूट पड़े ऐहलेशर जुल्म हुआ या नहीं मौलाना रहबर अशकरी ने अमान हुसैन के नौहे अब्बास उठाओ अली अकबर का जनाज़ा ,उठता नही मुझसे मेरे दिलबर का जनाज़ा ,अब्बास कमर टूट गई ग़म में तुम्हारे।को सुन कर लोगो की आंखों से आंसू निकल आये जिससे माहौल ग़मगीन हो गया। नौहे के बाद अजादारों ने या अली मौला,हैदर मौला की सदाये बुलंद की। कर्बला के शहीदों की याद में बड़ों के साथ साथ हिन्दू समुदाय के लोगों ने भी छूरी जंजीर का मातम किया। जंजीरज़नी के बाद जुलूस अपने निर्धारित रास्ते से होते हुए वार्ड नंबर छह मुहल्ला नाका में स्थित कर्बला अली शहीद में अजादारों ने ताजिया सुपुर्द खाक किया। जुलूस में सभी धर्मों को लोगों ने शामिल होकर इमाम हुसैन को नजराना ए अकीदत पेश की। नगर पंचायत की ओर से ताजिया के सभी रास्तों में विशेष सफाई व चूने का छिड़काव कराया गया।

ईयर फ़ोन और हेडफ़ोन का लम्बे समय तक न करें उपयोगः डीएम

संतकबीरनगर। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने एण्ड्राएड फोन्स के साथ ईयर फोन और हेडफोन/ईयर प्लग का अधिक समय तक कान में लगा कर उपयोग कर रहे नागरिकों विशेष तौर पर युवा वर्गों को इससे होने वाली हानियों, विशेष रूप से लम्बे समय तक इसके उपयोग से युवावों में श्रवण ह्रास की समस्या आने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये एडवाइजरी का संज्ञान लेते हुए जनपदवासियों युवाओं से अपील की है कि ईयर फ़ोन और हेडफोन/ईयर प्लग का लम्बे समय तक उपयोग करने से बचें। उन्होंने इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सुझावों तथा इससे होने वाली हानियों का जिक्र करते हुए तथा ईयर फ़ोन/ईयर प्लग के लम्बे समय तक उपयोग के कारण सुनने की श्रवण ह्रास और टिनिटस को रोकने में सहायता किये जाने के सम्बन्ध में जारी सुझाव का अनुपालन किये जाने की अपील की है। जिलाधिकारी ने उक्त के सम्बन्ध में बताया है कि वायर्ड या ब्लूटूथ इयर प्लग/हेडफ़ोन के अनावश्यक उपयोग से सुनने की क्षमता खराब या अस्थायी तौर पर सुनने की क्षमता भी खत्म हो सकती है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि प्रतिदिन 2 घण्टे से अधिक ईयर फोन/हेड फोन का उपयोग न किया जाय। आवश्यकता पड़ने पर 50 डेसिबल वॉल्यूम सहित ईयर फोन/हेडफोन जैसे व्यक्तिगत ऑडियो उपकरणों का सावधानी पूर्व एवं मानक के अनुसार ही उपयोग किया जाय। वाहन चलाते समय मोबाइल/ईयर फोन/ईयर प्लग का उपयोग न किया जाय। बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के सम्पर्क में आने से रोका जाय ताकि यह तेज आवाज आने वाले आवेग के सम्पर्क से बच सकें।

करंट की चपेट में आने से ताजिया दफ़न करने जाते एक की मौत

संवाददाता। संतकबीरनगर

कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के चुरेब रेलवे स्टेशन के समीप भाटपार फाटक के पास ताजिया दफ्न करने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

बुधवार को मोहर्रम त्योहार पर काटें चौकी क्षेत्र के भाटपार गांव सहित आस पास के अन्य गांवों के लोग निवासी मातमी गाजे बाजे जुलूस के साथ ताजिया दफ्न करने के लिए कर्बला पर जा रहे थे, कि अभी ताजिया गांव के किनारे रेलवे के समपार फाटक पर पहुंचा था, कि ट्रैक के ऊपर लगे रेल लाइन के तार में ताजिया छू जाने से सभी लोग चपेट में आ गए, जिसमें भाटपार गांव निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद इलियास पुत्र मो.अली की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अब्दुल करीम पुत्र नाजीर, राम सुबह पुत्र चंद्रबली समेत तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें संयुक्त जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भिजवाया गया, जहां, तीनों का उपचार चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है।

जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया की कांटे चौकी क्षेत्र थाना कोतवाली खलीलाबाद, चुरेब रेलवे क्रसिंग पर एक ताजिया का जुलूस निकल रहा था और रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए लापरवाहीवश रेलवे के ओवरहेड हाई टेंशन बिजली का तार छू जाने से एक व्यक्ति की दुर्भाग्यवश मौत हो गई है और दो जख्मी है जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मौके पे फोर्स पहुंच गई है, घटना स्थल पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। घटनास्थल पर जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर एवं पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता उपस्थित रहे।

लबों पर 'या हुसैन' की सदाओं के साथ दफ़नाये गये ताज़िये

मुसाफिरखाना, अमेठी। बुधवार को क्षेत्र के भनौली रसूलाबाद गंगेरवा कोटवा सहित कई गांवों में बहुत ही गमगीन माहौल में मोहर्रम का जुलूस निकाला गया। 10 मोहर्रम यानि आशूरा के दिन इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की याद में ताबूत निकाला गया। या हुसैन-या हुसैन की सदाओं के साथ अज़ादारों ने इमाम हुसैन का ताबूत उठाया और मातम करते हुए जुलूस निकाला।

सुबह से ही मजलिसों का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह सबसे पहले मौलाना आसिफ हुसैन के घर पर मजलिस हुई। उसके बाद कई घरों के साथ-साथ बड़े इमामबाड़े, छोटे इमामबाड़े, दरगाहे आलिया व पूरे बस्ती में मजलिस हुई। मजलिस के बाद आमाल-ए-आशूरा किया गया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ताबूत, अलम और ताजिया के साथ जुलूस बड़े इमामबाड़े से निकलकर अपने तयशुदा मार्ग से जामा मस्जिद इमामबाग पहुंचा। जहां लोगों ने नमाज पढ़ी। नमाज़ के बाद जुलूस वापस बड़े इमामबाड़े पहुंचा और यहां अंजुमन सिपाहे हुसैनी के नौजवानों ने जंजीरजनी कर बीबी फातेमा को उनके लाल का पुरसा दिया। यहां मौलाना सदाकत हुसैन ने तकरीर की और लोगों को कर्बला के शहीदों के बारे में बताया।

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया ताज़िया, पांच झुलसे

गोंडा। हाईटेंशन विद्युत तार की चपेट में ताजिया के आने की वजह से पांच लोग झुलस गए। जिन्हे पहले सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने हालत गंभीर देखकर गोंडा मेडिकल कालेज के लिए गोंडा रेफ़र कर दिया। घटना जनपद गोंडा के थाना इटियाथोक अंतर्गत ग्राम तेलियानी कानूनगो से जुडा है। यहां बुधवार को मोहर्रम के जुलूस में ताजियादार अपनी ताजिया लेकर चल रहे थे कि एक ताजिया की ऊंचाई अधिक होने की वजह से उसका उपरी सिरा हाई वोल्टेज विद्युत तार से टकरा गया। जिससे ताजिया की सम्पर्क में रही एक महिला सहित पांच लोग झुलस गए। जिसमे से तीन की हालत गंभीर थी। पुलिस ने झुलसे लोगों को आनन-फानन में सीएचसी इटियाथोक पहुंचाया। ज़हां प्राथमिक उपचार के बाद हालात गंभीर देखकर चिकित्सक ने तीन लोगों को गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया।

अघोषित बिजली कटौती को लेकर सपाइयों ने सौंपा ज्ञापन

अमेठी। जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती और सूख चुकी नहरों को को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता जयसिंह प्रताप यादव ने अमेठी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर नहरों में पानी छोड़े जाने और अमेठी में हो रही अघोषित बिजली कटौती को बंद करने की मांग की है।

सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने कहा कि इस समय खेती किसानी का समय चल रहा है किसानो के धान की रोपाई प्रगति पर है अमेठी ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती हो रही है और 18 घंटे से ज्यादा अंधाधुंध बिजली काटी जा रही है और बोल्टेज डाउन होने से नलकूप ठप पड़े है और आम नागरिकों को भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जिले की सभी नहरें और रजबहे सूखे पड़े हैं। जिससे किसानों को धान की रोपाई करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है विभागीय अधिकारी बिजली और पानी के नाम पर कागज तक सिमित है किसानो के सामने इतना बड़ा संकट खड़ा है सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही, इससे यह साबित होता है यह भाजपा की यह सरकार किसान विरोधी है।

सूख चुके कुंए, इंडिया मार्का नल खराब, पानी को लेकर हाहाकार

संवाददाता। नसीराबाद, रायबरेली

नगर पंचायत नसीराबाद के जिम्मेदारों की मनमानी और लाचर कार्य शैली के चलते भीषण उमस भरी गर्मी में महीनों से पानी के लिए तरस रहे नगर पंचायत के मोहल्ला लाला के बाजार (मौहरिया) के लोगों का आखिरकार धैर्य जवाब दे ही गया। मोहल्ले वासियों ने नगर पंचायत के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और जल्द ही पानी आपूर्ति बहाल करने की मांग की।

नगर पंचायत के नसीराबाद के अधिकारी कर्मचारी भले ही नगर की व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त रखने का लाख दावे करते है।लेकिन नगर के विकास में बाधा बन रही अफरशाही से नगर वासियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।बात करें नगर पंचायत नसीराबाद वार्ड नं.1 लाला की बाजार (मौहरिया)की तो इस चार हजार से ज्यादा की आबादी वाले मोहल्ले में शुद्ध पानी को लेकर मोहल्ले के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। शुद्ध पानी के लिए मोहल्ले के लोग तरस रहे हैं।

लो वोल्टेज और बिजली कटौती से जहां सबमर्सिबल वीरान पड़े है।वहीं तीन सरकारी हैंडपंपों में से दो हैंडपंप महीनों से खराब होकर गंदा पानी उगल रहें है। ऐसे में सिर्फ एक हैंडपंप के सहारे मोहल्ले वासी मजबूरन अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। मोहल्ले में पानी की किल्लत और लगातार शिकायतों के बाद भी नगर पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही ना होने के चलते मंगलवार को मोहल्ले वासियों ने नगर पंचायत में हो रही मनमानी को लेकर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि बीते कई महीनो से शुद्ध पानी की किल्लत हैं।

लो वोल्टेज व बिजली कटौती को लेकर समर्सेबल भी वीरान पड़े हैं। ऐसे में चार हजार से ज्यादा की आबादी वाले मोहल्ले को सिर्फ एक हैंडपंप के सहारे ही पानी की आपूर्ति हो रही है। एक बाल्टी पानी के लिए घंटो लाइन में लगकर पानी की जरूरत को पूरा किया जा रहा है। रहा है।पानी की समस्या को दूर कराने के लिए कई बार नगर पंचायत अधिकारियों को बताया जा चुका है। नतीजा सिफर रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जल्द ही पानी की समस्या दूर कराने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में सुरेश कुमार, शत्रुघ्न, रामू,राम जी, शंकर, श्यामू, रामखेलावन,धर्मराज समय तमाम नगर वासियों ने जल्द ही पानी आपूर्ति को दुरुस्त कराए जाने और खराब पड़े हैंडपंपों को सही कराए जाने की मांग की है।इस बावत ईओ दिनेश सिंह ने बताया कि जानकारी प्राप्त हुई है। जल्द ही हैंडपंपों को दुरूस्त करवाकर पानी की किल्लत को दूर किया जाएगा।

ग़मगीन माहौल में प्राचीन कर्बला में ताज़ियों को किया सुपुर्द ए ख़ाक

संवाददाता। कालपी, जालौन

बुधवार की शाम को ताजियेदारों एवं हजारों अकीदतमंदों ने गमगीन माहौल में प्राचीन कर्बला के मैदान में नगर के दर्जन भर ताजियों को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया।

विदित हो कि मोहर्रम की दसवीं की भोर सुबह 4 बजे इमाम चौकों से ताजियेदार तथा अकीदतमंद अपने-अपने ताजियों को लेकर सदर बाजार स्थित श्री दरवाजे गेट पर पहुंच गए। वहां पर मातम तथा गम के साथ ताजियों का जुलूस शुरू हुआ। जुलूस बड़ा बाजार, अदल सराय होते हुए दीवान औलिया के ग्राउंड में पहुंचा जहां अकीदतमंदों ने फातिहा पढ़ी जिसके बाद जुलूस का समापन किया गया। इस मौके पर मुन्ना राइन, इकबाल खान, हिदायत खान आदि ताजियेदारों के साथ काफी संख्या में महिलाएं तथा बच्चे शामिल रहे। ताजिया जुलूस में जगह-जगह लंगर वितरण किया गया। दोपहर दो बजे के बाद सभी तजियेदार अपने-अपने ताजियों को लेकर प्राचीन कर्बला के मैदान में पहुंचे। रंज एवं गम के माहौल में ताजियों को सुपुर्द ए खाक किया गया। कर्बला में आयोजित मोहर्रम के मेले में भारी संख्या में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया।

मोहर्रम के चांद की 9/10 वीं की रात में शासन प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर के दो अलग-अलग स्थानों में अकीदतमंदों के द्वारा जलते हुए आग के अलाव का प्रदर्शन किया गया। नगर के मुहल्ला उदनपुरा स्थित दीवान औलिया ग्राउंड में खलीफा नत्थू, खलीफा पप्पू एवं अकीदतमंदों की मौजूदगी में मातम के साथ अलाव का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद रात में 1 बजे दमदमा तकिया ग्राउंड में भी खलीफा अलीम के नेतृत्व में अलाव का प्रदर्शन किया गया। मोहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस, कर्बला मेला, छड़, अलम जुलूस में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन तथा पुलिस विभाग के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

चोरी के इरादे से घूम रहे दो युवकों को पुलिस ने पकड़ा

जालौन, उरई। चोरी के इरादे से अलग अलग स्थानों पर घूम रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। ग्रामीणों ने पुलिस बुलाकर दोनों युवकों को पुलिस के सुपुर्द किया। वहीं, पुलिस युवकों से पूछतांछ कर रही है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दहगुवां में मंगलवार की रात एक युवक खेतों में घूम रहा था। ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने देखा तो युवक गांव में स्थित एक नलकूप के पास रेकी कर रहा था। शक होने पर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया। उधर, कोतवाली क्षेत्र के ही ग्राम कुंवरपुरा में भी बाइक सवार दो युवक गांव के बाहर दो युवक चोरी के इरादे से घूम रहे थे। काफी देर तक उन्हें चक्कर लगाते हुए देखकर ग्रामीणों को शक हुआ और ग्रामीणों ने जब उन्हें रोका तो वह भागने लगे। जिसमें एक युवक मौके से भाग निकला जबकि दूसरे को ग्रामीणों ने पकड़पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने दोनों युवक सुपुर्द कर दिए। पुलिस दोनों युवकों को कोतवाली ले आई है।

अखाड़ों की बैठक में सम्मिलित होंगे अयोध्या के सैकड़ों संत

अयोध्या। 2025 में प्रयागराज कुंभ के मेले का आयोजन होगा जिसको लेकर के सभी अखाड़ों की बैठक प्रयागराज में की जा रही है इसी क्रम में अखिल भारतीय श्रीपंच रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या के सैकड़ों साधु- संत आगामी कुंभ मेले की बैठक के लिए बुधवार को प्रयागराज के लिए रवाना हो गए है और 18 जुलाई को प्रयागराज की बैठक में शामिल होंगे। निर्वाणी अनी के श्रीमहंत मुरली दास महाराज एवं निर्वाणी अनी के महासचिव सत्यदेव दास एवं महासचिव नंदराम दास के नेतृत्व में संतों का दल सबसे पहले हनुमानगढ़ी पर पहुंचकर हनुमान जी महाराज का पूजन की आरती उतारी और हनुमान जी के जयकारे लगाए और प्रयागराज के लिए रवाना हुए इन संतों की टोली में प्रमुख रूप से अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास के शिष्य हेमंत दास, हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास के उत्तराधिकारी डां महेश दास, अभिषेक दास, राजेश पहलवान, रामकृष्ण दास, अभिषेक दास, पहलवान केशव दास सहित सैकड़ो की संख्या में संत महंत सम्मिलित रहे जो दर्जनों वाहनों से रामनगरी अयोध्या से प्रयागराज के लिए कूच किया।

अवर अभियंता की देखरेख में जगम्मनपुर क्षेत्र में चलाया गया चेकिंग अभियान

जगम्मनपुर, जालौन। बुधवार को जगम्मनपुर कस्बा सहित आसपास के गांवों में अवर अभियंता आलोक खरे की अगुवाई में वृहद स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें दर्जन भर से अधिक लाइनमैनों ने घर-घर कनेक्शनधारकों के आवासों में दस्तक देकर जहां मीटरों की चेकिंग बड़े स्तर पर की तो वहीं कटियाधारकों की भी खबर लेकर उन्हें चेतावनी दी गयी। विद्युत महकमे के जेई आलोक खरे के निर्देश कस्बा जगम्मनपुर के साथ समीपस्थ गांव कंजौसा, भिटौरा, बेनीपुरा, जायघा, मई सहित अनेकों गांवों में वृहद स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान चेकिंग टीम में शामिल लाइनमैन पुत्तन मिश्रा, करन सिंह, रविन्द्र कुमार, राहुल, गजेंद्र सिंह, सुनील, ओमकार, धीरेंद्र, कमल सिंह, ज्ञान सिंह, मोनू व मुनुआ आदि ने घर-घर लगे मीटरों की बड़े स्तर पर चेकिंग की इस दौरान जहां पर भी गड़बड़ी मिली उसे ठीक कराया गया साथ ही विद्युत चोरी करने वालों को चेतावनी दी कि वह विद्युत का उपभोग कनेक्शन लेने के बाद ही करें। सभी कनेक्शनधारक नियमित रूप से अपने बिलों को जमा करें ताकि उन्हें नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। चेकिंग दौरान अवर अभियंता आलोक खरे ने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि वह अपने बकाया बिलों को समय से जमा कर विभाग का सहयोग करें। यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो वह तत्काल मुझे व लाइनमैनों को अवगत करायें।

तीन दोस्तों से साथ गये युवक का शव किले के कुएं से हुआ बरामद

संवाददाता। जालौन, उरई

मंगलवार को घर से युवक को बात करने के बहाने उसके तीन साथी अपने साथ ले गए थे। देर शाम तक जब युवक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने युवक की तलाश शुरू की। जिसमें युवक का शव गांव में गढ़ी पर बने किला के अंदर कुंए से बरामद हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और फोरेंसिक टीम को बुलाकर नमूने एकत्रित किए। पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिकरी राजा निवासी विशाल उर्फ भरत रजक (25) पुत्र देव प्रसाद मंगलवार की सुबह घर पर ही था। दोपहर में युवक नहाने के लिए जा रहा था। तभी उसके तीन साथी साथी धीरज पुत्र सुखराम बेलदार, मानसिंह पुत्र मुनीम बाल्मीकि, रामवरन उर्फ मामू निवासी महोबा वहां आए और गांव में घूम आने के बहाने उसे अपने साथ ले गए। पिता देवप्रसाद ने पुलिस को बताया कि शाम तक जब उनका बेटा विशाल घर वापस नहीं लौटा तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कील। जब वह उनके साथियों के यहां गए और पूछतांछ की तो उन्होंने कुछ नहीं बताया जिसके बाद उन्हें अनहोनी की आशंका हुई।

जब उन्होंने शराब की दुकान पर पूछतांछ की तो पता चला कि युवकों ने वहां से शराब ली थी और गढ़ी की ओर गए थे। गढ़ी पर पहुंचकर जब उन्होंने वहां किले के अंदर कुंए में झांककर देखा तो विशाल का शव कुंए में पड़ा था। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाल वीरेंद्र पटेल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। शव को बाहर निकलवाकर फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए। ग्रामीणों के अनुसार युवक के गले में गमछा भी पड़ा था और विशाल अपने पिता का अकेला ही पुत्र था। पिता देव प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोतवाल वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस तीनों की तलाश कर रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सांसद को सौंपा ज्ञापन

उरई, जालौन। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने देश में गरीब, वंचित समाज (एससी, एसटी, ओबीसी) को मुख्य धारा में जोड़ने के लिये महामहिम राष्ट्रपति, तथा प्रधानमंत्री को सम्बोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन क्षेत्रीय सांसद नारायण दास अहिरवार को सौंपा। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने अपने ज्ञापन में कहा है कि देश एवं प्रदेशों के अंदर समता, समानता, शिक्षा व स्वतंत्रता आदि मूल अधिकारों के विरुद्ध कार्य होता प्रतीत हो रहा है, साथ ही वंचित समाज के साथ आये दिन जुल्म, अत्याचार व उत्पीड़न हो रहे हैं। पूंजीवाद को स्थापित करने के लिए निजीकरण, संविदा भर्ती प्रक्रिया, लेटरल भर्ती प्रक्रिया व आउटसोर्सिंग आदि आरक्षण विरोधी नीतियों के कारण देश में आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक गैर बराबरी बढ़ती जा रही है, जिससे संविधान की मूल भावना समता, समानता व वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विकास के अवसर उपलब्ध कराने संबंधी आदि अधिकारों का हनन हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 गरीब, वंचित समाज के हित में नहीं है। असंवैधानिक और जनविरोधी अग्निवीर जैसी भर्तियों की नीति एवं पाँच वर्ष से रिक्त पड़े सृजित पदों को समाप्त करने की नीति बनाने से वंचितों में असंतोष की भावना है। क्योंकि स्थाई भर्ती प्रक्रिया रिक्त पड़े पदों को विशेष भर्ती अभियान द्वारा भरा जाना एवं पुरानी पेंशन योजना भारतीय नागरिको को भविष्य की सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं अल्पकालिक असंवैधानिक भर्ती प्रक्रिया, निजीकरण, रिक्त सृजित पदों को समाप्त करना एवं नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) नागरिकों में असंतोष की भावना पैदा करती है, जिससे शासन के प्रति विश्वास की भावना कम होने के साथ समाज में जन आक्रोश पैदा हो रहा है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी देश में व प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के कार्मिकों एवं अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के स्थान पर पदावनत (रिवर्ट) कर अपमानित करने का कार्य किया गया।

आलमपुर गौशाला में एसडीएम को गौवंशों के लिये गंदा पानी भरा मिला

संवाददाता। कालपी, जालौन

बुधवार को उप जिलाधिकारी ने आलमपुर स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें गौवंशों के लिए भरा गया पानी बेहद खराब मिला जिस पर उन्होंने नाराजगी प्रकट कर कार्यवाही के संकेत दिए हैं।

शासन ने आवारा गौवंशों की देखभाल के लिए जगह जगह गौशालाए संचालित की है जहां पर उनके लिए खाने पीने के साथ अन्य व्यवस्थाएं भी की गई है। लेकिन इसके बावजूद गौशालाओं की व्यवस्था ठीक नहीं है जिसके उदाहरण समय समय पर आते रहते हैं। सूत्रों की माने तो शासन ने गौवंशों के खानपान के लिए 50 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया है।

लेकिन इसके बाबजूद गौशालाओं में उनकी सेहत ठीक नहीं है हालाकि शासन ने प्रशासनिक अधिकारियों को समय पर उनका निरीक्षण करने के निर्देश दिए है और इसी के चलते वुधवार को उप जिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह ने मुहल्ला आलमपुर में नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित गौशाला कि निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कुछ भी ठीक नहीं लगा।

उनके अनुसार गौवंशों के पीने के लिए परिसर में बनी हौद में बेहद खराब पानी भरा है जिसके पीने से गौवंश बीमार हो जाते हैं तो गौवंशों के लिए उपलब्ध भूसे की भी गुणवत्ता ठीक नहीं लग रही थी। जिसके चलते उप जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद पालिका के संविदा कर्मचारी को फटकार लगाई और कहा कि गौशाला की व्यवस्था नही सुधरी तो कडी कार्यवाही की जाएगी।

इस दौरान उन्होंने संचालकों को गुणवत्ता युक्त भोजन के निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिदिन एक गौवंश के लिए 50 रूपये कम नहीं है और अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो कार्यवाही की जाएगी।

मादक पदार्थ की बड़ी रिकवरी 1000 कुंतल गांजा बरामद

● 15 करोड़ की संपत्ति अवैध मादक पदार्थ के तस्करों से जब्त तथा 10 करोड़ की लक्जरी गाड़ियां की गई जब

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस अधीक्षक बांदा और चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांदा को नशा मुक्त बनाने हेतु 15 करोड़ की संपत्ति नशा व्यापारियों की जप्त की और लगभग 10 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां जप्त की लगभग 1000 कुंतल गांजा बरामद किया जनपद को नशा मुक्त बनाने तथा नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु शुरू किया गया ऑपरेशन ईगलष्। आपरेशन ईगल के तहत अवैध मादक पदार्थो की बिक्री करने वाले गिरोह की पूरी चेन पर की जायेगी कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह भी बताया कि डिग्री कॉलेज में और इंटर कॉलेज में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर शक्ति से रोक लगाई जाएगी भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर बांदा को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है अवैध मादक पदार्थों का अभियुक्त कितना भी पावरफुल हो उसे छोड़ नहीं जाएगा हालांकि यह भी सच्चाई है बांदा में उड़ीसा हैदराबाद आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश पंजाब हरियाणा से भयंकर तरीके से तस्करी की जाती है इन्हें हर हाल में रोका जाएगा और हम रोक भी रहे हैं।

क्षेत्राधिकारी अपराध, एसओ जी. सर्विलांस एवं लोकल थाना की इंटीग्रेटेड टीम ऑपरेशन ईगल के तहत अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वालो पर करेगी कार्यवाही। अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले तथा उसमें किसी भी तरह से शामिल अभियुक्तों पर गैगेस्टर एवं पिट एनडीपीएस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अवैध सम्पत्ति को किया जायेगा कुर्क साथ ही ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत नये कानून के प्रावधानो के अन्तर्गत दिलायी जायेगी कठोर सजा। मुख्यमंत्री उप्र शासन द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही हेतु जारी किये गये आदेशो एवं निर्देशो के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज भानू भास्कर के मार्गदर्शन व पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने तथा अवैध मदक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोहो पर कठोर कार्यवाही करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान ऑपरेशन ईगल शुरू किया गया है।

ऑपरेशन ईगल के तहत न सिर्फ केवल जनपद में अवैध मादक पदार्थ लाकर बिक्री करने वाले गिरोहो पर बल्कि उनसे जुडी प्रत्येक कड़ी पर कार्यवाही की जायेगी। अवैध मादक पदार्थो की बिक्री करने वाले छोटे.छोटे अभियुक्त से लेकर तस्करी की चेन में ऊपर सप्लाई कर रहे अभियुक्तों के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायेगी चाहे जनपद बांदा या उनके आस.पास के जनपदो में बैठे हो या अन्य किसी दूसरे राज्य में पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन ईगल का उद्देश्य नशे के दलदल में फ्सते जा रहे जनपद के युवाओ को बाहर निकलाकर जनपद को नशा मुक्त बनाना तथा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोहो जड़ से खत्म करना है।

अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी अपराध, एसओजी, सर्विलांस एवं लोकल थानो को मिलाकर एक समर्पित टीम का गठन किया गया है जो वॉंडीवार्न कैमरो तथा अन्य तकनीकि संशाधनो से युक्त रहेगी जो ऐसे अपराधो पर कार्यवाही करेगी। ऑपरेशन के तहत जनपद में अवैध मादक पदार्थो की छोटे पैमाने पर बिक्री करने वाले अभियुक्तों के साथ.साथ उनसे जुडे अभियुक्तों जो अवैध मादक पदार्थो की सप्लाई करते है को कार्यवाही के दायरे में लाया जायेगा।

दो पक्षों में हुई जमकर फायरिंग, गांव में दहशत, पुलिस ने शुरु की जांच पड़ताल

संवाददाता। मौदहा, हमीरपुर

पुलिस से लिखित शिकायत करने जाता युवक

क्षेत्र के ग्राम परछा में मंगल वार की देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गांव में अलाव देख रहे लोगों के अलावा आसपास मौजूद किसी अनहोनी की आशंका को लेकर अपने घरों में दुबक गए। घटना की जानकारी होते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में एक पक्ष ने कोतवाली में तहरीर सौंप आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। कोतवाली क्षेत्र मौदहा का ग्राम परछा झगड़ा व अपराधिक कृत्यों के चलते काफी चर्चित है। मंगलवार की देर रात गांव में जब अलाव का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था तभी देर रात गांव की गली में फायरिंग की आवाज सुन अलाव देख रहे ग्रामीण व आसपास मौजूद लोग अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने घरों में जाकर दुबक गए। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है वही घटना के बाद गांव के मुइनुद्दीन उर्फ जुम्मु ने गांव के ही इरफान व उसके साथियों पर नाजायज असलहों से फायरिंग कर उसे जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है हालांकि गांव में चर्चा है कि यह फायरिंग दोनों पक्षों की ओर से हुई है इस मामले को लेकर कोतवाली प्रभारी राम आसरे सरोज का कहना है कि घटना की जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी।

शासन से भूमि संरक्षण विभाग के पांच साल के कार्यों की टीएसी जांच के आदेश

हमीरपुर। शासन स्तर से स्थानीय भूमि संरक्षण विभाग की तीन इकाईयों के पांच साल के कार्यों की टीएसी जांच के आदेश होने से विभागीय अफ्सरों की नीद उड़ गयी है। चारो तरफ से फंसते देख बचाव के रास्ते खोजे जा रहे हैं। राठ इकाई के बीएसए इन दिनों बनारस में तैनात है। मामले की शिकायत राज्य सभा सांसद ने सीधे कृषि मंत्री से की थी।

नमी संरक्षण के नाम पर जिले में भूमि सरंक्षण विभाग प्रथम,दिवतीय व राठ इकाई ने पांच साल में करोड़ो रुपये खर्च किये है राज्य व केंद्र सरकार के धन का जमकर दुरुपयोग हुआ है। बंधी के ऊपर बंधी बनाना, कुलावे व मेडबंधी बनाने के नाम पर जमकर धांधली की गयी है यही नही किसानों द्वारा जो शिकायते की गयी थी उस पर कोई ध्यान नही दिया गया है। किसानों के खेतों में नमी संरक्षण, खेत तालाब योजना,कृषि समृद्धि योजना, डव्ल्यू डीसी पीएमकेएसवाई, नमसा व अन्य तमाम कार्य भूमि संरक्षण इकाई प्रथम व दिवतीय एवं राठ इकाई द्वारा किया जा रहा है। कई सालों तक राठ इकाई व हमीरपुर इकाई का कार्यभार अशोक यादव संभाले रहे है और जमकर धाधली की गयी यही नही बनारस ट्रांसफर होने के बाद भी श्री यादव कई महीने तक हमीरपुर का कार्यभार नही छोड़ा और वही से काम करते रहे। बाद में शासन के हस्तक्षेप करने के बाद कार्यभार छोड़ा था,उसी समय जमकर धांधली की गयी थी, अशोक यादव के वित्तीय अनियमतिता करने की शिकायत डीडी कृषि भी लिख चुके है यही नही मंडलीय अधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक ने भी इनकी लिखित शिकायत की थी मगर उनके ऊपर कोई असर नही पड़ा है। विभागीय नेटवर्क इतना मजबूत है कि एक मर्तवा मामले की जांच डीएम हाल ही मे करा चुके है मगर जांच अधिकारियों से मिलकर भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने अपने पक्ष में रिपोर्ट लगवा ली थी हालाकि उसी जांच रिपोर्ट को आधार मानकर अधिकारी अपने को पाक साफ बनने का प्रयास कर रहे है मगर शासन स्तर पर टीएसी जांच को रोक पाने में अधिकारी सफल नही हो पा रहे है। शिकायत राज्य सभा सांसद बाबूराम निषाद ने सीधे कृषि मंत्री से की थी,कृषि मंत्री में मामले को गंभीरता से लेते हुये पांच सालों के कार्यो के समस्त कार्यों की जांच टीएसी लखनऊ से कराने के आदेश कर दिये है। हालाकि यहां के विभागीय अधिकारी लखनऊ में टीएसी के अफ्सरों को रोकने का बहुत प्रयास किया है मगर सफल नही हो पा रहे है। जिससे तीनों इकाईयों के अफ्सरो के होश उड़ गये है। हालाकि भूमि संरक्षण विभाग के बीएसए बीरचंद पटेल ने तो शासन को लिखकर दे दिया हैकि उनके इकाई की जांच करा ली जाये क्योकि उनका रिटायरमेंट होने वाले है वह जांच में पूरा सहयोग करेगे।

टीएसी के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि हर हाल मे होगी हमीरपुर में टीएसी जांच

हमीरपुर। टीएससी लखनऊ के डिप्टी डायरेक्टर व यूपी हेड आरके सिंह ने बुधवार को बताया कि हमीरपुर में टीएसी जांच लोकसभा चुनाव के कारण रुक गयी थी मगर हर हाल में अगस्त या सितम्बर में जांच की जायेगी। पांच साल में जो जो कार्य हुये है वह सभी जांच किये जायेगे। इसके लिये अभिलेख मांगे जायेगे क्योकि विभाग दवारा जो तालाब बनाये गये है उनमे अभी पानी भरा होगा इसलिये थोडा जांच मुश्किल होगी मगर फिर भी जांच करायी जायेगी श्री सिंह ने बताया कि करीब पच्चीस फीसदी कार्यों की जांच तो पहले टीएसी कर चुकी है मगर शेष कार्य तो टीएसी टीम देखेगी। जांच में जो भी गड़बडी पायी जायेगी तो संबंधित अधिकारी से रिकवरी करायी जायेगी।

केएसवाई में किसी को नही है जानकारी कहा हो रहा है काम

हमीरपुर। दो साल से सरकार द्वारा संचालित केएसवाई विभागीय अफ्सरों के लिये बरदान सावित हो रही है, हर साल प्रत्येक इकाई के लिये 75-75 लाख रुपये का बजट बंधी बांधने के लिये मिल जाता है मगर कार्य कहां हो रहे है इसकी जानकारी न तो ग्राम प्रधान को है न ही किसी किसान को है। भूमि संरक्षण अधिकारी अपने स्तर से इस बजट को खर्च कर लेते है,यह योजना पांच साल तक जिले में संचालित की जायेगी।

सपा नेता की दबंगई के विरुद्ध ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

● लाखों रुपए हड़पने का लगाया आरोप, सीएम सहित उच्चाधिकारियों से की शिकायत, नतीजा सिफर

सपा नेता द्वारा कब्जा की गई जमीन पर रखा प्लांट का समान व प्रदर्शन करते ग्रामीण।

गुरसहायगंज (कन्नौज)। सपा के एक कद्दावर नेता पर ग्रामीणों ने अमानत में खयानत करने एवं लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुये प्रदर्शन कर एक बार फिर कार्यवाही किये जानें की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेज कर कार्यवाही की मांग की लेकिन सुनवाई नही हुई। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तेरा जाकेट निवासीगण अवध बिहारी अवस्थी पुत्र जागेश्वर प्रसाद, सुमन देवी पत्नी अवध बिहारी, संजीव दुबे पुत्र रामविलास, रजनीकांत सूर्यकांत ललित कांत पुत्रगण सुरेश दत्त द्विवेदी एवं गौरव आदि ने वरिष्ठ सपा नेता/अखिलेश के बेहद करीबी जयकुमार तिवारी बउवन पर अमानत में खयानत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार में 2015 में जयकुमार तिवारी ने उक्त लोगों से उनकी जमीन की किरायेदारी का एग्रीमेंट कराया था। जिसमें यह तय हुआ था की उक्त जमीन का किराया प्रति वर्ष एक लाख 51 हजार रुपए खेत मालिकों को देंगे। एग्रीमेंट के उपरांत एक वर्ष का किराया खेत मालिकों को दिया गया। खेत मालिकों ने कहा कि जयकुमार तिवारी की मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म है जिस नाम से वह ठेकेदारी करते हैं। उन्होंने उनके खेतों में हॉट मिक्स प्लांट की मशीनें व धर्मकांटा लगाकर कई वर्ष काम किया। उनपर करीब 35 लाख रुपए किराया बाकी है। जब उक्त गणों द्वारा किराए के पैसे की मांग की गई तो उन्हें सपा नेता द्वारा लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सपा नेता के दुव्यवहार से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इससे पहले ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहित पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी कन्नौज, थाना दिवस, तहसील दिवस, स्थानिय कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र लेकर न्याय की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

करंट की चपेट में आकर किसान की मौत

फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के मवइया गांव मे पंखा चालू करते समय करंट की चपेट में आकर अधेड़ किसान गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों को जानकारी हुई तो तुरन्त उसको इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के मवईया गांव निवासी स्वर्गीय महावीर का 60 वर्षीय पुत्र हरिश्चंद्र आज सुबह अपने खेतों पर काम करने गया था। वहां से वापस घर आने के बाद खाना पीना खाकर आराम करने जा रहा था। तभी पंखा चालू करने के लिए जैसे ही उसने बोर्ड में हाथ लगाया तभी वह बिजली के करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों को जानकारी हुई तो तुरंत घटना की सूचना सरकारी 108 एंबुलेंस को दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एंबुलेंस ने उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस में रखवा दिया।

क्विक न्यूज

अवर अभियंता ने दी धमकी, 30 हजार दो नहीं तो दर्ज करा देंगे एफआईआर, आडियो वायरल

फर्रुखाबाद। विद्युत विभाग के अवर अभियंता की रिश्वतखोरी की एक कथित आडियो वायरल हो रही है। वह 30 हजार रूपये की रिश्वत न देनें पर एफआईआर की धमकी दे रहा है। डीएम से शिकायत की गयी है। विद्युत उपकेन्द्र अमृतपुर प्रथम, उपखंड राजेपुर के संविदा कर्मी नीरज राजपूत, दीपक राजपूत, अमन राजपूत, प्रवेश राजपूत नें जिलाधिकारी से शिकायत की। अवर अभियंता होरी लाल वर्मा आये दिन उन्हें परेशान किया जाता है। अबैध बसूली करने का दबाब बनाते हैं। अबैध बसूली करनें के लिए कर्मचारियों नें मना किया तो 21 जून को कायमगंज डिविजन के विद्युत उपकेंद्र हुसैनपुर तराई व हजियापुर में तबादला कर दिया। तबादला किये गये कर्मियों ने जाने से आपत्ति की है। अमृतपुर विद्युत उपकेंद्र पर पिछले एक साल से शीशराम नाम का एक फर्जी कर्मी तैनात है। कर्मियों ने आरोपी अवर अभियंता की कथित आडियो वायरल भी उपलब्ध करायी है। वह 30 हजार रूपये न देनें पर मुकदमा दर्ज करानें की धमकी दे रहा है।

घरेलू कलह से आजिज आकर मजदूर ने फांसी लगाकर दी जान

राठ (हमीरपुर)। कोतवाली के टोला गांव में एक मजदूर ने घरेलू झगड़े के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। चित्रकूट के भरकूप निवासी श्याम सुंदर ने बताया कि उसके पिता 60 वर्षीय भरत लाल पुत्र भोला व उसकी मा सुनीता कोतवाली के टोला गांव में धान की फसल लगाने के मजदूरी पर 25 दिन पहले आए थे। उसके पिता आए दिन मां के साथ झगड़ा फसाद करते थे। मंगलवार को उसके पिता ने टोला गांव के बाहर नीम के पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी है।

ससुराल आए युवक का खेत से शव बरामद, हत्या का आरोप

फतेहपुर। किशनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम महावतपुर असहट अपनी ससुराल गए 34 वर्षीय युवक का बुधवार की सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने खेत से शव बरामद किया है। मृतक के चाचा ने ससुरालीजनों पर जबरन जहर खिलाकर मार डालने का आरोप लगाया है। असोथर थाना क्षेत्र के केवटरा मजरे सातों जोगा निवासी विजय कुमार निषाद का पुत्र अमित कुमार मंगलवार की शाम चार बजे अपनी ससुराल गया था। पुलिस ने शव बरामद करते हुए विच्छेदन गृह भेजा है। कल शाम 06.30 बजे उसके भतीजे का फोन आया कि ससुराल वाले उसे जान से मारना चाह रहे हैं, जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो ससुराल वालों ने बताया कि वह शौचक्रिया के लिए गया था। काफी देर बीत जाने के बाद भी वह नहीं आया तो खोजबीन शुरू कर दी लेकिन कोई सुराग न लगा। पुलिस ने शव बरामद किया है। भतीजे को ससुरालीजनों ने जहर खिलाकर मार दिया है।

घर से निकले वृद्ध का मिला शव

फतेहपुर। घर से निकले 60 वर्षीय वृद्ध का शव नौबस्ता रोड नहर पक्की झाल के किनारे से मंगलवार की सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने बरामद कर विच्छेदन गृह भेजा है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के कठेरवा गांव निवासी स्व. शिव मंगल का पुत्र शिवलाल मंगलवार की सुबह साइकिल लेकर घर से निकल गया था। देर रात वापस न आने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन की लेकिन कोई सुराग न लगा। ग्रामीणों की सूचना पर नौबस्ता रोड नहर पक्की झाल के किनारे से वृद्ध का शव बरामद हुआ है। वही पास में ही उसकी साइकिल मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विच्छेदन गृह भेज दिया है। मृतक के भाई ने घटना को संदिग्ध बताया है।

सड़क हादसे में वृद्ध की मौत

फतेहपुर। मलवां थाना क्षेत्र के अल्लीपुर एनएच-2 में मंगलवार की देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से लगभग 62 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के नंदौली गांव निवासी स्व. शिवशंकर का पुत्र सिद्धनाथ कल्यानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौहार के आलू स्टोर में काम करता था। देर रात वह किसी काम से मलवां आया था। तभी अल्लीपुर के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विच्छेदन गृह भेज दिया।

गश खाकर तालाब में गिरी महिला, मौत

फतेहपुर। राधानगर थाना क्षेत्र के ग्राम बसावनपुर में बुधवार की दोपहर कूड़ा फेंकने गई 30 वर्षीय महिला को अचानक चक्कर आ गया जिससे वह तालाब में गिर गई और हालत बिगड़ गई। उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बसावनपुर गांव निवासी दिनेश की पत्नी निशा सिंह बुधवार की दोपहर घर का कूड़ा फेंकने तालाब के समीप गई थी। तभी उसे चक्कर आ गया और वह पानी में गिर गई। परिजन गांव वालों की मदद से उसे बाहर निकाला और सदर अस्पताल लाए, जहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

भाविपा की पांचाल शाखा ने जिला जेल में लगाए 100 फलदार वृक्ष

फर्रुखाबाद। भारत विकास परिषद के 62वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पांचाल शाखा द्वारा जिला कारागार में फतेहगढ़ में आदरणीय अपर जिला जज संजय कुमार जी, भीमसेन मुकुंद जिला कारागार अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं अध्यक्ष कन्हैया लाल जैन वित्त सचिव अनुपम पुरवार संयोजक बृजेश सिंह फतेहगढ़ शाखा के संगठन सचिव आदरणीय श्री श्याम प्रकाश श्रीवास्तव ने 100 फलदार वृक्षों को लगाया गया जिसमें आम, अमरुद, जामुन, कटहल,अनार, नींबू अन्य पेड़ लगाए। अपर जिला जज संजय कुमार, जिला कारागार अधीक्षक श्री भीमसेन मुकुंद जी को स्मृति चिन्ह एवं पटका उढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया। अध्यक्ष कन्हैया लाल जैन, सचिव देवेन्द्र नारायण श्रीवास्तव,वित्त सचिव अनुपम पुरवार, नारायण प्रसाद अग्रवाल,नमन गर्ग, योगेश वर्मा, आयुष गुप्ता,संयोजक बृजेश सिंह जी सभी व्यवस्थाएं संभाली सफल संचालन सचिव देवेन्द्र नारायण श्रीवास्तव जी ने किया।

खीरी जनपद में बेहतर कार्य करने के लिए राज्यपाल से सम्मानित हुए डॉ रविंद्र शर्मा

लखीमपुर खीरी। जनपद में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्वास्थ्य सहित अन्य सामाजिक कार्यों में बेहतर कार्य करने को लेकर सभापति इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लखीमपुर खीरी डॉ रविंद्र शर्मा लखनऊ में राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन द्वारा सर्वोत्तम कार्य पुरस्कार से एक समारोह में सम्मानित किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएमध् सभापति इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बृजेश पाठक सहित राज्य महासचिव उत्तर प्रदेश डॉ हेमा बिंदु नायक भी उनके साथ मौजूद रहे।

अध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लखीमपुर डॉ रविंद्र शर्मा ने राज्यपाल द्वारा मिले सम्मान को लेकर बताया कि वह लखीमपुर खीरी जिले में बतौर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी काम कर चुके हैं 2022 में रिटायरमेंट के बाद से उन्हें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लखीमपुर का सभापति बनाया गया थाए जिसके बाद से लगातार वह स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक कार्य संगठन के बैनर तले कर रहे थे उन्होंने तमाम स्वास्थ्य कैंप का आयोजन भी करवाया है आम जनमानस तक कैंप के माध्यम से विभिन्न बीमारियों की दवाई वितरित कराई है महिलाओं के लिए छात्रों के लिए युवा और युक्तियां के लिए भी कई कार्यक्रमों का आयोजन करवाया है। रेड क्रॉस द्वारा आपदा जैसे बाढ़, सूखा और आग के समय भी लोगों को बड़ी संख्या में सहायता कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई।

इसी के साथ एसएसबी आरटीओ व अन्य विभागों में स्वास्थ्य को लेकर तमाम जागरूकता कार्यक्रम कराए गए हैं वहीं कई अन्य सरकारी विभागों में भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बैनर तले आपदा प्रबंधन व जागरूकता कार्यक्रम किए गए हैं। करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के फल स्वरूप उन्हें एक्सीलेंस अवार्ड ;सर्वोत्तम कार्य पुरस्कारद्ध से नवाजा गया है इसमें उनकी पूरी टीम का सहयोग मिला है। साथियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में 20 लोगों को चयन कर यह पुरस्कार लखनऊ में आयोजित एक समारोह में 16 जुलाई को दिया गया है। इस सम्मान को दिलाने के लिए उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं हैं।

यौमे आशूर पर निकले अलम और ताज़ियों के जुलूस

● नम आंखों से हज़रत इमाम हुसैन की बेमिसाल कुर्बानी को किया याद

कल्लू चौधरी का ऐतिहासिक ताज़िया

संडीला (हरदोई)। शहीद ए इंसानियत पै0 हज़रत मोहम्मद (स0अ0) के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 परिजन द्वारा सत्य की रक्षा के लिए मैदान ए कर्बला में दी गयी बेमिसाल कुर्बानी की याद में नगर में अलम, ताज़िए, कारवान, गरीबां के जुलूस के आयोजन किए गए। इस दौरान नोहा ख्वानी, सीना ज़नी और छुरियों से मातम करके लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन की बेमिसाल कुर्बानी को याद किया। नगर के मोहल्ला इमाम चौक मलकाना से स्व. चौ. मो. दायम उर्फ कल्लू चौधरी के ऐतिहासिक ताज़िए के जुलूस को दोबारा से निकाला गया। इसके साथ ही नगर के मोहल्ला किसान टोला से भी ताज़ियों का मिला जुला जुलूस निकला जो बड़ा चौराहा होते हुए पुराने सिनेमा घर के पास पहुंचा। जहां कल्लू चौधरी का ताज़िया पहले से पहुंचकर थोड़े विश्राम के लिए रखा जाता है। इसके बाद ताज़ियों का एक सामूहिक जुलूस पुराने रास्ते से दरगाह रोड होकर छोटे चौराहे होता हुआ धीरे.धीरे आगे बढ़ा। देर रात इन तमाम ताज़ियों को कब्रिस्तान कर्बला में दफ्नाया जाएगा।

शिया भाईयों की ओर से फ़ाका शिकनी का अलम निकाला गया। यह अलम मण्डई से होता हुआ नगर के मुख्यमार्ग पर पहुंचा। छोटा चौराहा पर इस अलम के जुलूस में छुरियों और ज़ंजीरों से मातम किया गया। इस दौरान लोगों ने नोहा ख्वानी और सीना ज़नी भी की। इमाम बाड़ा हवेली में मजलिसे शाम ए गरीबां का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने हज़रत इमाम हुसैन की बेमिसाल कुर्बानी के विषय में विस्तार से जानकारी दी। नवीं मोहर्रम की रात अरशी रिज़वी के निर्देशन में गरीबान ए कर्बला का जुलूस जिसमें शहनाई पर मातमी धुन बजाई जा रही थी। इसके अलावा ताबूत, जुलजनह, सजे हुए ऊंट तथा अलम शामिल थे।

पूर्व सपा जिलाध्यक्ष के जन्मदिन पर दलीय सीमाएं टूटी

कानपुर देहात। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पूर्व जिलाध्यक्ष वीरसेन यादव के जन्मदिन पर कांग्रेस कमेटी कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष नरेश कटियार ने केक कटवाकर बुके भेंटकर अपने दर्जनों समर्थकों के उन्हे जन्मदिन कि बधाई दी सपा नेता के जन्मदिन पर पूरे दिन बधाई देने वालों का सुबह से ही उनके आवास पर तांता लगा रहा इसके तत्पश्चात सरवनखेड़ा, गजनेर, मूसानगर, पुखरायां आदि जगह सपाइयों व उनके चाहने वालों ने केक कटवाकर फूल माला पहनाकर बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष का जन्मदिन मनाया पुखरायां में जनसंपर्क कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वीरसेन यादव ने कहा कि मै पिछले 30 वर्षो से निरंतर आपकी सेवा में लगा हुं पूरे जनपद मे सभी के सुख दु:ख में शामिल होने का प्रयास करता हूं पिछले क़रीब डेढ़ दशक से संगठन में बिना किसी पद पर न होने के बावजूद जिस प्रकार आप सभी का सहयोग और साथ रहा उसके लिए जीवन पर्यन्त आप सभी का आभारी रहूंगा आज मेरे जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं देने वाले सभी शुभचिंतकों का हृदय से आभार एवम् धन्यवाद व्यक्त करता हूं कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रोहित कटियार, प्रहलाद निषाद, राजेंद्र सचान, वसीम कुरेशी, अंशू कटियार, अनिकेत कुमार, पवन शर्मा, सुरेंद्र यादव प्रधान, मिलन यादव प्रधान, महाराज सिंह यादव पूर्व प्रधान, नसरीन अख्तर, शेखू खान, मोहित गुप्ता, राजू यादव, पवन यादव प्रधान, अविनाश सचान, सोनेलाल यादव, रामराज सिंह, धर्मेंद्र त्रिवेदी, चौधरी सरनाम सिंह यादव, हिम्मत यादव, धर्मसिंह यादव पूर्व प्रधान, रोहित विश्वकर्मा, रोहित भोला यादव, ऋषभ यादव, रामस्नेही कटियार, देवशरण निषाद, शिवम् यादव, अजीत यादव, अमित यादव आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

राजा राजेश्वर सिंह ने बाढ़ प्रभावित गाँवों में लंच पैकेट वितरित व चौपाल लगाकर जाना पीड़ितों का हाल

निघासन। भाजपा के जनपद खीरी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश संयोजक राजा राज राजेश्वर सिंह ने निघासन विधानसभा के बाढ़ प्रभावित गाँवों में भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की व चौपाल लगाकर उनका हाल जाना। साथ ही गाँव वालों को लंच पैकेट भी वितरित किये। राजा साहब ने तारानगर, बूधनपुरवा, महादेव, बंगाली कालोनी ए जीतपुरवा, लोनियनपुरवा, टापरपुरवा समेत तमाम बाढ़ प्रभावित गावों मे भ्रमण किया व गाँव वालो को मिले प्रशासनिक सुविधाओं का अवलोकन किया व संबंधित अधिकारियों को फोन द्वारा गावों कि समस्याओं से अवगत कराया। जीतपुरवा व टापरपुरवा जैसे गाँवों में पानी अधिक होने के कारण ट्रेक्टर ट्राली द्वारा भ्रमण किया व लंच पैकेट दिये। बूधनपुरवा गाँव में कटान के कारण रोड पर रह रहे लोगों को भी लंच पैकेट घर घर जाकर वितरित किये।

उल्लेखनीय है कि विगत 15 वर्षों से राजा साहब बाढ़ जैसी क्षेत्र में आयी अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा में झण्डी से अपनी व्यवस्था से इसी प्रकार जनता के बीच उन्हे लंच पैकेट व अन्य मदद पहुँचाने का कार्य करते आ रहे हैं। राजा साहब के साथ बैलहा के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष निघासन संजय गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष अंतरवेद मंडल सौरभ शुक्ला, भाजपा पिछडा मोर्चा से माल चंद लोधी, सिरसी के सेक्टर अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, बूथ अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ए बूथ अध्यक्ष बूधन पुरवा तुशार मंडल, बूथ अध्यक्ष जमुना लोधी, रफत अली, सुरेश गुप्ता, चंद्रजीत मिश्रा समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने लंच पैकेट वितरण किये ।

न्यायालय ने आपराधिक मुकदमों में राजनीतिक प्रभाव पर चिंता जताई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश से बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह के खिलाफ दोहरे हत्याकांड के तीन दशक पुराने मामले को फिर से शुरू करते हुए कहा कि देश की न्यायिक प्रणाली अक्सर खुद को लंबे विलंब और संदिग्ध राजनीतिक प्रभाव के व्यापक मुद्दों से जूझते हुए पाती है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि 19 मई 2012 के निचली अदालत के आदेश से यह स्पष्ट है कि आरोपी छोटे सिंह के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। 19 मई 2012 के आदेश को आरोपियों और पीड़ितों दोनों ने चुनौती दी थी, लेकिन मामला 12 वर्षों से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है, जिससे मुकदमे की कार्यवाही में रुकावट आ गई, जो बेहद परेशान करने वाली बात है।

पीठ ने कहा, हमारे देश की न्यायिक प्रणाली अक्सर कानूनी कार्यवाही में लंबे विलंब और संदिग्ध राजनीतिक प्रभाव के व्यापक मुद्दों से जूझती रहती है। वर्तमान मामला उस खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जहां मामलों, विशेष रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों में, काफी देरी होती है, जिससे न्याय प्रदान में बाधा उत्पन्न होती है। शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अनुचित प्रभाव स्थिति को और भी बदतर बना देता है, जिससे निष्पक्षता को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। यह मामला चिंताजनक परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है, जिसमें दिनदहाड़े दोहरे हत्याकांड के आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति लगभग तीन दशकों से मुकदमे से बचते रहे हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, आरोपी छोटे सिंह का राजनीतिक प्रभाव तथा उसके खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने में निचली अदालत के लापरवाह रुख पर विचार करते हुए इस अदालत की राय है कि केवल आरोपी व्यक्ति का विधानसभा के लिए चुना जाना आम जनता में उसकी छवि का प्रमाण नहीं हो सकता है। पीठ ने कहा, उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, हम आरोपी छोटे सिंह के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के फैसले को खारिज करने के पक्ष में हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि दोहरे हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध के मामलों में केवल इस आधार पर अभियोजन वापस नहीं लिया जाता कि पूरी जांच के बाद आरोपपत्र में नामजद आरोपी की सार्वजनिक छवि अच्छी है। 15 जुलाई के आदेश में कहा कि जनहित में इस तरह से मुकदमा वापसी की अनुमति नहीं दी जा सकती और इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता वाले मामलों में। पीठ ने मामले से निपटने में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की भी आलोचना की। सिंह पर नौ अन्य लोगों के साथ मिलकर 30 मई 1994 को राजकुमार और जगदीश शरण पर अंधाधुंध गोलीबारी करने का आरोप है। दोनों की मृत्यु हो गई थी। मुकदमा लंबित रहने के दौरान ही सिंह 2007 में बसपा के टिकट पर उप्र विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई बसपा ने 2008 में सिंह और अन्य के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया था।

आंतरिक रूप से कमजोर करने वाले तत्वों की वजह से आतंकवाद को समर्थन मिल रहा है: पनुन कश्मीर

जम्मू। पनुन कश्मीर ने बुधवार को कहा कि आंतरिक रूप से कमजोर करने वाले तत्वों की वजह से जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को समर्थन मिल रहा है और पुलिस प्रमुख आर.आर स्वैन की यह बात सही है कि पाकिस्तान ने केंद्र शासित प्रदेश में समाज के विभिन्न तबकों में घुसपैठ की है। कश्मीरी पंडितों के अधिकारों की वकालत करने वाले पनुन कश्मीर के प्रमुख अजय च्रुंगू ने कहा, हम डीजीपी के बयानों की सराहना करते हैं, जिनमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने में आंतरिक राजनीतिक तत्वों की भूमिका की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि आंतरिक अशांति उन बड़ी वजहों में से एक है, जिनसे जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को समर्थन मिलता रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक स्वैन ने सोमवार को कहा था कि पाकिस्तान ने घाटी में तथाकथित मुख्यधारा या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बदौलत समाज के विभिन्न तबकों में घुसपैठ कर ली है।

सैन्यकर्मियों-आम नागरिकों के मारे जाने के खिलाफ प्रदर्शन, आतंकियों के सफाए की मांग उठी

भाषा। जम्मू

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक मुठभेड़ में चार सैन्यकर्मियों के शहीद होने के बाद बुधवार को जम्मू के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कड़ी कार्वाई का अनुरोध करते हुए सभी आतंकवादियों के पूरी तरह खात्मा करने के लिए अभियान चलाने की मांग की। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख राकेश कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में सैन्यकर्मियों एवं आम नागरिकों के मारे जाने तथा आतंकवाद को पाकिस्तान के कथित समर्थन के खिलाफ रैली निकाली। उन्होंने पुतले फूंके और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। कुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, हम इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। सरकार को सैन्यकर्मियों और नागरिकों को निशाना बनाने वाले विदेशी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करना चाहिए।

सोमवार शाम को शुरू हुई मुठभेड़ पिछले तीन सप्ताह में डोडा जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच तीसरी बड़ी मुठभेड़ थी। मुठभेड़ में कैप्टन बृजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही बृजेंद्र और सिपाही अजय शहीद हो गए।

सांबा में कांग्रेस और राजौरी जिले में युवा कांग्रेस इकाइयों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए और सरकार से निर्णायक आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू करने तथा स्थानीय आबादी के बीच विश्वास बहाल करने का आग्रह किया। उन्होंने घाटी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आश्वासन की भी मांग की। डोडा और भद्रवाह में भी व्यापारियों और नागरिक समाज के सदस्यों ने इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए, पाकिस्तान के पुतले फूंके और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट का आह्वान किया। उन्होंने जम्मू की पहाड़ियों में दूरदराज के गांवों की सुरक्षा के लिए ग्राम रक्षा समूहों को आधुनिक हथियारों से लैस करने की भी वकालत की। एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ताओं ने डोडा आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) के खिलाफ कड़ी कार्वाई करने का आग्रह किया।

चांदीपुरा विषाणु से पहली मौत, एनआईवी ने संक्रमण से लड़की की मौत की पुष्टि की

भाषा। अहमदाबाद

गुजरात में संदिग्ध चांदीपुरा विषाणु के कारण अब तक हुई आठ मौतों में से चार वर्षीय एक लड़की की संक्रमण के कारण मौत होने की पुष्टि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) ने की है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि यह राज्य में इस तरह की पहली मौत है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि गुजरात में अब तक चांदीपुरा विषाणु संक्रमण के 14 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इनमें से आठ मरीजों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सभी के नमूने पुष्टि के लिए पुणे स्थित एनआईवी भेजे गए हैं। साबरकांठा के मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी (सीडीएचओ) राज सुतारिया ने कहा, अरावली के मोटा कंथारिया गांव की चार वर्षीय बच्ची, जिसकी साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में मौत हो गई थी, का नमूना चांदीपुरा विषाणु के लिए सकारात्मक पाया गया है। राज्य में चांदीपुरा विषाणु संक्रमण से यह पहली मौत है।

उन्होंने बताया कि साबरकांठा जिले से तीन अन्य लोगों के नमूने एनआईवी को भेजे गए थे, जिनमें संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। इनमें से एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि दो अन्य ठीक हो गए हैं।

मंत्री पटेल ने कहा कि संदिग्ध चांदीपुरा विषाणु संक्रमण के मामले साबरकांठा, अरावली, महिसागर, खेड़ा, मेहसाणा और राजकोट जिलों से सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के दो और मध्य प्रदेश के एक मरीज का भी राज्य के अस्पतालों में इलाज किया गया है। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्रों के 26 आवासीय क्षेत्रों में 44,000 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। चांदीपुरा विषाणु से बुखार होता है, जिसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, तथा तीव्र इंसेफेलाइटिस (मस्तिष्क की सूजन) होती है। यह रोगजनक रैबडोविरिडे परिवार के वेसिकुलोवायरस जीनस का सदस्य है। यह मच्छरों, बालू मक्खी जैसे कीट पतंगों द्वारा फैलता है। मध्य भारत में 2003-2004 में हुए प्रकोप के कारण आंध्र प्रदेश और गुजरात में 56-75 प्रतिशत तक मृत्यु दर देखी गई थी, जिसमें विशिष्ट मस्तिष्क ज्वर के लक्षण थे।

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

● आरोपी की पहचान काजिम अंसारी के रूप में हुई और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया

दरभंगा, पटना(भाषा)। बिहार पुलिस ने प्रदेश के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी थी। जीतन सहनी (70) की सोमवार रात दरभंगा जिले में उनके पैतृक घर पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी। दरभंगा पुलिस ने एक बयान में कहा, आरोपी की पहचान सुपौल बाजार इलाके के निवासी काजिम अंसारी (40) के रूप में हुई है। इसी इलाके में पूर्व मंत्री का पैतृक घर भी स्थित है। अंसारी ने अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। पुलिस के अनुसार, अंसारी ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने अपनी जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रखकर सहनी के पिता से 1.5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वह पैसे लौटा नहीं पाने के कारण इस भूखंड को वापस नहीं ले पा रहा था। इससे पहले, दिन में पुलिस ने जीतन सहनी की हत्या की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए अंसारी समेत चार लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने कहा था, सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से पता चला है कि इन चार लोगों ने 15 जुलाई की रात करीब साढ़े 10 बजे जीतन सहनी के घर में प्रवेश किया था और वे कुछ देर बाद वापस लौट गए थे। इस मामले की जांच के लिए जिला पुलिस के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बिहार के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख सम्राट चौधरी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं ने सहनी के पिता की हत्या किए जाने की निंदा की है।

ओमान तट पर डूबे टैंकर पर सवार 13 भारतीयों में से आठ को बचाया गया

नई दिल्ली(भाषा)। ओमान तट के नजदीक हाल में डूब गए कोमोरोस के ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर सवार चालक दल के सदस्यों का पता लगाने के लिए संचालित बचाव अभियान में भारत के एक युद्धपोत ने आठ भारतीयों और एक श्रीलंकाई नागरिक को बचाया। भारतीय नौसेना ने बुधवार रात को यह जानकारी दी। नौसेना ने बताया कि जहाज 15 जुलाई को ओमान में रास मदराख से दक्षिण पूर्व में करीब 25 समुद्री मील दूर समुद्र में डूब गया था और ओमान के अधिकारिएं के साथ मिलकर बचाव तथा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र (एमएससी) ने कहा कि मालवाहक पोत एमटी फाल्कन प्रेस्टीज पर सवार चालक दल के सदस्यों की संख्या 16 थी जिनमें 13 भारतीय और तीन श्रीलंकाई थे। उसने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक सदस्य मृत पाया गया। हालांकि उसकी नागरिकता का अभी तक पता नहीं चला है।

कांवड़ मार्ग पर खानपान की दुकानों पर मालिकों का नाम प्रदर्शित के फैसले पर विपक्ष का हमला

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने-पीने की सभी दुकानों पर मालिकों का नाम प्रदर्शित करने का आदेश जारी किया। वहीं कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। स्थानीय पुलिस प्रमुख अभिषेक सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और असदुद्दीन ओवैसी ने ही एक्स पर साझा किया। सिंह ने खाने-पीने की दुकानों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश के बारे में पूछे जाने पर बताया, जिले में कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। मार्ग पर सभी होटल, ढाबे, ठेले वालों से अपने मालिकों या फिर वहां काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने को कहा गया है। उन्होंने बताया, यह इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम किसी कांवड़िए के अंदर ना रहे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सरकार प्रायोजित कट्टरता करार दिया। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले की तुलना दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और जर्मनी में यहूदिया के बहिष्कार से की। खेड़ा ने इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सिर्फ राजनीतिक दलों को ही नहीं सभी सही सोच वाले लोगों और मीडिया को इस राज्य प्रायोजित कट्टरता के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। हम भाजपा को देश को अंधकार युग में वापस धकेलने की अनुमति नहीं दे सकते। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार, अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले।

सरकार उत्तर प्रदेश में करीब 800 दिव्यांग जन को सहायक उपकरण वितरित करेगी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम में करीब 800 दिव्यांग जन को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। बुधवार को जारी बयान में कहा गया कि सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि यह शिविर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के तहत सहायक यंत्रों ाउपकरणों की खरीदाफिटिंग के लिए दिव्यांगजन को सहायता (एडीआईपी) मुहैया कराने की योजना का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में पहले से चिह्नित किए गए 791 दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे तथा इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। बयान में बताया गया कि इस कार्यक्रम में वितरित किए जाने वाले सहायक उपकरणों में मोटर चालित तिपहिया साइकिल, हस्तचालित तिपहिया साइकिल, मोड़ी जा सकने वाली व्हीलचेयर , वॉकर , चलने में मददगार छड़ियां, ब्रेल किट , रोलेटर , कान के पीछे लगाए जाने वाले (बी.टी.ई.) श्रवण यंत्र, सी.पी. चेयर , सेंसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक सुगम्य छड़ियां, स्मार्टफोन, कृत्रिम अंग आदि शामिल होंगे। यह पहल दिव्यांगजन के सशक्तीकरण और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के प्रयासों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। इन प्रयासों से उन्हें एक सार्थक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल सकेगी। भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम इस शिविर का आयोजन करेगा। यह निगम दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है।

एचआईवी पॉजिटिव सेवानिवृत्त सैनिक के लिए मुआवजा जमा कर दिया गया है : वायु सेना ने न्यायालय में कहा

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय वायुसेना ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि 2002 में जम्मू-कश्मीर के सांबा में एक सैन्य अस्पताल में दूषित रक्त चढ़ाने के कारण एचआईवी संक्रमित हुए जवान (अब सेवानिवृत्त) को 18 लाख रुपए दिए गए हैं और मुआवजे की शेष राशि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा करा दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत्त सैनिक की याचिका पर वायुसेना को उन्हें लगभग 1.5 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश पिछले वर्ष 26 सितंबर को दिया था। इस सैनिक को 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन पराक्रम के दौरान बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उन्हें एक यूनिट रक्त चढ़ाना पड़ा था।

शीर्ष अदालत ने इस साल अप्रैल में इस मामले में सितंबर 2023 के अपने फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करने संबंधी एक याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व सैनिक ने उच्चतम न्यायालय के 2023 के फैसले में जारी निर्देशों की अवमानना का आरोप लगाने वाली एक याचिका दाखिल की जिस पर मंगलवार को पीठ में सुनवाई हुई।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मामले में अनुपालन हलफनामा दायर किया है। पीठ में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराई गई राशि पूर्व सैनिक को जारी की जाए। इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे एक वकील ने सैनिक की नियमित चिकित्सा जांच के बारे में बताया और कहा कि पीठ इसके लिए उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में रेफर करने पर विचार कर सकती है। पीठ ने कहा कि चूंकि वह व्यक्ति अजमेर में रहता है इसलिए उसे असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जयपुर में अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

न्यायमित्र से पीठ ने इस मुद्दे पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ चर्चा करने को कहा ताकि इसे सुलझाया जा सके और मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। उच्चतम न्यायालय ने पांच मार्च को निर्देश दिया था कि 18 लाख रुपए व्यक्ति को दिए जाएं तथा शेष राशि दो सप्ताह के भीतर अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराई जाए। पीठ ने यह भी आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को दिव्यांगता पेंशन देने के लिए उसकी दिव्यांगता को 100 फीसदी समझा जाए।

असम में मुस्लिम आबादी अब चालिस प्रतिशत जनसांख्यिकी परिवर्तन बड़ा मुद्दाः हिमंत

भाषा। रांची

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को दावा किया कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी बढ़कर अब 40 प्रतिशत हो गई है और पूर्वोत्तर राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के झारखंड चुनाव सह-प्रभारी ने यहां पार्टी की एक बैठक के इतर यह टिप्पणी की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैं असम से संबंध रखता हूं और जनसांख्यिकी परिवर्तन मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। मेरे राज्य में मुस्लिम आबादी अब 40 प्रतिशत है, जो 1951 में 12 प्रतिशत थी। यह मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि जीवन-मरण का सवाल है। इससे पहले, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि झारखंड के आदिवासी इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में घुसपैठियों के खिलाफ एक मजबूत कार्ययोजना को शामिल करेगी। शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला करते हुए उन पर झारखंड को मिनी बांग्लादेश में बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, घुसपैठिए झारखंड आते हैं और आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं झारखंड में एक ऐसे कानून की मांग करता हूं जिसमें यह प्रावधान हो कि आदिवासी लड़कियां घुसपैठियों से शादी नहीं कर सकतीं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, पिछले पांच साल में राज्य में कोई विश्वविद्यालय या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला गया। विकास कार्य ठप हो गए। युवाओं को न तो नौकरी दी गई और न ही बेरोजगारी भत्ता। शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने झारखंड की 14 में से नौ सीट जीतीं और 51 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की।

पेज 1 का शेष

उप चुनाव...

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे कार्यकर्ताओं से ज्यादा से ज्यादा मिलें। उनका मनोबल बढ़ाएं। समस्याओं के बारे में जानकारी लें और संतुष्ट करें। जिससे उन्हें लगे कि पार्टी में उनका सम्मान है। सरकार और संगठन उनके साथ है साथ ही मंत्री कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए लंबा इंतजार भी न कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाद कर लोगों को बताएं कि पूर्व की सरकारों में कानून-व्यवस्था का क्या हाल था। किसने संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। गांवों में रात्रि विश्राम के साथ नुक्कड़ सभाएं करें और विपक्ष की पोल खोलें। सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहें। विपक्ष के हर झूठ का तत्काल जवाब दें। मंत्रियों के प्रत्येक ग्रप में प्रभारी मंत्री, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्री शामिल हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सूर्यप्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, अनिल कुमार, सुनील शर्मा, लक्ष्मीनारायण चौधरी, जयवीर सिंह, योगेन्द्र उपाध्याय, राकेश सचान, संजय निषाद, अनिल राजभर, आशीष पटेल, सोमेन्द्र तोमर, केपी मलिक, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, गुलाब देवी, बृजेश सिंह, कपिलदेव अग्रवाल, संदीप सिंह, अजीत पाल सिंह, नितिन अग्रवाल, दयाशंकर सिंह, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा, दयाशंकर मिश्र, रविन्द्र जायसवाल और रामकेश निषाद शामिल रहे।

दिल्ली का...

लंबी कतारें देखना आम बात है। हालांकि, यह खाने के शौकीनों को उनके पसंदीदा व्यंजन दाल मखनी, नान और दही कबाब मिलता था। 28 वर्षीय एकांउटेंट समीक्षा ठाकुरने बताया कि वह बचपन से लेकर अब तक 100 से अधिक बार इस जगह पर आ चुकी हैं।

अजीत...

नेता 20 जुलाई को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल होंगे। चार एनसीपी (अजीत पवार) नेताओं के इस्तीफे को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि पुणे का जुड़वां उपग्रह शहर पिंपरी-चिंचवाड़ पिछले तीन दशकों से अजीत पवार का गढ़ रहा है। एनसीपी (एपी) छोड़ने का गवाहणे का फैसला इस तथ्य से उपजा है कि पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में भोसरी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने से साफ इनकार कर दिया था, इस आधार पर कि भोसरी से भाजपा के महेश लांडगे दो बार जीते हैं। एनसीपी (एपी) के जानकार सूत्रों ने बताया कि गवाहणे ने हाल ही में अजीत पवार से मुलाकात की थी, जिन्होंने उनसे पूछा पार्टी को भोसरी सीट पर क्यों चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि यह भाजपा का है, जहां से उसके उम्मीदवार दो बार जीते हैं। गवाहणे और लांडगे कई वर्षों से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। वे पार्टी में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। गवाहणे के एनसीपी (एसपी) में शामिल होने का कारण यह है कि शरद पवार ने कथित तौर पर उन्हें आश्वासन दिया है कि वे उन्हें भोसरी से पार्टी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारेंगे।

विदेशी...

गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। सेना ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वह जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त और समन्वित अभियानों की एक श्रृंखला चला रही है, ताकि सीमा पार से घुसपैठ करने वाले विदेशी आतंकवादियों को खत्म किया जा सके जो जम्मू क्षेत्र के उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जिलों के ऊपरी इलाकों में और उसके बाद कश्मीर की ओर बढ़ रहे थे। सेना ने कहा, उत्तरी कमान की सभी टुकड़ियां जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के संकट को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए अथक अभियान जारी रहेंगे। जम्मू में, कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को घोषणा की कि वह बढ़ती आतंकी गतिविधियों को रोकने में भाजपा नीत सरकार की कथित विफलता और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले उपराज्यपाल को बेलगाम शक्तियां देने के उसके फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। जम्मू में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख विकार रसूल वानी ने कहा, आंदोलन राज्य स्तर पर शुरू होगा और आने वाले दिनों में जिला और ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाएगा।

हरियाणा में...

बैच को उम्र में पांच वर्षों की छूट दी जाएगी। इसके बाद के बैच के लिए यह छूट तीन वर्षों के लिए होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप-डी यानी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। यह पीएम नरेंद्र मोदी की लोकहित की योजना है और इसके माध्यम से स्किल और एक्टिव युवा तैयार होंगे। 14 जून, 2022 को लागू की गई इस योजना के तहत भारतीय सेनाओं में चार वर्षों के लिए अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। चार वर्षों की सेवा के बाद कुल अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत स्थायी होंगे और बाकी रिटायर हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही फैसला किया है कि चार वर्षों के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को अर्द्ध-सैनिक बलों की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार पुलिस में कांस्टेबल, वन विभाग में फोरेस्ट गार्ड, माइनिंग गार्ड, जेल विभाग में जेल वार्डन तथा स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। मालूम हो कि एसपीओ के तहत सेना व अर्द्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को नियुक्त किया जाता है। सीएम ने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप-सी के सिविल पदों के लिए सीधी भर्ती में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। वहीं ग्रुप-डी के पदों में एक प्रतिशत आरक्षण की सुविधा होगी। ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट मिलेगी। इस मौके पर मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ व सीएम के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे भी मौजूद रहे।

अग्निवीरों....

लौटने के बाद निजी क्षेत्र में आसानी से नौकरी मिल सके, इसके लिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आर्म्स लाइसेंस मिलेंगे। इसी तरह से विभिन्न विभागों तथा बोर्ड-निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैरिट स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई अग्निवीर अपना खुद का उद्योग लगाना चाहता है तो सरकार उसे पांच लाख रुपये तक का ब्याज रहित ऋण मुहैया कराएगी।

केजरीवाल...

व्यक्ति रिहाई के लिए अधिकृत है। उसे रिहा किया जाना चाहिए लेकिन उसकी रिहाई न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई है और मुख्यमंत्री होने के नाते वह जमानत के हकदार हैं। सीबीआई की ओर पेश हुए अधिवक्ता डीपी सिंह ने केजरीवाल द्वारा दाखिल दो याचिकाओं का विरोध किया। मुख्यमंत्री ने एक अर्जी में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है जबकि दूसरी अर्जी में जमानत देने का अनुरोध किया है।

विधि मंत्रालय...

जब तक कि उन्हें नवीनीकृत न किया जाए। भारत में राजकोषीय और कर कानूनों में सनसेट क्लॉज का अक्सर इस्तेमाल किया जाता रहा है, जैसे कि कर अवकाश और मुद्रा नियंत्रण विनियम। संविधान में संसद और विधान सभा सीटों के लिए आरक्षण के लिए 10 साल की सनसेट अवधि का प्रावधान है (अनुच्छेद 334)। ऐसे प्रावधान विधि निर्माताओं द्वारा यह स्वीकारोक्ति हैं कि कानून अनंत काल के लिए नहीं बनाया जाता है और यह मान्यता है कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं - चाहे वह एक साल हो या पांच साल। इस सीख को कानून के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित करने की आवश्यकता है, यह स्वीकार करते हुए कि सामाजिक परिस्थितियां और संस्थागत व्यवहार (जैसे आर्थिक परिस्थितियां) भी समय के साथ बदलती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कानूनों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे कानून अधिक से अधिक विशिष्ट होते जा रहे हैं, इस बात की अधिक आवश्यकता है कि एक तंत्र हो जो यह जांच सके कि स्थिति को संभालने में कानून ने कैसा प्रदर्शन किया है और क्या और कैसे, उस स्थिति के आसपास की परिस्थितियां बदल गई हैं।

सरकार ने एवियन फ्लू खतरे पर की उच्चस्तरीय बैठक

नई दिल्ली। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा मंगलवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में विशेषज्ञों ने एवियन इन्फ्लूएंजा से निपटने के लिए गहन निगरानी और बेहतर समन्वय की वकालत की। कृषि भवन में आयोजित विचार-मंथन सत्र में विभिन्न सरकारी निकायों और अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे के संदर्भ में रणनीति तैयार करने के लिए एक साथ आए। बैठक में, विशेष रूप से हाल के प्रकोपों के मद्देनजर, एवियन इन्फ्लूएंजा की चुनौती से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिसमें इस बीमारी द्वारा प्रजातियों की बाधाओं को पार करने की क्षमता को सामने रखा गया। एक सरकारी बयान में कहा गया, हाल ही में अमेरिका में डेयरी मवेशियों में एचपीएआई (अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा) का प्रकोप, जिसका अन्य स्तनधारियों में भी फैलाव हुआ है, एचपीएआई की महामारी क्षमता को रेखांकित करता है। विशेषज्ञ समिति ने बहुआयामी दृष्टिकोण की सिफारिश की, जिसमें गहन पर्यावरणीय निगरानी, अद्यतन प्रोटोकॉल और मानव-पशु-वन्यजीव इंटरफेस पर बेहतर समन्वय शामिल है। बैठक में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को गति देने में भारत के पॉल्ट्री क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया, साथ ही एचपीएआई के बार-बार होने वाले प्रकोपों से उत्पन्न खतरे पर भी ध्यान दिया गया। विशेषज्ञों ने संभावित प्रकोपों का शीघ्र पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम एक मजबूत निगरानी प्रणाली की आवश्यकता की जरूरत बताई।

सबका साथ, सबका विकास की जरूरत नहीं : शुभेंदु अधिकारी

कहा, हम उनका साथ देंगे जो हमारे साथ हैं

भाषा। कोलकाता

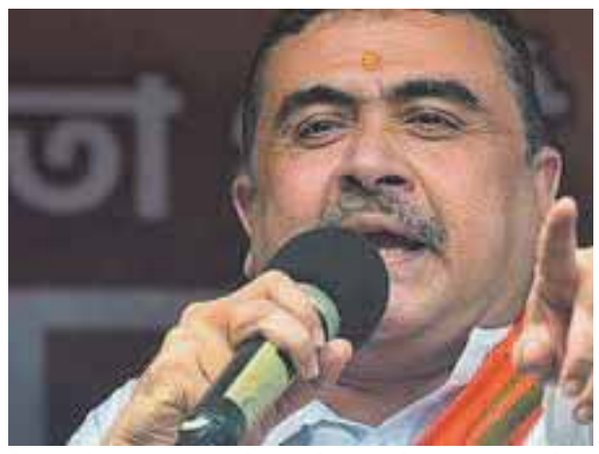

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने हालिया लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से कम समर्थन मिलने को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास की जरूरत नहीं है और इसके बजाय उन्होंने हम उनके साथ जो हमारे साथ का प्रस्ताव दिया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तारित सत्र को बुधवार को संबोधित करते हुए अधिकारी ने यह भी कहा कि पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की जरूरत नहीं है। हालांकि, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया और कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का पूरा समर्थन करते हैं।

अधिकारी ने भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तारित सत्र को संबोधित करते हुए कहा, मैंने राष्ट्रवादी मुस्लिमों की भी बात की है। हम सभी सबका साथ, सबका विकास की बात किया करते हैं, लेकिन आगे से अब मैं यह नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इसके बजाय यह हम उनके साथ जो हमारे साथ होना चाहिए...अल्पसंख्यक मोर्चा की कोई जरूरत नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में करीब 30 फीसदी अल्पसंख्यक मतदाता हैं, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को हालिया लोकसभा चुनाव में दक्षिणी पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में शानदार जीत हासिल करने में मदद की। वहीं, उत्तर बंगाल में वाम-कांग्रेस गठबंधन और तृणमूल के बीच मतों के विभाजन ने भाजपा को क्षेत्र में कई सीट हासिल करने में मदद की। साल 2014 में भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया था और 2019 में एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर दिया था। अधिकारी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के जिहादी गुंडों ने हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया। अधिकारी ने कहा, पश्चिम बंगाल में, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। तृणमूल के जिहादी गुंडे ऐसा नहीं होने देंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव राज्य में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू कर ही संभव है। हम राष्ट्रपति शासन लागू कर पिछले दरवाजे से राज्य में सत्ता हथियाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा, लोगों के जनादेश से चुनाव जीतने पर ही हम सत्ता में आएंगे। लेकिन उसके लिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना होगा। बाद में, अपनी टिप्पणियों से विवाद उत्पन्न हो जाने पर अधिकारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आधार पर लोगों के बीच विभाजन करने में यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा, मेरे बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग राष्ट्रवादी हैं, वे इस देश और पश्चिम बंगाल के लिए खड़े हैं, हमें उनके साथ होना चाहिए। जो लोग हमारे साथ नहीं खड़े हैं, जो देश और पश्चिम बंगाल के हित के खिलाफ काम करते हैं, हमें उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है। अधिकारी ने कहा, साथ ही, ममता बनर्जी की तरह हमें लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में नहीं बांटना चाहिए तथा उन्हें भारतीय के रूप में देखना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

अधिकारी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी टिप्पणी किसी समुदाय के खिलाफ नहीं थी। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कुछ चीजें महसूस की गईं, उनमें से एक यह है कि तृणमूल के आतंक के राज के कारण समान अवसर नहीं मिल पाने के बावजूद भाजपा उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी दल के रूप में उभरी है। दूसरा, यह कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। उन्होंने कहा, तीसरा, यह कि माकपा ने हिंदू मतों को विभाजित करने में तृणमूल की मदद की। इसलिए, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को यह पता होना चाहिए कि अगर वे एकजुट नहीं हुए तो भविष्य में पश्चिम बंगाल में वे कहीं के नहीं रह जाएंगे।

कासगंज पहुंचे स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ हरि नारायण साकार

हाथरस भगदड़ कांड

भाषा। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ की घटना के बाद सुर्खियों में आए स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा बुधवार को कासगंज के पटियाली स्थित अपने आश्रम पहुंचे। भोले बाबा के वकील ए.पी. सिंह ने कासगंज में संवाददाताओं से कहा, वह (भोले बाबा) अपने आश्रम पहुंच गए हैं और यहीं रहेंगे। वह यहां आश्रम से ही आए हैं। वह कभी किसी के घर, होटल या किसी दूसरे देश में नहीं गए। उन्होंने कहा कि कासगंज बाबा की जन्मस्थली है और वह आखिरी बार 2023 में एक दिन के लिए यहां आए थे और इससे पहले वे 2013 में यहां आए थे। हाथरस के सिकंदराराऊ इलाके में दो जुलाई को स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) और न्यायिक आयोग का गठन किया है। भगदड़ के मामले में दर्ज मुकदमे में बाबा का नाम आरोपी के तौर पर शामिल नहीं था।एसआईटी ने गत जुलाई को राज्य सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में भगदड़ के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया। एसआईटी रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन की ओर से चूक की ओर भी इशारा किया गया। रिपोर्ट में भगदड़ के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया और दावा किया गया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सूत्रों ने बताया कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने इस आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया।

सीबीएसई विचार कर रहा है कि साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं कब और कैसे आयोजित की जाएं

नई दिल्ली। सीबीएसई नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (एनसीएफ) के तहत साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर दुविधा में है और इस बाबत तीन विकल्पों पर चर्चा कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सेमेस्टर प्रणाली पर भी विचार कर रहा है जिसमें द्विवार्षिक परीक्षाएं शामिल हैं। वर्तमान में, कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी-मार्च में आयोजित की जाती हैं। अधिकारियों ने बताया कि विचार-मंथन जारी है और अब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है कि वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की योजना कब और किस प्रारूप में लागू की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया, तीन संभावित विकल्पों पर चर्चा की गई है, जिनमें से एक सेमेस्टर प्रणाली में परीक्षा आयोजित करना है। इसमें पहली बोर्ड परीक्षा जनवरी-फरवरी में और दूसरी मार्च-अप्रैल में आयोजित करना है या फिर कंपार्टमेंट या सुधार परीक्षाओं के साथ जून में बोर्ड परीक्षाओं का दूसरा चरण आयोजित किया जाए। उन्होंने बताया, जिस तरह से हमारा शैक्षणिक कैलेंडर बनाया गया है, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं का कार्यक्रम और सीबीएसई स्कूल देश भर में और विदेश तक में होने के चलते भौगोलिक चुनौतियां हैं जिससे सेमेस्टर प्रणाली कम व्यवहार्य लगती है। बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से कहा है कि मौजूदा व्यवस्था में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए 150 से अधिक कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस प्रक्रिया में कम से कम 310 दिन लगते हैं, जिसमें विद्यार्थियों की सूची भरना, केंद्र अधिसूचना, रोल नंबर जारी करना, प्रैक्टिकल आयोजित करना, लिखित परीक्षा, परिणाम घोषित करना, सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन शामिल है। दो परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए कम से कम 55 दिन की जरूरत है। अब सीबीएसई के सामने चुनौती यह है कि दूसरे चरण के लिए यह व्यापक कवायद कब और कैसे दोहराई जाए। अधिकारी ने कहा, फरवरी से पहले परीक्षाएं आयोजित करने में अपनी तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में सर्दियां बेहद कठिन होती हैं। वर्तमान में बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी के आसपास शुरू होती हैं, इसलिए पर्याप्त अंतराल रखने के लिए तिथियों पर भी उसी के अनुसार काम करना होगा। उन्होंने कहा, दूसरा विकल्प कंपार्मेंट या सुधार परीक्षा के साथ जून में परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित करना हो सकता है। हालांकि, इनमें से कोई भी विकल्प अंतिम नहीं है। हम अब भी विचार-विमर्श कर रहे हैं और व्यापक परामर्श जारी है। यह संभव है कि प्रक्रिया के दौरान और भी विकल्प सामने आएं। मंत्रालय की योजना 2024-25 शैक्षणिक सत्र से वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षाएं शुरू करने की थी। हालांकि, इसे एक साल के लिए टाल दिया गया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा तैयार की गई नई एनसीएफ में कक्षा 11 वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक सेमेस्टर प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले अक्टूबर में पीटीआई-भाषा को दिए एक साक्षात्कार में बताया था कि छात्रों के लिए साल में दो बार बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा।

इंदिरा, राजीव की हत्या पर अमित मालवीय की टिप्पणी का भाजपा ने किया बचाव

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या पर अपने सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय की टिप्पणी का बुधवार को बचाव करते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। एक दिन पहले मालवीय की टिप्पणी के लिए कांग्रेस ने उन्हें बर्खास्त करने और भाजपा से माफी मांगने की मांग की थी। मालवीय ने कहा था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या उनके राजनीतिक फैसलों के लिए की गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने पीटीआई-भाषा से कहा, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। उन्हें सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने क्या किया। गौतम ने आरोप लगाया, उन्होंने आपातकाल लगाया, लोकतंत्र और संविधान की हत्या की। प्रधानमंत्री बनने के लिए, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विभाजन का का नेतृत्व किया। लाखों लोग मारे गए।

भाजपा नेता ने कहा कि लोगों को देश का इतिहास जानना चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही इसे दबाने का प्रयास किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास की पृष्ठभूमि में सोमवार शाम एक टीवी बहस के दौरान मालवीय ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, इससे पहले कि कांग्रेस यह दावा करे कि उनके अपने नेताओं की हत्या हुई है तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनके (नेताओं) द्वारा लिए गए राजनीतिक निर्णयों के कारण उनकी हत्या की गई...प्रधानमंत्री रहते हुए भी कई बार इंदिरा गांधी के काफिले पर पथराव हुआ। मालवीय ने कहा, इंदिरा और राजीव दोनों के साथ बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं, हम उसकी निंदा करते हैं लेकिन गांधी परिवार की संतान आज वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी पर हमले और मौत की कामना कर रही हैं...। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं के संदर्भ में असंवेनदशील टिप्पणियां करने के लिए मालवीय को बर्खास्त किया जाए तथा भाजपा देश से माफी मांगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने नड्डा को लिखे पत्र में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को मालवीय की टिप्पणियों को खारिज करना चाहिए।रमेश ने नड्डा को लिखे पत्र में कहा, मैं भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय द्वारा की गई हालिया टिप्पणियों के संबंध में गहरी चिंता और निराशा के साथ लिख रहा हूं।

केदारनाथ मंदिर से सोने की चोरी के आरोपों पर शंकराचार्य के समर्थक और मंदिर समिति प्रबंधन अब आमने-सामने

भाषा। रुद्रयाग

केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से सोने की कथित चोरी संबंधी आरोपों पर श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति प्रबंधन और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक आमने-सामने आ गए हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने गर्भगृह से सोने की चोरी के आरोपों को बेबुनियाद और तथ्यहीन बताते हुए आरोप लगाने वालों से विवाद खड़ा करने की बजाय सक्षम स्तर पर मामले की जांच की मांग कराने का अनुरोध किया।अजय ने इन आरोपों को षड्यंत्र बताते हुए स्पष्ट किया कि दानदाता द्वारा केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्णजड़ित करने की इच्छा प्रकट की गई थी और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का परीक्षण कर उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई।

उन्होंने कहा कि बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम-1939 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ही दानदाता से दान स्वीकारा गया और इसके लिए विधिवत प्रदेश शासन से अनुमति ली गई।मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने का कार्य किया गया।अजय ने यह भी स्पष्ट किया कि गर्भ गृह को स्वर्ण मंडित करने का कार्य दानदाता ने स्वयं किया और उन्होंने ही अपने स्तर से स्वर्णकार से तांबे की प्लेटें तैयार करवाईं और फिर उन पर सोने की परतें चढ़ाई गईं।उन्होंने कहा कि दानदाता ने अपने स्वर्णकार के माध्यम से ही इन प्लेटों को मंदिर में स्थापित भी कराया।मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सोना खरीदने से लेकर दीवारों पर जड़ने तक का सम्पूर्ण कार्य दानी द्वारा कराया गया तथा मंदिर समिति की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। न्होंने कहा कि कार्य होने के बाद दानदाता ने सभी आधिकारिक बिल एवं वाउचर मंदिर समिति को दे दिए थे, जिसके बाद नियमानुसार इसे स्टॉक बुक में दर्ज किया गया।दानस्वरूप किए गए इस कार्य हेतु दानी व्यक्ति अथवा किसी फर्म द्वारा मंदिर समिति के समक्ष किसी प्रकार की शर्त नहीं रखी गई और न ही उन्होंने मंदिर समिति से आयकर अधिनियम की धारा-80 जी का प्रमाण पत्र मांगा। अजय ने कहा कि उक्त दानदाता ने 2005 में श्री बदरीनाथ मंदिर के गर्भगृह को भी स्वर्ण जड़ित किया था लेकिन अब एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत विद्वेषपूर्ण आरोप लगाए जा रहे हैं।

दूसरी ओर, ज्योर्तिमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में हुई सोने की चोरी की जांच कराए जाने की मांग के समर्थन में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित भी आ गए हैं।

केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने वीडियो संदेश जारी कर केदारनाथ सोना प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने संदेश में कहा कि वे (तीर्थ पुरोहित) शुरुआती दौर से ही केदारनाथ धाम में चांदी और सोने की परत लगाए जाने का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोध के बावजूद मंदिर समिति प्रशासन की ओर से पहले चांदी और उसके बाद सोने की परत लगाई गई। केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष किशन बगवाड़ी ने आरोप लगाया कि गर्भगृह से सोने की 528 प्लेटों के साथ ही चांदी की 230 प्लेटें भी गायब हैं। उन्होंने मंदिर समिति से सवाल किया कि आखिर 230 किलो सोना कहां गया। इसके अलावा, उन्होंने पूर्व में लगी चांदी के बारे में भी मंदिर समिति से जवाब मांगा है। बगवाड़ी ने कहा कि तीर्थ पुरोहित शुरू से ही उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकार उसे अनसुना करती रही है।उत्तराखंड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने कहा कि गर्भगृह में लगाए गए सोने की गुणवत्ता को लेकर भी उन्हें संदेह है और उनका सवाल यह है कि मंदिर में लगा सोना तांबे में कैसे बदल गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व में गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में जांच समिति बनाने की बात कही थी लेकिन उसकी रिपोर्ट के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है।

झारखंड में झामुमो की सत्ता में वापसी हुई तो मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे: शिवराज

रांची। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को दावा किया कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन सरकार सत्ता में वापस आती है तो झारखंड के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे।हटिया में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड और इसकी परंपराओं को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा, अगर झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन फिर से सत्ता में आता है तो राज्य के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण राज्य की जनसांख्यिकी बदल रही है। चौहान ने आरोप लगाया कि घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार पर हमला करते हुए चौहान ने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्य के लोगों को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा, सरकार ने युवाओं को नौकरी और बेरोजगार युवकों को भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन, इसने न तो किसी को नौकरी दी और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया। इसने युवाओं को धोखा दिया है। चौहान ने कहा, इसी तरह, महिलाओं को खाना पकाने की लागत के रूप में 2,000 रुपए प्रति माह और बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ऋण देने का वादा किया गया था। लेकिन, राज्य की किसी भी महिला को इसका लाभ नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय झामुमो नीत सरकार खनिज और रेत की लूट में लिप्त रही। चौहान ने दावा किया, लूट इतनी बड़ी थी कि कई पहाड़ियां गायब हो गईं। झारखंड चुनाव के प्रभारी चौहान ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े चार साल में राज्य में 7,812 हत्याएं, 7,115 बलात्कार, 8,552 दंगे, 2,721 लूट और 485 डकैती की घटनाएं दर्ज की गईं। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि सिर्फ भाजपा ही झारखंड को बचा सकती है और इसे समृद्ध बना सकती है ताकि लोगों को रोजी-रोटी के लिए अन्य राज्यों में पलायन न करना पड़े।

तमिलनाडु में तेज रफ्तार वैन ने श्रद्धालुओं को कुचला

तंजावुर (तमिलनाडु)। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में बुधवार की सुबह तंजावुर-तिरुचिरापल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार वाहन ने चार महिलाओं समेत पांच श्रद्धालुओं को कुचल दिया। हादसे में एक अन्य महिला घायल हो गई। पुलिस ने इसकी जानकरी दी। पुलिस ने बताया कि पुडुकोट्टई जिले के रहने वाले सभी श्रद्धालु सड़क मार्ग से पदयात्रा करते हुए समयपुरम मरिअम्मां मंदिर जा रहे थे कि यहां से 30 किलोमीटर दूर वलंबकुडी गांव के पास तिरुचि जा रही वैन ने उन्हें कुचल दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में चार महिलाओं समेत पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में घायल एक महिला को उपचार के लिए तंजावुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शोक प्रकट करते हुए पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। एक बयान में उन्होंने उपचाराधीन महिला को भी एक लाख रुपए देने की घोषणा की।

समुद्री अनुसंधान पोत बनाएगा जीआरएसई

कोलकाता। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) ने एक महासागर अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। ीआरएसई ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि 42 महीनों में पोत के निर्माण के लिए जीआरएसई और एनसीपीओआर अधिकारियों के बीच लगभग 840 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। कोलकाता मुख्यालय वाली युद्धपोत निर्माता कंपनी ने कहा कि उसके पास सर्वेक्षण जहाजों के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता है और वह लगभग चार दशकों से भारतीय नौसेना के लिए इनका निर्माण कर रही है। जीआरएसई अधिकारी ने एक बयान में कहा कि इस अनुबंध पर मंगलवार को गोवा में शिपयार्ड और एनसीपीओआर के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए।

लोस चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के लिए राकांपा से गठबंधन जिम्मेदार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक साप्ताहिक अखबार ने पार्टी के फैसले को कसूरवार ठहराया

भाषा। मुंबई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े एक साप्ताहिक अखबार ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खराब प्रदर्शन के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से गठबंधन के उसके फैसले को कसूरवार ठहराया है। अखबार में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि भाजपा के अजित पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुट से हाथ मिलाने के बाद जनभावनाएं पूरी तरह से पार्टी के खिलाफ हो गईं। लेख के मुताबिक, उसने भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से बात की और इन सभी ने कहा कि वे राकांपा से हाथ मिलाने के पार्टी के फैसले से सहमत नहीं थे।

अखबार ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच व्याप्त असंतोष को कम करके आंका गया। उसने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में बेहतर समन्वय और शासन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं को दिए गए महत्व ने राज्य की लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में भाजपा की मदद की। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा की सीटों की संख्या पिछले चुनाव में 23 के मुकाबले घटकर नौ हो गई। वहीं, महायुति के उसके गठबंधन सहयोगियों-एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना को सात, जबकि अजित पवार नीत राकांपा को महज एक सीट से संतोष करना पड़ा। दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर कब्जा जमाया। एमवीए में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राकांपा (शरद चंद्र पवार) और कांग्रेस शामिल हैं। आरएसएस से जुड़े साप्ताहिक अखबार विवेक ने मुंबई, कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र में 200 से अधिक लोगों पर की गई अनौपचारिक रायशुमारी के आधार पर यह लेख प्रकाशित किया। लेख में कहा गया है, भाजपा या संगठन (संघ परिवार) से जुड़े लगभग हर व्यक्ति ने कहा कि वह राकांपा (अजित पवार के नेतृत्व वाले) के साथ गठबंधन करने के भाजपा के फैसले से सहमत नहीं है। हमने 200 से अधिक उद्योगपतियों, व्यापारियों, चिकित्सकों, प्रोफेसर और शिक्षकों की राय जानी। इन सभी ने माना कि भाजपा-राकांपा गठबंधन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में व्याप्त असंतोष को कम करके आंका गया। लेख के अनुसार, एक-दूसरे से छोटी-मोटी शिकायतों के बावजूद हिंदुत्व के साझा सूत्र के चलते शिवसेना के साथ भाजपा के गठबंधन को हमेशा स्वाभाविक माना जाता है। लेख में कहा गया है कि लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एमवीए के तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत स्वीकार कर ली थी। यह बगावत उद्धव सरकार के गिरने का कारण बनी थी। इसमें कहा गया है कि भाजपा ने बाद में शिंदे के समर्थन की घोषणा की और वह सरकार बनाने में सफल रहे। लगभग एक साल बाद, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजित पवार पार्टी के कई विधायकों के साथ शिंदे सरकार में बतौर उपमुख्यमंत्री शामिल हो गए। लेख में कहा गया है, हालांकि, राकांपा से हाथ मिलाने के बाद जनभावनाएं पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ हो गईं। राकांपा की वजह से गणित गड़बड़ाने के बाद पार्टी की भावी रणनीति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लेख के मुताबिक, भाजपा की एक ऐसे दल के रूप में छवि बन गई, जो नेताओं को मांझने की पुरानी संगठनात्मक प्रक्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए दूसरी पार्टी के नेताओं को खुद में शामिल करती है।

लेख में कहा गया है कि इस प्रक्रिया से पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अटल बिहारी वाजपेई और राज्य स्तर पर गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जैसे दिग्गज नेता मिले। इसमें कहा गया है कि ए सभी नेता विनम्र पार्टी कार्यकर्ता थे, जो आगे चलकर बड़े नेता बने और वे इस बात को हमेशा से जानते थे। लेख में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदुत्व का प्रचार करने वाले यूट्यूबर भाऊ तोरसेकर को भाजपा की राज्य पदाधिकारी श्वेता शालिनी की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किया गया। तोरसेकर ने अपने एक हालिया पोस्ट में शालिनी के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की थी, जिसके बाद शालिनी ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा था। हालांकि, बाद में उन्होंने इसे वापस ले लिया। लेख में कहा गया है, विपक्ष ने यह धारणा कायम करने में सफलता पाई कि पार्टी के मूल कार्यकर्ता हमेशा निचले पायदान पर रहेंगे, जबकि दलबदलुओं को बड़े पद मिलेंगे। सोशल मीडिया पर हिंदुत्व का प्रचार करने वालों के खिलाफ कुछ लोगों की कार्वाई ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष बढ़ा दिया। कार्यकर्ता यह भी सोचने लगे कि पार्टी में उनकी राय की कोई कीमत है या नहीं। अखबार ने राम मंदिर की सीमित स्वीकार्यता और आपातकाल के दौरान आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बलिदान को भी रेखांकित किया। उसने कहा, आपातकाल के दौरान और राम मंदिर आंदोलन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बलिदान के बारे में कोई संदेह नहीं है। पर जब मतदान की बात आती है, तो 45 वर्ष से कम उम्र के शिक्षित लोगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है? भले ही वह व्यक्ति हिंदुत्व समर्थक हो, उसे तीन-चार दशक पहले हुई घटनाओं से कोई जुड़ाव महसूस नहीं होगा।

ब्रिटेन की नई सरकार ने जीवन-यापन की लागत के संकट को कम करने का वादा किया

लंदन। ब्रिटेन की नई लेबर पार्टी सरकार ने बुधवार को कहा कि वह धन सृजन पर ध्यान केंद्रित करके देश को जीवनयापन की लागत के संकट से उबरने में मदद करेगी। इसके साथ ही सरकार ने ै राष्ट्रीय नवीनीकरण ै के लिए अपनी योजनाओं को पेश किया। महाराजा चार्ल्स तृतीय ने बुधवार को संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर की नई सरकार के विधाई एजेंडे का विवरण पेश किया। अभिभाषण में ब्रिटेन के सार्वजनिक वित्त को स्थिर करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की सरकार की योजना का जिक्र किया गया। महाराजा ने सैकड़ों सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, ै मेरी सरकार व्यवसाय और कामकाजी लोगों -दोनों के साथ एक नई साझेदारी की तलाश करेगी और सभी समुदायों के लिए धन सृजन को प्राथमिकता देकर देश को

जीवन-यापन की लागत की चुनौतियों से आगे बढ़ने में मदद करेगी। चुनाव प्रचार के दौरान स्टॉर्मर ने ब्रिटेन में साहसिक बदलाव लाने का वादा किया था।

लेबर सरकार द्वारा लिखे भाषण में कहा गया है कि पार्टी और आवास तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण करेगी, श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करेगी और नई औद्योगिक रणनीति बनाएगी। महाराजा चार्ल्स तृतीय ने यह भाषण पढ़ा। अभिभाषण की लिखित प्रस्तावना में, प्रधानमंत्री ने धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि बदलाव के लिए आसान उत्तरों और लोकलुभावनवाद वादों के बजाय दृढ़ निश्चई, धैर्यपूर्ण काम और गंभीर समाधानै की आवश्यकता होगी। लेबर पार्टी ने चार जुलाई को आम चुनाव में भारी जीत हासिल की। स्टॉर्मर ने देश के पुराने बुनियादी ढांचे और खराब सार्वजनिक सेवाओं को दुरुस्त करने का वादा किया है। उनका कहना है कि वे व्यक्तिगत कर की दर नहीं बढ़ाएंगे। अभिभाषण में 40 विधेयकों को शामिल किया गया जबकि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के समय पिछले अभिभाषण में केवल 21 विधेयक थे। इन 40 विधेयकों में घर बनाने से लेकर रेलवे का राष्ट्रीयकरण और बिजली आपूर्ति क्षेत्र में बदलाव लाना शामिल हैं। सरकार ने कहा कि वह ब्रिटेन के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय धन कोष की स्थापना करेगी और नए घरों और बुनियादी ढांचे के निर्माण को बाधित करने वाले नियोजन नियमों को फिर से तैयार करेगी।

ओमान की मस्जिद में हुई गोलीबारी में मारे गए छह लोगों में एक भारतीय भी शामिल

दुबई, मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट में एक शिया मस्जिद के समीप इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह की गोलीबारी में मारे गए छह लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। इमाम अली मस्जिद के समीप सोमवार रात को हुई गोलीबारी में एक पुलिस कर्मी और चार पाकिस्तानी नागरिकों की भी जान चली गई जबकि 28 अन्य लोग घायल हो गए। मस्कट में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मस्कट शहर में 15 जुलाई को गोलीबारी की घटना के बाद ओमान सल्तनत के विदेश मंत्रालय ने सूचित किया कि एक भारतीय नागरिक ने जान गंवाई है तथा एक अन्य घायल है। दूतावास पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है तथा उन्हें हरसंभव मदद देने के लिए तैयार है। सोमवार की रात को अल-वादी अल-कबीर इलाके में हुई इस घटना के दौरान सुरक्षाबलों ने तीन हमलावरों को भी मार गिराया।

विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉरीशस के शीर्ष राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की

पोर्ट लुई। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को मॉरीशस के विपक्षी नेता अरविन बूलेल सहित वहां के शीर्ष राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उनसे द्वीपीय राष्ट्र के साथ भारत की विशेष और स्थाई साझेदारी को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। जयशंकर मंगलवार को दो दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे। विदेश मंत्री के रूप में अपने वर्तमान कार्यकाल में यह उनका पहला दौरा था। विदेश मंत्री ने मंगलवार को कहा था, यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और गहराई को रेखांकित करता है। यह मॉरीशस के साथ भारत की विशेष और स्थाई साझेदारी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करने का भी अवसर है।

जयशंकर ने बूलेल के साथ मॉरीशस-भारत संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र की समृद्धि और कल्याण के लिए इसके महत्व पर

चर्चा की। जयशंकर ने एक्स पर लिखा, हमारे संबंधों को लगातार मजबूत करने के लिए उनके समर्थन का स्वागत है। बूलेल का जन्म पोर्ट लुई में एक आर्य समाजी भारतीय मूल के मॉरीशस के परिवार में हुआ था, वे लेबर पार्टी के पूर्व नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री सैटकैम बूलेल के पुत्र हैं। उन्होंने पार्टी मौरिसियन सोशल डेमोक्रेट के नेता जेवियर ल्यूक डुवाल से भी मुलाकात की।

जयशंकर ने एक्स पर कहा, भारत-मॉरीशस साझेदारी को मजबूत करने पर विचारों का अच्छा आदान-प्रदान हुआ। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों पॉल बेरेन्जर और नवीन रामगुलाम से भी मुलाकात की। जयशंकर ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री पॉल बेरेन्जर से मिलकर अच्छा लगा। समकालीन वैश्विक मुद्दों पर जीवंत बातचीत हुई। भारत-मॉरीशस संबंधों के लिए उनके समर्थन की सराहना करता हूं।

बेरेन्जर 2003 से 2005 तक मॉरीशस के प्रधानमंत्री रहे। जयशंकर ने एक्स पर लिखा, आज सुबह पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. रामगुलाम से मिलकर खुशी हुई। हमारी दीर्घकालिक द्विपक्षीय साझेदारी और इसके आगे विकास की व्यापक इच्छा पर चर्चा की। भारत-मॉरीशस संबंधों के लिए उनके समर्थन की सराहना करता हूं। रामगुलाम के पूर्वज बिहार से मॉरीशस चले आए थे। वह दिसंबर 1995 से सितंबर 2000 तक पहली बार प्रधानमंत्री रहे। पांच जुलाई 2005 को वे दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने और 2014 तक इस पद पर रहे।

उत्तर कोरिया की बारूदी सुरंगों के दक्षिण कोरिया में बाढ़ में बहकर आने की आशंका

सियोल। उत्तर कोरिया ने हाल में दक्षिण कोरिया की कड़ी सुरक्षा वाली सीमा पर हजारों अतिरिक्त घातक विस्फोटक तैनात कर दिए हैं, जिस पर दक्षिण कोरिया की सेना ने बुधवार को चेतावनी दी कि बाढ़ के कारण पड़ोसी देशी की बारूदी सुरंगे उसके यहां बहकर आ सकती हैं। उत्तर कोरिया द्वारा सीमा पर अप्रैल से निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनमें बारूदी सुरंगें बिछाना, टैंक रोधी अवरोधों को लगाना और सड़कों को सुदृढ़ करना शामिल है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का मानना है कि उत्तर कोरिया का लक्ष्य अपनी अग्रिम पंक्ति की सुरक्षा स्थिति को मजबूत करना तथा अपने सैनिकों एवं नागरिकों को दक्षिण कोरिया में जाने से रोकना है। दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने स्थानीय पत्रकारों को बताया कि गर्मियों में बारिश के कारण आने वाली बाढ़ सीमा पार की बारूदी सुरंगों को बहा कर ला सकती है।

प्रीति पटेल विपक्ष के नेता के रूप में सुनक की जगह लेने के लिए कर सकती हैं दावा

लंदन। ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष के नेता के रूप में ऋषि सुनक का स्थान लेने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में अपना दावा पेश कर सकती हैं। ब्रिटिश मीडिया की खबरों के अनुसार, भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद पटेल (52) इस महीने की शुरुआत में हुए आम चुनाव में अपनी पार्टी की करारी हार के बावजूद एसेक्स की वाइथम सीट पर शानदार जीत दर्ज करने में सफल हो गईं। सुनक ने पांच जुलाई को लेबर पार्टी की जीत के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की थी और वह बुधवार को संसद के राजकीय उद्घाटन समारोह में अंतरिम विपक्षी नेता के रूप में शामिल होंगे।

डेली टेलीग्राफ ने वरिष्ठ सांसद के एक करीबी सूत्र के हवाले से अपनी खबर में कहा, प्रीति ने दूसरों को सहयोग देने की पूरी कोशिश की है, उनका मानना है कि उनके सहकर्मियों को भी आम चुनाव के नतीजों को पचाने के लिए समय चाहिए और वह नहीं चाहतीं कि संभावित उम्मीदवार मीडिया में अपनी बात रखें।

सूत्र ने कहा कि उन्होंने (पटेल ने) एक टीम भी बना ली है, क्योंकि पिछले सप्ताह पार्टी के कई सहयोगियों ने उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। पटेल ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, वाइथम निर्वाचन क्षेत्र के महान लोगों द्वारा उन्हें एक बार फिर संसद के लिए चुना जाना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, मैं एसेक्स के हमारे खूबसूरत क्षेत्र के लोगों के लिए एक मजबूत और मुखर समर्थक बनी रहूंगी और अपने मूल्यों के लिए खड़ी रहूंगी।

यदि वह विपक्ष के नेता पद की दौड़ में शामिल होती हैं, तो उन्हें भारतीय मूल की उनकी सहकर्मी सुएला ब्रेवरमैन और रॉबर्ट जेनरिक समेत कई अन्य पूर्व कैबिनेट मंत्रियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

ट्रंप के बारे में सच बोलना नहीं बंद करूंगा: बाइडन

लास वेगास। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी में कड़वाहट कम करने का आह्वान किया। हालांकि, उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि ऐसा करने का यह मतलब नहीं है कि हम सच बोलना बंद कर दें। लास वेगास में एनएएसीपी सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाइडन ने कहा कि देश में राजनीतिक हिंसा से निपटने का मतलब हर तरह के खूनखराबे पर लगाम लगाना, पुलिस की क्रूरता का बेहतर मुकाबला करना और ट्रंप पर बीते सप्ताहांत हुए हमले में इस्तेमाल एआर-स्टाइल राइफल जैसे हथियारों पर प्रतिबंध लगाना होना चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, देश में एक महत्वपूर्ण चर्चा का समय आ गया है। हमारा राजनीतिक परिदृश्य बहुत गरमा गया है। और चार साल के नारों के बीच उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि हमें अपनी राजनीतिक बयानबाजी में कड़वाहट कम करनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा से संबंधित है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सच बोलना बंद कर देना चाहिए।

सम्मेलन में राष्ट्रपति अश्वेत मतदाताओं के लिए अपने प्रशासन के समर्थन को प्रदर्शित करते नजर आए, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का बड़ा वोट बैंक होने के साथ ही उनके दृढ़ समर्थक भी माने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर ट्रंप के कार्यकाल को अश्वेत अमेरिकियों के लिए नर्क करार दिया। बाइडन ने कोरोना वायरस महामारी के कुप्रबंधन, लॉकडाउन के दौरान बढ़ी बेरोजगारी और अश्वेत इतिहास को मिटाने के कथित प्रयासों को लेकर भी पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन पर निशाना साधा।

बाइडन ने ट्रंप के ब्लैक जॉब्स का संदर्भ देने का उपहास किया और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जिक्र करते हुए कहा, मुझे यह वाक्यांश पसंद है। मुझे पता है कि ब्लैक जॉब से उनका मतलब क्या है। उनका मतलब अमेरिका की उपराष्ट्रपति से है। वह राष्ट्रपति बनने के भी योग्य हैं। बाइडन ने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी जिक्र किया। उन्होंने केतनजी ब्राउन जैक्सन का भी नाम लिया, जो अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत एवं महिला न्यायाधीश हैं।

बाइडन पिछले महीने ट्रंप के साथ बहस में खराब प्रदर्शन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद की उनकी उम्मीदवारी पर उठते सवालों के बीच एनएएसीपी सम्मेलन में पहुंचे। राष्ट्रपति के खराब प्रदर्शन ने उम्र, सेहत और ट्रंप को हराने की उनकी क्षमता को लेकर पार्टी नेताओं और मतदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, बाइडन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की मांग खारिज कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं और ट्रंप को एक बार फिर हरा सकते हैं। वहीं, रिपब्लिकन नेता मिलवाउकी में जारी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ट्रंप के साथ पहले से कहीं अधिक एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं।

रिपब्लिकन पार्टी की भारतीय-अमेरिकी नेता निक्की हेली ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया

मिलवाउकी। रिपब्लिकन पार्टी की भारतीय मूल की नेता निक्की हेली ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है जिससे प्राइमरी चुनाव के दौरान उनकी कटु प्रतिद्वंद्विता के बाद अब एकता का संदेश मिलता है। हेली (52) ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए ट्रंप (78) को चुनौती दी थी तथा महीनों तक उनके खिलाफ प्रचार किया था लेकिन बाद में इस दौड़ से हटने की घोषणा की थी। उन्होंने पिछले सप्ताह अपने 97 डेलीगेट को पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में ट्रंप के लिए वोट करने का निर्देश दिया था और पार्टी में एकता का आह्वान किया था।

हेली ने यहां मिलवाउकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में दिए अपने संबोधन में कहा, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप को मेरा पुरजोर समर्थन प्राप्त है। इस सम्मेलन में पर्याप्त संख्या में डेलीगेट (मतदाताओं के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति) के वोट हासिल करने के बाद ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए हैं। वह बृहस्पतिवार को नामांकन स्वीकार करने हुए अपना संबोधन देंगे। हेली ने हजारों डेलीगेट और पार्टी नेताओं से कहा कि ट्रंप देश के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं और रिपब्लिकन नेता निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन को हराने के लिए एकजुट हैं। उन्होंने अपने भाषण में पूर्व राष्ट्रपति की विदेश नीति का बचाव किया और उनसे कुछ मुद्दों पर असहमति रखने वाले मतदाताओं से सीधे बात की। उन्होंने कहा, कुछ अमेरिकी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से 100 फीसदी सहमत नहीं है। उन्हें मेरा संदेश स्पष्ट है : ट्रंप के लिए वोट करते समय आपको उनसे 100 फीसदी सहमत होने की जरूरत नहीं है।

हेली ने कहा, हमारा देश एक अहम मोड़ पर है। हमें किसी को चुनना होगा। एक साल से अधिक वक्त से मैंने कहा है कि जो बाइडन के लिए वोट करने का मतलब कमला हैरिस के लिए वोट करना है। हमारे देश की खातिर हमें डोनाल्ड ट्रंप को चुनना होगा। हेली के भाषण के वक्त ट्रंप सम्मेलन केंद्र में मौजूद थे। जब हेली ने भाषण शुरू किया तो ट्रंप और सीनेटर जे डी वेंस ने उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाईं।

भारतीय-अमेरिकी नेता ने कहा, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया पर आक्रमण किया। जब जो बाइडन राष्ट्रपति हैं तो पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर ही हमला कर दिया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो पुतिन ने कुछ नहीं किया। कोई आक्रमण नहीं, कोई युद्ध नहीं। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया क्योंकि वह जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप सख्त हैं। एक मजबूत राष्ट्रपति युद्ध शुरू नहीं करता है। एक मजबूत राष्ट्रपति युद्ध रोकता है। भारतीय-अमेरिकी उद्यमी से नेता बने विवेक रामास्वामी ने भी सम्मेलन से पहले देशवासियों से ट्रंप के लिए वोट करने को कहा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो असल में देश को एकजुट करेंगे और वह भी महज बातों से नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने के बाद।

आंतरिक सुरक्षा विभाग ट्रंप की रैली में सुरक्षा संभालने के तरीके की जांच कर रहा

वाशिंगटन। अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा विभाग के महानिरीक्षक ने कहा है कि विभाग पेन्सिल्वेनिया में आयोजित रैली में हुए हमले के दौरान यूएस सीक्रेट सर्विस द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी संभालने के तरीकों की जांच कर रहा है। बुधवार को अपनी वेबसाइट पर एक संक्षिप्त नोटिस में कहा कि जांच का उद्देश्य पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की 13 जुलाई की रैली के दौरान उन्हें सुरक्षा मुहैया करने संबंधी सीक्रेट सर्विस की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना है। जांच कब शुरू की गई, इसकी कोई तारीख नहीं बताई गई। रैली में हुई गोलीबारी की घटना के बाद ए सवाल उठ रहे हैं कि बंदूकधारी उस छत पर पहुंचने में कैसे कामयाब हुआ जहां से पूर्व राष्ट्रपति उसके सीधे निशाने पर आए। राष्ट्रपति जो बाइडन ने रैली में सुरक्षा इंतजाम की स्वतंत्र समीक्षा का पहले ही निर्देश दिया है। सीक्रेट सर्विस की निदेशक किम चीटल ने कहा कि एजेंसी बाइडन द्वारा दिए गए समीक्षा के आदेश को समझती है और यह इसमें तथा गोलीबारी की घटना पर गौर कर रही संसदीय समितियों का पूरी तरह से सहयोग करेगी।

रूस, यूक्रेन ने की 95-95 युद्धबंदियों की अदला-बदली

कीव। यूक्रेन और रूस ने 95-95 युद्धबंदियों की अदला-बदली की है। दोनों देशों के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इससे पूर्व, तीन सप्ताह पहले भी युद्धबंदियों की इस तरह की अदला-बदली की गई थी। यह बंदी बनाए गए सैनिकों को वापस भेजने के लिए कभी-कभार होने वाले समझौतों का हिस्सा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस अदला-बदली की सूचना दी। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से 54 बार युद्धबंदियों की अदला-बदली हो चुकी है। ना तो रूस और ना ही यूक्रेन ने युद्धबंदियों की संख्या का खुलासा किया। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने फिर से समझौतों की मध्यस्थता की है। यूएई ने कहा कि उसका रूस और यूक्रेन दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम है।

जेलेंस्की ने पोस्ट में लिखा, चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हम उन सभी की तलाश कर रहे हैं जो कैद में हैं। हमें सभी को वापस लाना होगा। रिहा किए गए यूक्रेन के नागरिकों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दो साल से ज्यादा समय तक कैद में बिताया। यूक्रेन के युद्धबंदियों के समन्वय मुख्यालय ने बताया कि उन्हें कीव क्षेत्र में रूस के शुरुआती आक्रमण और पूर्वी लुहांस्क क्षेत्र में लड़ाई के दौरान मारियुपोल में पकड़ा गया था। मुख्यालय ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 3,400 से ज्यादा लोग रूस की कैद से वापस लौटे हैं। इनमें सैन्य और असैन्य दोनों तरह के लोग शामिल हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रिहा किए गए रूसी सैनिकों को चिकित्सा उपचार और पुनर्वास के लिए मॉस्को ले जाया जाएगा। जनवरी में रूस और यूक्रेन ने सैकड़ों युद्धबंदियों की अदला-बदली की थी, जो कि एक बार में रिहा किए गए बंदियों की सर्वाधिक संख्या है।

रामास्वामी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए ट्रंप को वोट देने का आग्रह किया

भाषा। मिलवाउकी (अमेरिका)

भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी एवं रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी ने अमेरिकियों से राष्ट्रीय गौरव को फिर से हासिल करने और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का आग्रह किया है। रामास्वामी (38) रिपब्लिकन प्राइमरी के शुरुआती चरण में ही राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ से बाहर हो गए थे। रिपब्लिकन राष्ट्रीय सम्मेलन (आरएनसी) को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति साबित होंगे जो खोखले शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से अमेरिका को एकजुट करेंगे।

रामास्वामी ने कहा, यदि आप सीमा सील करना चाहते हैं, तो ट्रंप को वोट दें। अगर आप कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करना चाहते हैं, तो ट्रंप को वोट दें। यदि आप हमारी अर्थव्यवस्था को फिर से गति देना चाहते हैं, तो ट्रंप को वोट दें। यदि आप राष्ट्रीय गौरव को फिर से हासिल करना चाहते हैं, तो ट्रंप को वोट दें। यदि आप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं, तो ट्रंप को वोट दें। उनके भाषण की कई लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए सराहना की।

रामास्वामी ने कहा, हम वह देश हैं जहां हम एक-दूसरे से काफी हद तक असहमत हो सकते हैं और फिर भी अंत में हम एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। यही वह अमेरिका है जिसे मैं जानता हूं। यही वह अमेरिका है जिसकी हमें कमी खलती है। उन्होंने कहा, यदि आप मेरी हर बात से असहमत हैं तो आपके लिए हमारा संदेश यह है - हम फिर भी आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करेंगे क्योंकि हम अमेरिकी ऐसे ही हैं।

टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर रामास्वामी के भाषण की प्रशंसा की। अपने लगभग सात मिनट के जबरदस्त भाषण में रामास्वामी ने कहा कि वह एक ऐसा संदेश देना चाहते है जिसे मीडिया नहीं चाहता कि वे रिपब्लिकन पार्टी से सुनें। उन्होंने कहा, अश्वेत अमेरिकियों के लिए: मीडिया ने दशकों से आपको यह समझाने की कोशिश की है कि रिपब्लिकन आपके समुदायों की परवाह नहीं करते हैं। हम आपके लिए वही चाहते हैं जो हम हर अमेरिकी के लिए चाहते हैं। हम सभी के लिए सुरक्षित पड़ोस, साफ सड़कें, अच्छी नौकरियां, आपके बच्चों के लिए बेहतर जीवन और एक समान न्याय प्रणाली चाहते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन हम सिर्फ दूसरे पक्ष की आलोचना करके यह चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं।

ढाका विवि अनिश्चितकाल के लिए बंद

● विद्यार्थियों से छात्रावास खाली करने को कहा गया

ढाका। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान में सुधार की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों में कम से कम छह लोगों के मारे जाने के बाद ढाका विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने संस्थान को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की बुधवार को घोषणा की। अधिकारियों ने छात्रों को शाम छह बजे तक छात्रावास खाली करने के निर्देश दिए हैं। समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून ने प्रति-कुलपति (अकादमिक) प्रोफेसर सीतेश सी बाचर के हवाले से बताया कि यह निर्णय कुलपति एएसएम मकसूद कमाल के कार्यालय में एक आपात बैठक में लिया गया।

बाचर ने द डेली स्टार से कहा , छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद करने और हॉल खाली कराने का फैसला किया है। समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और वे कुलपति के आवास पर एकत्र हो गए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हुई झड़प में मंगलवार को तीन विद्यार्थियों सहित कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। इसके बाद स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।

उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने वाले 2018 के सरकारी परिपत्र को पांच जून को अवैध घोषित कर दिया था, इसके बाद 10 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश जारी किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से अगली सूचना तक कक्षाएं स्थगित करने और छात्रावास खाली कराने को कहा था। इस पर बुधवार को ढाका विश्वविद्यालय की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था, सिंडिकेट की एक बैठक तत्काल बुलाई गई।

यूजीसी का यह निर्देश प्रदर्शनों के दौरान हुई कई झड़पों के बाद आया है। ए झड़पें सोमवार को शुरू हुईं, जब सत्तारूढ़ अवामी लीग के छात्र मोर्चे के कार्यकर्ता प्रदर्शनकारियों के सामने आ गए। प्रदर्शनकारी इस बात पर जोर दे रहे थे कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था सरकारी सेवाओं में मेधावी छात्रों के नामांकन को काफी हद तक रोक रही है। प्रदर्शनकारियों ने चार महत्वपूर्ण शहरों-मध्य ढाका, उत्तर पश्चिम राजशाही, दक्षिण पश्चिम खुलना और चट्टोग्राम में राजमार्ग और रेल मार्ग अवरूद्ध कर दिए। मौजूदा आरक्षण प्रणाली के तहत 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नायकों की संतानों और पौत्र-पौत्रियों के लिए 30 फीसदी नौकरियां, प्रशासनिक जिलों के लिए 10 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत, जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए पांच प्रतिशत और दिव्यांगों के लिए एक प्रतिशत नौकरियां आरक्षित हैं।

ईरान ने ट्रंप की हत्या की साजिश में संलिप्तता के आरोपों से इनकार किया

तेहरान। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश संबंधी आरोपों को खारिज किया लेकिन साथ ही एक प्रतिष्ठित जनरल की 2020 में की गई हत्या के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ कानूनी कार्वाई करने का संकल्प जताया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नसीर कनानी के हवाले से कहा कि ईरान ट्रंप पर हाल में हुए सशस्त्र हमले में किसी भी प्रकार की संलिप्तता या ऐसी किसी कार्वाई की ईरान की मंशा के बारे में दावों को सिरे से खारिज करता है। कनानी ने हालांकि कहा, इस्लामिक गणराज्य शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के अपराध में ट्रंप की सीधी भूमिका के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्वाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सुलेमानी, ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर कुद्स फोर्स के कमांडर थे और जनवरी 2020 में बगदाद में अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए थे। अमेरिका के दो अधिकारियों ने मंगलवार को कहा था कि शनिवार को पेनसिल्वेनिया में हुई रैली से कुछ दिनों पहले ईरान से ट्रंप की जान को खतरे के कारण उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई गई थी लेकिन इसका रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की हत्या की कोशिश से कोई संबंध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सैयद इरावनी ने मंगलवार को तेहरान के खिलाफ आरोपों को निराधार तथा राजनीति से प्रेरित बताया था।

थाइलैंड के होटल में मृत पाए गए छह लोगों के रक्त में साइनाइड के अंश मिले

बैंकॉक। बैंकॉक के एक होटल में संदिग्ध हालात में मृत मिले छह लोगों के शवों का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों ने उनके रक्त में साइनाइड के अंश मिलने की बुधवार को पुष्टि की। साइनाइड बेहद जहरीला रसायन है जिसके सेवन के बाद बच पाना लगभग नामुमकिन है। चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय के मेडिकल स्कूल में फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. कोर्नकियाट वोंगपाइसरनसिन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सिटी स्कैन में शवों पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं जिससे यह अनुमान पुष्ट होता है कि उन्हें जहर दिया गया। बैंकॉक के व्यस्त इलाके में स्थित ग्रैंड हयात इरावन होटल में मंगलवार को छह शव पाए गए थे। पुलिस ने बताया कि होटल के रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि कमरे में छह लोगों के अलावा कोई अन्य बाहरी व्यक्ति नहीं था।

सोमवार दोपहर को जब उनके कमरे में भोजन पहुंचाया गया था तब आखिरी बार उन्हें जीवित देखा गया था। होटल के कर्मचारी ने देखा था कि महिला ने खाना लिया और बाकी सभी लोग कुछ ही देर बाद एक-एक करके कमरे में आए। थाईलैंड पुलिस के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल त्राइरोंग पिवपन ने बताया कि कमरे से कब्जे में लिए गए खाली कप से पुलिस को साइनाइड के अंश मिले हैं। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट बुधवार दोपहर को आने की उम्मीद है।

बैंकॉक के पुलिस प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल थिति सांगसवांग ने बताया कि मृतकों की पहचान दो वियतनामी-अमेरिकी के तौर पर और चार की वियतनाम के नागरिक के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि मृतकों में तीन पुरुष और तीन महिलाएं हैं। बैंकॉक के उप पुलिस प्रमुख नोप्पसिन पुन्सावत ने बताया कि मृतकों की उम्र 37 से 56 वर्ष थी। उन्होंने कहा, यह मामला व्यक्तिगत प्रतीत होता है और इससे पर्यटकों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीड़ितों के रिश्तेदारों से हासिल जानकारी का हवाला देते हुए पुन्सावत ने बताया, एक दंपति ने अन्य दो दंपति के साथ मिलकर धन निवेश किया था, जिससे अनुमान है कि यह मामला धन निवेश से जुड़ा हो सकता है।

यह निवेश जापान में एक अस्पताल बनाने के लिए किया गया था और संभवत: वे लोग इसी मामले को लेकर मिले थे। बैंकॉक के पुलिस प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल थिति सांगसवांग ने मंगलवार को बताया कि चार शव बैठक कक्ष और दो शव शयनकक्ष में बरामद किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से दो ने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही वे गिर पड़े। नोप्पसिन ने बुधवार को बताया कि जब वे लोग थाईलैंड आए थे तो उनके साथ एक सातवां व्यक्ति भी था जो कि उन छह लोगों में से एक का रिश्तेदार है और उसी के नाम पर होटल में बुकिंग की गई थी लेकिन वह 10 जुलाई को ही थाईलैंड से चला गया। पुलिस का मानना है कि सातवें व्यक्ति का इन मौतों से कोई संबंध नहीं है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन ने कहा कि इस घटना को लेकर वियतनाम और अमेरिका के दूतावासों से संपर्क किया गया है तथा जांच के लिए अमेरिका का फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) भी यहां पहुंच रहा है।

ओलंपिक के लिए 117 खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों की सूची जारी, आभा खटुआ हुई बाहर

भाषा। नई दिल्ली

आभा खटुआ

पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल हैं। सहयोगी स्टाफ के 72 सदस्यों को सरकार के खर्चे पर मंजूरी मिली है। ओलंपिक के लिए जिन खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया था उनमें से केवल गोला फेंक की एथलीट आभा खटुआ का नाम सूची में नहीं है। विश्व रैंकिंग के जरिए कोटा हासिल करने वाली आभा खटुआ का नाम हटाने को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कुछ दिन पहले विश्व एथलेटिक्स की ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सूची से उनका नाम हटा दिया गया था। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि चोट लगने, डोपिंग उल्लंघन या किसी अन्य तकनीकी समस्या के कारण उनका नाम हटाया गया है।

ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले अन्य खिलाड़ियों को उम्मीद के अनुरूप मंजूरी मिल गई। लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पूर्व निशानेबाज गगन नारंग को दल प्रमुख बनाया गया है। नारंग भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) में उपाध्यक्ष भी हैं।खेल मंत्रालय की ओर से आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा को लिखे गए पत्र में कहा गया है, ओलंपिक खेल 2024 की आयोजन समिति के मानदंडों के अनुसार सहयोगी स्टाफ के 67 सदस्य ही खेल गांव में रुक सकते हैं जिनमें आईओए के 11 अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारियों में पांच सदस्य चिकित्सा दल के हैं। पत्र में कहा गया है, खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की लागत पर 72 अतिरिक्त कोच और अन्य सहायक कर्मचारियों को मंजूरी दी गई है और उनके ठहरने की व्यवस्था होटल-खेल गांव के बाहर के स्थानों में की गई है। आभा खटुआ का नाम शामिल नहीं होने के बावजूद खिलाड़ियों की सूची में सर्वाधिक 29 (11 महिला और 18 पुरुष) खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं। उनके बाद निशानेबाजी (21) और हॉकी (19) का नंबर आता है।टेबल टेनिस में भारत के आठ जबकि बैडमिंटन में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता के पीवी सिंधु सहित सात खिलाड़ी भाग लेंगे। कुश्ती (6), तीरंदाजी (6) और मुक्केबाजी (6) में छह-छह खिलाड़ी ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करेंगे। इसके बाद गोल्फ (4), टेनिस (3), तैराकी (2), सेलिंग (2) का नंबर आता है। घुड़सवारी, जूडो, रोइंग और भारोत्तोलन में एक-एक खिलाड़ी भाग लेंगे। निशानेबाजी दल में 11 महिला और 10 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। टेबल टेनिस में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में चार-चार खिलाड़ी शामिल हैं। तोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू दल में शामिल एकमात्र भारोत्तोलक हैं। वह महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। तोक्यो ओलंपिक में भारत के 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया था जिन्होंने सात पदक जीते थे। इनमें नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में जीता गया ऐतिहासिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। चोपड़ा पेरिस में अपने खिताब का बचाव करने के लिए उतरेंगे। दल में शामिल में 21 अधिकारियों में 11 खेल गांव में रुकेंगे जबकि बाकी अधिकारी खेल गांव के बाहर होटल में ठहरेंगे। इनका खर्च सरकार वहन करेगी। निशानेबाजी में सहयोगी स्टाफ के सर्वाधिक 18 सदस्य शामिल हैं जिनमें से एक हाई परफॉर्मेंस निदेशक और छह कोच खेल गांव में ठहरेंगे। बाकी 11 सदस्य होटल में रुकेंगे जिनमें चार कोच, चार फिजियो, दो मनोवैज्ञानिक और एक अनुकूलन विशेषज्ञ शामिल हैं। एथलेटिक्स में सहयोगी स्टाफ के 17 सदस्य शामिल हैं। उसके बाद कुश्ती (12), मुक्केबाजी (11), हॉकी (10), टेबल टेनिस (9), बैडमिंटन (9), गोल्फ (7), घुड़सवारी (5), तीरंदाजी (4), नौकायन (4), भारोत्तोलन (4) टेनिस (3), तैराकी (2) और जूडो (1) का नंबर आता है। मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि पेरिस में भारतीय दूतावास में एयर अताशे पद पर कार्यरत एयर कमोडोर प्रशांत आर्य ओलंपिक अताशे होंगे, जिनके पास मान्यता पत्र होगा तथा वह दूतावास की सहायता और हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले किसी भी मुद्दे का समाधान करने के लिए खेल गांव और प्रतियोगिता स्थलों का दौरा करेंगे।

भारतीय दल को सर्वश्रेष्ठ सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हो रही है आलोचना : उषा

नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने बुधवार को कहा कि पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों को उनकी पसंद का सहयोगी स्टाफ मुहैया कराने के लिए खेल मंत्रालय, आईओए और राष्ट्रीय महासंघों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने इस शानदार तालमेल पर गौर नहीं करने के लिए आलोचकों को लताड़ भी लगाई। खेल मंत्रालय ने 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए 117 खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को मंजूरी दी है। इनमें निजी कोच, मानसिक ट्रेनर और फिजियोथैरेपिस्ट भी शामिल है। आईओए विशेष रूप से प्रसिद्ध खेल चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. दिनशॉ पारदीवाला के नेतृत्व में गठित 13 सदस्यीय खेल विज्ञान टीम भी दल के साथ भेज रहा है।उषा ने बुधवार को जारी बयान में कहा, आईओए ने हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके है, जहां खिलाड़ी हमारी योजना और तैयारियों के केंद्र में है। खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के सदस्यों के बीच सामान्य 3:1 अनुपात के बजाय हमने इसे1:1 अनुपात से थोड़ा बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की हर मांग पूरी करने के प्रयासों के बावजूद कुछ रिपोर्टों में काम की नकारात्मक तस्वीर पेश करना निराशाजनक है।उषा ने कहा, खेल मंत्रालय और इसकी इकाइयों, राष्ट्रीय खेल महासंघों और कॉर्पोरेट भागीदारों के साथ मिलकर आईओए ने शानदार टीमवर्क से काम किया है। यह देखकर हैरानी होती है कि कुछ लोगों ने इस तरह के तालमेल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले छह पहलवानों में से एक अंतिम पंघाल कथित तौर पर अपने चार सदस्यीय सहायक स्टाफ के लिए वीजा का इंतजार कर रही है, जिससे उनके अभ्यास में बाधा पड़ रही है।

ओलंपिक में पदक जीतने का सिलसिला जारी रख पाएंगे भारतीय पहलवान!

भाषा। नई दिल्ली

भारत ने बीजिंग ओलंपिक 2008 से लेकर प्रत्एक ओलंपिक में पदक जीता है और पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे पहलवानों के लिए इस सिलसिले को जारी रखना बड़ी चुनौती होगी। लगातार चार ओलंपिक में सफलता के बाद कुश्ती भारत का प्रमुख खेल बन गया। इस बीच उसने सीनियर ही नहीं जूनियर स्तर पर भी अच्छी सफलताएं हासिल की। वह सुशील कुमार थे जिन्होंने 2008 में कांस्य पदक जीत कर भारत में कुश्ती का परिदृश्य बदला। इसके चार साल बाद लंदन ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक हासिल किया जबकि योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक खेल 2016 में कांस्य पदक जीत कर यह सिलसिला जारी रखा जबकि तोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने रजत और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता।

लेकिन जब यह खेल नित नई ऊंचाई हासिल कर रहा था तब देश के शीर्ष पहलवानों के भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण इसकी प्रगति को करारा झटका लगा। इसके कारण राष्ट्रीय शिविर और घरेलू प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो पाया। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और तब कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। राष्ट्रीय महासंघ के चुनाव हुए लेकिन नई संस्था को निलंबित कर दिया गया। इस खेल की अंतरराष्ट्रीय संस्था के निलंबन हटाए जाने के बाद ही स्थिति सामान्य हो पाई। भारत का केवल एक पुरुष खिलाड़ी और पांच महिला खिलाड़ी ही ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर पाए। इन खिलाड़ियों के मजबूत और कमजोर पक्षों का यहां विश्लेषण किया जा रहा है। अमन सहरावत (पुरुष फ्रीस्टाइल 50 किग्रा): अपने खेल में निरंतर सुधार करने वाले अमन ने 57 किग्रा भार वर्ग में रवि दहिया की जगह ली। उनका दमखम और धैर्य बनाए रखना मजबूर पक्ष है। अगर मुकाबला 6 मिनट तक चलता है तो उन्हें हराना आसान नहीं होगा। उनके खेल में हालांकि रणनीति का अभाव नजर आता है। उनके पास प्लान बी नहीं होता है। पेरिस में उन्हें रेई हिगुची और उज्बेकिस्तान के गुलोमजोन अब्दुल्लाव से कड़ी चुनौती मिल सकती है।विनेश फोगाट (महिला 50 किग्रा): इसमें कोई संदेह नहीं है कि विनेश फोगाट भारत की सबसे बेहतरीन महिला पहलवानों में से एक हैं। मजबूत रक्षण और उतना ही प्रभावशाली आक्रमण उनकी ताकत है। लेकिन पिछले एक साल में उन्हें चोटी की खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का कम मौका मिला है। इसके अलावा वह कम वजन वर्ग में भाग ले रही है। उन्हें वजन कम करने की जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंतिम पंघाल (महिला 53 किग्रा): हिसार की यह तेजर्तार खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली पहली पहलवान थी। जब विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर था, तब उन्होंने विनेश को ट्रायल के लिए चुनौती भी दी थी। अंतिम का मजबूत पक्ष उनका लचीलापन है जिससे वह विरोधी की पकड़ से जल्दी बाहर निकल जाती है। उन्होंने हालांकि एशियाई खेलों में भाग नहीं लिया और पीठ की चोट के कारण उन्हें इस साल एशियाई चैम्पियनशिप से बाहर होना पड़ा। पिछले कुछ समय में कम प्रतियोगिताओं में भाग लेने का उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंशु मलिक (महिला 57 किग्रा): जूनियर स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद सीनियर स्तर में जगह बनाने वाली अंशु पदक के दावेदारों में शामिल है।

ओलंपिक की तैयारी में लगे नडाल की हुई आसान जीत

बस्ताड (स्वीडन)। ओलंपिक की तैयारी में लगे राफेल नडाल ने क्ले कोर्ट पर खेले जा रहे नॉर्डिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के एकल के पहले दौर में स्वीडन के दिग्गज खिलाड़ी ब्योर्न बोर्ग के 21 वर्षीय बेटे लियो बोर्ग को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराया। नडाल ने मैच के बाद अपने 21 वर्षीय प्रतिद्वंद्वी के बारे में कहा, हमारे खेल के इतिहास के सबसे दिग्गज खिलाड़ी में से एक के बेटे के खिलाफ खेलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मुझे लगता है कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके सामने अभी लंबा करियर है और मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं। नडाल ने यहां 2005 में 19 वर्ष की उम्र में खिताब जीता था। उसके बाद वह इस टूर्नामेंट में पहली बार भाग ले रहे हैं। ओलंपिक के दौरान टेनिस के मैच रोला गैरां में क्ले कोर्ट पर खेले जाएंगे और उसकी तैयारी के सिलसिले में ही नडाल इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। फ्रेंच ओपन के पहले दौर में बाहर होने के बाद नडाल ने पहली बार एकल मैच खेला। उनका अगला मुकाबला ब्रिटेन के कैमरन नोरी से होगा।

इंटर मियामी के लिए कम से कम दो मैच में नहीं खेल पाएंगे मेस्सी

फोर्ट लॉडरडेल (अमेरिका)। कोपा अमेरिका फाइनल के दौरान चोटिल होने वाले लियोनेल मेस्सी अपनी मेजर लीग सॉकर टीम इंटर मियामी की तरफ से कम से कम दो मैच में नहीं खेल पाएंगे। इंटर मियामी के कोच गेरार्डो मार्टिनो ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि मेस्सी के दाहिने टखने में चोट लगी है और उनकी फिटनेस का निरंतर आकलन किया जाएगा। इंटर मियामी बुधवार रात टोरंटो एफसी और शनिवार रात शिकागो की मेजबानी करेगा। मेस्सी अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच रविवार को खेले गए मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। उन्हें कोपा अमेरिका फाइनल के इस मैच में 64 मिनट बाद मैदान छोड़ना पड़ा था। अर्जेंटीना ने यह मैच1-0 से जीता था। अर्जेंटीना के इस स्टार खिलाड़ी ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर बताया कि उनकी प्रगति अच्छी है और उम्मीद जताई कि कि वह जल्द वापसी करेंगे।

नागल और ड्रेजेविक की जोड़ी नॉर्डिया ओपन से बाहर

बस्ताड (स्वीडन)।ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल और पोलैंड के उनके जोड़ीदार करोल ड्रेजेविक को यहां नॉर्डिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल में सीधे सेटों में हार का सामना करना पड़ा। नागल और ड्रेजेविक की जोड़ी मंगलवार को 59 मिनट तक चले मुकाबले में एलेक्जेंडर मुलर और लुका वान असचे की फ्रांसीसी जोड़ी से 3-6, 4-6 से हार गई।भारत के 26 वर्षीय खिलाड़ी ने हालांकि एकल वर्ग में अपनी चुनौती बरकरार रखी है।

साल के अंत में जय शाह बनेंगे चेयरमैन या 2025 तक पद पर बने रहेंगे बार्कले!

भाषा। नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के कोलंबो में शुक्रवार से शुरू होने वाले चार दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के दौरान सभी की निगाहें भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह पर होंगी जहां इस बात पर गंभीर चर्चा हो सकती है कि वह न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले से वैश्विक संस्था के अध्यक्ष का पद कब संभालेंगे। शुक्रवार को बोर्ड की बैठक के साथ शुरू होने वाले आईसीसी सम्मेलन में वैश्विक संस्था द्वारा अमेरिका में टी20 विश्व कप मैचों की मेजबानी में दो करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के नुकसान पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि एजीएम (वार्षिक आम बैठक) के नौ सूत्रीय एजेंडे (जिसकी एक प्रति पीटीआई के पास है) में टूर्नामेंट का वित्तीय विवरण शामिल नहीं है, लेकिन बोर्ड द्वारा कार्यक्रम के बाद की रिपोर्ट के रूप में इस पर चर्चा की जाएगी जो एक मानक संचालन प्रक्रिया है।

आईसीसी की सदस्यता, एसोसिएट सदस्यों की बैठक की रिपोर्ट और आईसीसी विकास पुरस्कार प्रस्तुति पर चर्चा के साथ-साथ आईसीसी के नए बाहरी लेखा परीक्षक की नियुक्ति भी एजेंडे में है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदू- चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान नहीं जाना - आईसीसी बोर्ड के आधिकारिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है जब तक कि इसे कोई अन्य काम वर्ग के तहत अध्यक्ष की अनुमति से नहीं लाया जाता। हालांकि चीजों की जानकारी रखने वाले आईसीसी के एक सूत्र ने कहा कि आईसीसी में सभी की मुख्य रूप से इसमें है कि शाह वैश्विक संस्था की बागडोर कब संभालेंगे। आईसीसी सूत्र ने कहा, यह कैसे के बारे में नहीं है, बल्कि कब के बारे में है क्योंकि बीसीसीआई सचिव के रूप में उनके पास अब भी एक साल बचा है जिसके बाद संविधान के अनुसार भारतीय बोर्ड में उनका ब्रेक (कूलिंग ऑफ पीरियड) 2025 में शुरू होगा। हालांकि अगर उन्हें 2025 में पदभार संभालना है तो बार्कले दिसंबर 2024 से दिसंबर 2026 तक दो साल का अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, एक विचारधारा यह है कि क्या होगा यदि आईसीसी की अध्यक्षता का कार्यकाल दो-दो साल के तीन कार्यकाल से बदलकर तीन-तीन साल के दो कार्यकाल हो जाए, तो कुल कार्यकाल छह साल ही रहेगा। माना जा रहा है कि अगर बार्कले का मौजूदा कार्यकाल तीन साल का होता है तो शाह बीसीसीआई सचिव के रूप में छह साल पूरे कर सकते हैं और फिर 2025 में तीन साल के लिए आईसीसी चेयरमैन बन सकते है।

छह देशों को मिलेगा डेवलपमेंट पुरस्कार

नई दिल्ली।अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार 2023 के वैश्विक विजेताओं की घोषणा जिसमें छह उभरते हुए देश मेक्सिको, ओमान, नीदरलैंड, यूएई, नेपाल और स्कॉटलैंड शामिल है। पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान शानदार प्रदर्शन के अलावा महत्वपूर्ण पहल के लिए 21 उभरते हुए देशों में से छह को पुरस्कारों के लिए चुना गया और इनका चयन एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा किया गया। आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार इस साल विजेताओं का चयन अप्रैल में घोषित क्षेत्रीय पुरस्कार विजेताओं की सूची से किया गया जिसे आईसीसी के पूर्ण सदस्य अधिकारियों, पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों और आईसीसी वैश्विक भागीदारों के एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा चुना गया जिसमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी भी शामिल है। आईसीसी डेवलपमेंट (विकास) पुरस्कार 2002 में शुरू किए गए थे जो एसोसिएट सदस्य देशों में खेल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किए गए काम के लिए दिए जाते है।

सूर्यकुमार टी20 रैंकिंग में नंबर दो पर डटे

भाषा। दुबई

आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव बुधवार को जारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं जबकि युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायवाल छठे स्थान पर पहुंच गए। रुतुराज गायकवाड़ टी20 बल्लेबाजों की सूची में एक स्थान के नुकसान से आठवें पायदान पर हैं।जिंबाब्वे के खिलाफ टी20 श्रृंखला में भारत की 4-1 की जीत के बाद रैंकिंग को अपडेट किया गया है।श्रृंखला में 141 रन बनाने वाले जायसवाल को चार स्थान का फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर चल रहे हैं।सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में जिंबाब्वे दौरे पर भारतीय टीम की अगुआई करने वाले शुभमन गिल पांच पारियों में 170 रन बनाकर श्रृंखला के शीर्ष स्कोरर रहे। वह 36 स्थान की लंबी छलांग के साथ 37वें स्थान पर हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की रैंकिंग में कोई भारतीय शीर्ष 10 में नहीं है। जिंबाब्वे के खिलाफ श्रृंखला से अक्षर पटेल को ब्रेक दिया गया था और वह चार स्थान के नुकसान से 13वें स्थान पर खिसक गए हैं। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और वाशिंगटन सुंदर को रैंकिंग में फायदा हुआ है। तीन मैच में आठ विकेट चटकाने वाले मुकेश 36 स्थान के फायदे से 46वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पांच मैच में आठ विकेट हासिल करने वाले सुंदर 21 स्थान की छलांग के साथ 73वें स्थान पर हैं।

यशस्वी जायसवाल को छठवीं पोजीशन

इंग्लैंड के आदिल राशिद टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के एनरिच नोर्किया और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा का नंबर उनके बाद आता है।टी20 अंतरराष्ट्रीय ऑलराउंडर की सूची में भारत के हार्दिक पंड्या चार स्थान के नुकसान से छठे स्थान पर खिसक गए जबकि अक्षर एक स्थान के नुकसान से 13वें स्थान पर हैं। सुंदर और शिवम दुबे आठ और 35 स्थान के फायदे से क्रमश: 41वें और 43वें स्थान पर हैं।श्रीलंका के हसरंगा ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष पर चल रहे हैं।

नागल पेरूगिया चैलेंजर के फाइनल में हारे: पेरूगिया (इटली), भारत के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल रविवार को यहां पेरूगिया चैलेंजर के एकतरफा फाइनल में इटली के लुसियानो डार्डेरी से हार गए। नागल को इटली के प्रतिद्वंद्वी से एक घंटे से भी कम समय में।-6 2-6 से हार मिली। इस तरह यह 26 वर्षीय भारतीय इस साल अपना तीसरा खिताब जीतने से चूक गया। नागल ने स्पेन के बर्नबे जापाटा मिरालेस पर 7-6 (7-2) 1-6 6-2 की संघर्षपूर्ण जीत से फाइनल में प्रवेश किया था।

उषा ने अंतिम के कोचों में सूची में जगह न देने के लिए डब्ल्यूएफआई तदर्थ पैनल को फटकार लगाई

नई दिल्ली। (भाषा) भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने बुधवार को निलंबित भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का प्रबंधन करने वाले तदर्थ पैनल की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों के आयोजकों को भेजी गई लंबी सूची में पहलवान अंतिम पंघाल के कोचों के नाम नहीं दिए। आईओए की प्रतिक्रिया खेलों के लिए अंतिम के पसंदीदा कोचों को वीजा मंजूरी मिलने में देरी के मद्देनजर आई है। हिसार में प्रशिक्षण लेने वाली 19 साल की पंघाल पेरिस खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय पहलवान थीं।

कपिल की ओलंपिक के लिए जाने वाले खिलाड़ियों को सलाह, स्वच्छंद होकर खेलें

भाषा। नई दिल्ली

भारत की 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान और भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर (पीजीटीआई) के अध्यक्ष कपिल देव ने बुधवार को ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को 26 जुलाई से शुरू हो रहे खेलों के महाकुंभ में स्वच्छंद होकर खेलने की सलाह दी और उम्मीद जताई कि देश पेरिस में दोहरे अंक में पदक जीतेगा। पेरिस में भारत का प्रतिनिधित्व 117 सदस्यीय दल करेगा और देश को तोक्यो में जीते सात पदकों की संख्या को बेहतर करने की उम्मीद है। ट्रीनिटी गोल्फ चैंपियन्स लीग (टीजीसीएल) के दूसरे सत्र की घोषणा के मौके पर कपिल ने कहा, मैं किसी खिलाड़ी के लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं उन्हें शुभकामनाएं दे सकता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम इस साल और अधिक पदक जीतेंगे और यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, सभी को (भारतीय खिलाड़ियों) मेरी सलाह होगी कि वे जाएं और खुद को जाहिर करें, स्वच्छंद होकर खेलें। हम क्यों उम्मीद नहीं करेंगे कि हम दोहरे अंक में पदक जीतेंगे। कपिल ने हालांकि भारतीय क्रिकेट और नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर पर टिप्पणी करने से परहेज किया।

उन्होंने कहा, अगर गौतम गंभीर वह पद (भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पद) संभाल रहे हैं तो मैं उन्हें और टीम को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मैं भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं।

गोल्फ के शौकीन कपिल ने उम्मीद जताई कि देश में यह खेल आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा, जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस ऊंचाई पर पहुंचेगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन गोल्फ भी क्रिकेट की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। टीजीसीएल के दूसरे सत्र का आयोजन बेंगलुरु के प्रेस्टीज गोल्फशर क्लब में दो से सात सितंबर तक किया जाएगा। टूर्नामेंट में इस बार श्रीलंका की एक टीम सहित कुल आठ टीम खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगी जिनमें नाम वेव राइडर्स, मुंबई वारियर्स, चंडीगढ़ टाइटंस, चेन्नई हसलर्स, दक्षिण रेंजर्स, लहरी लायंस, गोल्फिज्म और कोलंबो लायंस हैं।

टूर्नामेंट के पहले सत्र में चार टीमों ने हिस्सा लिया था।

सीएमवाईके प्रिंटेक के लिए तथा उसी की ओर से मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा टिन टिन प्रिंटेक प्रा.लि. सी-33 अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज लखनऊ से मुद्रित एवं चौथी मंजिल, सहारा शापिंग सेंटर, फैजाबाद रोड, लखनऊ (फोन: 0522-4036600) से प्रकाशित। प्रधान सम्पादक: शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: विजय प्रकाश सिंह। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।